ISSN-0971-8397

विशेषांक

आज़ादी का अमृत महोत्सव

योजना

सितम्बर 2022 | विकास को समर्पित मासिक | ₹ 30

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख

प्रमुख आलेख

जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ बनता माहौल

डॉ.

फोकस

निवेश को प्रोत्साहन

रोहित कंसल, दीपंकर सेनगुप्त

विशेष आलेख

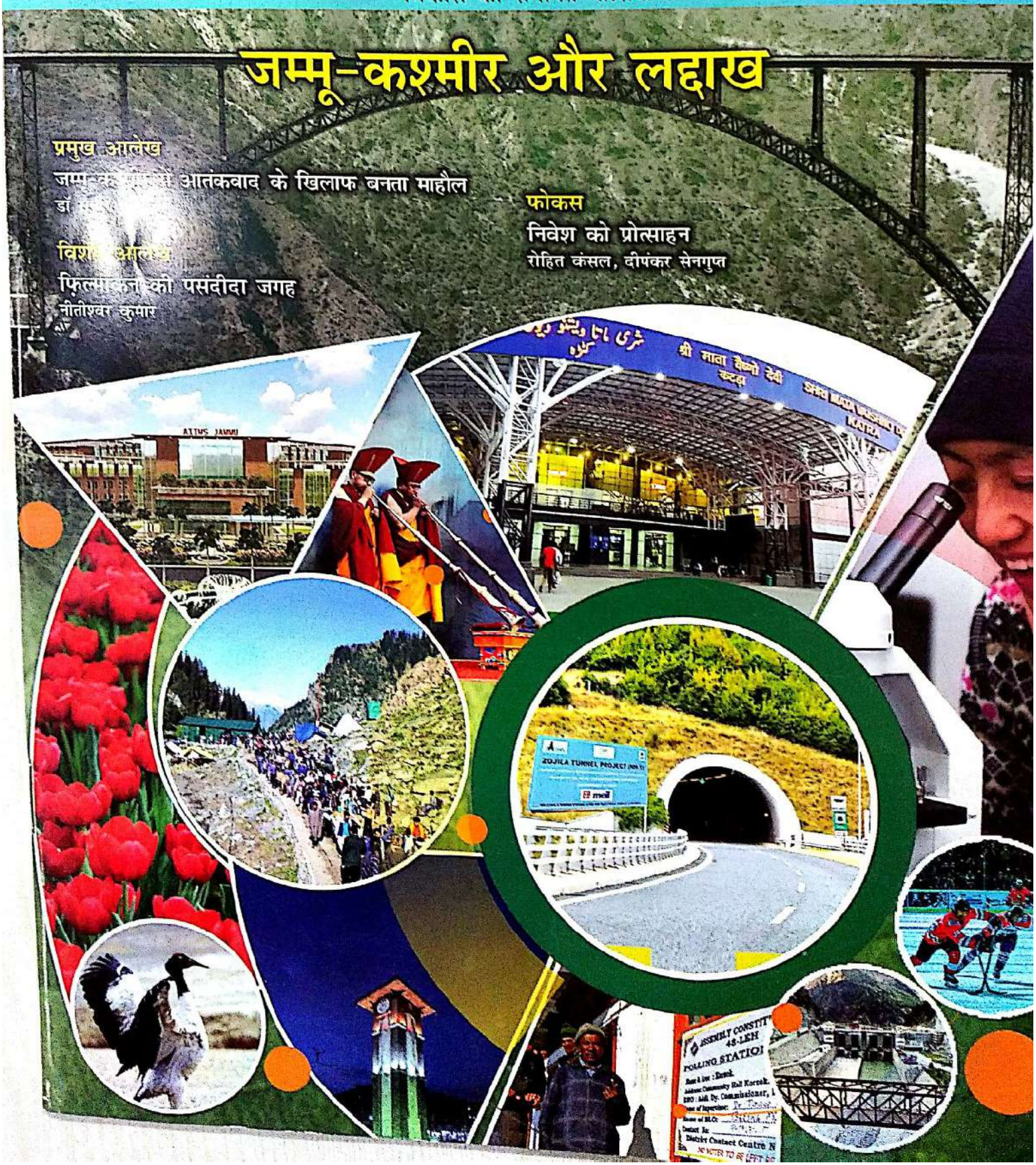

फिल्मांकन की पसंदीदा जगह

नीतीश्वर कुमार

आपकी राय

yojanahindi-dpd@gov.in

जनजातीय समुदाय का जीवन

'योजना' पत्रिका का जुलाई 2022 अंक भारत के जनजातीय समुदाय पर केन्द्रित था। प्रस्तुत अंक में भारत के विभिन्न राज्यों में रहने वाली जनजातियों के बारे में जानकारी दी गई थी। संविधान में जनजातियों की सुरक्षा एवं कल्याण से सम्बन्धित प्रावधानों की चर्चा की गई थी तो जनजातियों के कल्याण से सम्बन्धित विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी भी थी।

देश के विभिन्न भागों में यथा गुजरात, पूर्वोत्तर, मध्य भारत की विभिन्न जनजातियों की जीवनशैली एवं उनकी परम्पराओं की भी जानकारी दी गई थी। देशज संस्कृति के लेख में अलग-अलग जनजातीय समुदाय की विभिन्न संस्कृतियों की चर्चा थी। गोंड जनजाति के जीवन पर विशेष प्रस्तुति थी। यह मध्य भारत की प्रमुख जनजाति है।

खेलों में जनजातीय समुदाय के खिलाड़ियों की उपलब्धि सराहनीय है। इस समुदाय के लोग गरीब व अल्पसुविधा होते हुए भी खेलों में बेहतर प्रदर्शन करते हैं। छत्तीसगढ़ के स्वाधीनता नायकों के बारे में जानकर अच्छा लगा।

आगामी अंक का इंतज़ार रहेगा।

– नितेश कुमार
गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश

समाज का पथप्रदर्शक

विकास को समर्पित 'योजना' पत्रिका का अगस्त 2022 का अंक बेहद रोचक एवं ज्ञानपूर्ण रहा।

साहित्य न केवल किसी समाज के इतिहास की जानकारी देता है बल्कि आने वाले समाज का पथ प्रदर्शक भी होता है। भारतीय साहित्य हर युग, हर काल में अपनी सजीवता और समाज के हित की भावना प्रदर्शित करने वाला रहा है। एक ओर जहां वैदिक साहित्य से हमें अपनी सभ्यता एवं संस्कृति का ज्ञान होता है वहीं आज के आधुनिक साहित्य से हमें जीवन में बदलाव, नई चीजों को समझने और अच्छे बुरे की समझ को बढ़ाने में साहित्य की अद्वितीय भूमिका होती है।

मध्यकाल में जब एक भाई द्वारा दूसरे भाई की हत्या तथा साम्राज्य के लालच का अंधकारमय युग चल रहा था ठीक उसी समय तुलसीदास ने 'रामचरितमानस' लिखकर न सिर्फ एक राज्य कैसा होना चाहिए की मर्यादा स्थापित की, साथ ही उनका साहित्य व्यक्तिगत हित 'जेहि विधि होहि नाथ हित मोरा' से आगे बढ़ता हुआ।

'जेहि विधि होय सुखी पुर लोगा। करहिं कृपानिधि सोई संजोगा' के रूप में पूरे समाज का हित धारण करता हुआ आगे बढ़ा।

उसी काल में कबीर जात-पात, ऊँच-नीच को खारिज करते हुए प्राणी मात्र के प्रेम पर बल दे रहे थे।

उसी दौर में दादू, नानक, मीरा आदि के साहित्य उल्लेखनीय है। आधुनिक काल में प्रेमचंद का साहित्य गरीब, वंचित शोषित वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। पूस की रात, सदगति और कफन जैसी कहानियों में चरम यथार्थ है तथा गोदान में उस समय के संपूर्ण भारत के चित्र को प्रदर्शित करने की अभूतपूर्व क्षमता है। यथार्थ की जो परम्परा प्रेमचंद जी ने शुरू की थी वह आज अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्राप्त गीतांजलि श्री से आगे बढ़ते हुए सतत रूप से जारी है।

भारत में अंग्रेजी साम्राज्य द्वारा शोषण को विभिन्न साहित्यकारों ने उजागर किया है। इसी क्रम में भारतेंदु जी अपने नाटक 'भारत दुर्दशा' में लिखते हुए, "पै धन विदेश चलि जात इहै अति ख्वारी" धन बहिर्गमन की निंदा करते हैं।

अत: कहा जा सकता है साहित्य हर युग हर काल में उपयोगी रहा है।

आज के सोशल मीडिया युग में साहित्य का सार्वभौमीकरण हो गया है जिससे सुगमता पूर्वक साहित्य की उपलब्धता एवं लेखन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

– माधवेंद्र मिश्रा,
साईं सेल्फ स्टडी जोन,
नेहरू नगर, रायबरेली, उत्तर प्रदेश

शब्दों का महत्व

'योजना' पत्रिका का अगस्त 2022 अंक काफी जागरूकतावर्धक और ज्ञानवर्धक रहा। देश ने जहाँ 75वीं वर्षगांठ का अमृत महोत्सव मनाया तो ऐसे में उन भारत बलिदानियों के त्याग, निष्ठा, समर्पण और देशभक्ति के जज़्बे

आपकी राय का पृष्ठ पाठकों के विचार और उनकी टिप्पणियाँ 'योजना' टीम से साझा करने के लिए ही है। अपने पत्र हमें ईमेल करें–

yojanahindi-dpd@gov.in

पर या लिखें - वरिष्ठ संपादक, 648, सूचना भवन, सीजीओ परिसर, लोदी रोड, नयी दिल्ली-110 003

Scanned with OKEN Scanner

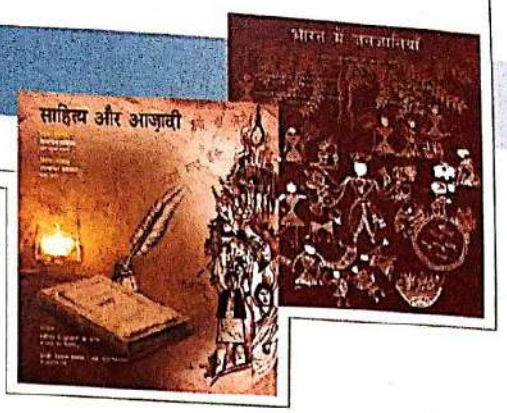

के प्रति सम्मान प्रकट करना कर्तव्य बन जाता है। इस अंक का संपादकीय बड़ा रोचक और संदेशवाहक रहा। 'शब्दों की ताक़त' का अंदाजा लगाते हुए यह महसूस किया जा सकता है कि स्वतंत्रता संग्राम में इनकी क्या भूमिका रही होगी। अंग्रेज शासन के अत्याचार के खिलाफ विरोध करने हेतु जो आवाज़ें उठीं वह या तो गीतों में, कविता या नारों में गढ़ी गईं। क्रांतिकारियों ने अत्याचार के दर्द को मार्मिक ढंग से अपनी रचनाओं में प्रस्तुत किया। शब्दों की यही ताकत आज भी लोगों की ज़ुबां पर गुंजायमान होती है। उन शहीदों को सादर नमन!

– जीवितेश कुमार
मुरादनगर, उत्तर प्रदेश

आगे बढ़ते जाना

योजना अगस्त 2022 अंक साहित्य और आज़ादी विशेषांक को पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। चमन लाल जी द्वारा लिखित लेख 'प्रतिबंधित प्रकाशन' बहुत ही सराहनीय है। जिसमें विरोध होने के बाबजूद स्वतंत्र विचारों के विकास के बारे में विस्तार से समझाया गया। वर्तमान में, योजना पत्रिका न केवल प्रतियोगी छात्रों, बल्कि समाज में अन्य लोगों के बौद्धिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। योजना पत्रिका समाज के लिए कुछ इस तरह कार्य कर रही है।

"पथ का अंतिम लक्ष्य नही है सिंहासन
चढ़ते जाना सब समाज को लिए साथ में
आगे है बढ़ते जाना।" संपादक मंडल, और समस्त लेखकों को बहुत-बहुत आभार।।

– सौरभ कुमार
सहायक प्राध्यापक सीएसजेएम
विश्वविद्यालय कानपुर, स्टेशन बाजार
अछल्दा (औरैया), उत्तर प्रदेश

आज़ादी का साहित्य

योजना पत्रिका के अगस्त 2022 के अंक को आज़ादी और साहित्य के विशेषांक के रूप में प्रस्तुत किया है जिसमें आज़ादी के साथ ही विभाजन के समय के साहित्य कार्य को सम्मिलित किया है जिसमें भारत के विभिन्न क्षेत्रों में हुए साहित्यिक कार्यों को समावेशित किया गया है। योजना पत्रिका का हमेशा से ही यह प्रयास रहा है जिसके अंतर्गत किसी विशेष विषय की लगभग सभी मुख्य पहलुओं पर चर्चा करते हुए गागर में सागर जैसी प्रस्तुति रहती है।

इस अंक में भी इस विषय की अधिकतर बातों को समावेशित किया है जिसमें चाहे हिंदी हो या बांग्ला, गुजराती, उर्दू हो चाहे आदिवासियों का योगदान हो। सभी पहलुओं का एक ही जगह पर मिलना संभवत: कम ही होता है। ऐसे में पत्रिका परिवार को इस खूबसूरत प्रस्तुति के लिए बहुत धन्यवाद और आभार!

– मनीष रमन
अलवर, राजस्थान

आज़ादी का अमृत महोत्सव

योजना का अगस्त अंक 'साहित्य और आज़ादी' बेहद आकर्षक और रोचक है। नि:संदेह शब्दों की ताक़त किसी अस्त्र से अधिक है। 'आज़ादी के अमृत महोत्सव' वर्ष में प्रस्तुत अंक में शब्दों के संसार और गरिमा से परिचय कराया गया है।

नि:संदेह शब्द-साहित्य के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से जनमानव को आंदोलित करने के लिए संदेश देने का काम किया जिसने स्वतंत्रता आंदोलन में प्राणतत्व फूँके।

शब्दों का रचनात्मक संसार गीत-संगीत, सिनेमा, साहित्य के जरिये आज भी नई पीढ़ी का भूतकाल के गौरव और भविष्य की संभावनाओं से परिचय करा रहा है तो पुरानी पीढ़ी को सुखद स्मृतियों का भान कराता है।

– प्रांजलि
नई दिल्ली

जनजाति और परम्पराएँ

'योजना' का जुलाई 2022 के अंक परम्पराएँ और सामाजिक आर्थिक परिप्रेक्ष्य लेख अत्यंत सूचनाप्रद लगा। भारतीय समाज में विभिन्न जनजातियों का पाया जाना हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। आधुनिक युग की खोज उपभोगवाद पर आधारित है। किन्तु इतिहास के संदर्भ में आदिम जनजातीय का अध्ययन करना भी आधुनिक समाज की आवश्यकता है। देश के सम्पूर्ण विकास में इन पर भी ध्यान देना आवश्यक है।

पराधीनता के समय में जब अँग्रेज़ों ने उनके निवास स्थलों पर अतिक्रमण किया तो सीधे-सादे आदिवासियों ने अँग्रेज़ी सत्ता के विरुद्ध अपनी परम्परागत हथियारों से लड़ाई लड़ी। सदियों से पिछड़ी ये आदिम जनजाति आज आधुनिकता की दौड़ से अत्यन्त दूर है। इन पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

यह समुदाय परम्पराओं और अपनी संस्कृति को जीवंत रखने में अत्यंत प्रयासरत है।

अत: देश के सम्पूर्ण विकास में सभी समुदाय का सहयोग आवश्यक है।

– नीलम कुमारी
जहांगीरपुरी, नई दिल्ली

Scanned with OKEN Scanner

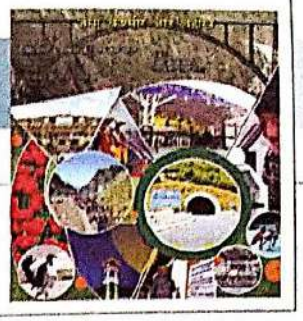

ऐतिहासिक बदलाव

केंद्रीय गृह मंत्री ने 5 अगस्त 2019 को संसद में जम्मू-कश्मीर से जुड़े दो बिल और दो प्रस्ताव पेश किए। यह एक ऐतिहासिक कदम था, जिसका मकसद जम्मू-कश्मीर में लोकतंत्र को मज़बूत करना और इसे देश के अन्य भाग की तरह ही मुख्यधारा में लाना था। इससे देश के अन्य क्षेत्रों की तरह ही केंद्र की विकास योजनाओं का लाभ यहाँ भी मिल सकेगा। यह जम्मू-कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र के दीर्घकालिक विकास की दिशा में बड़ा कदम था जिससे सामाजिक-आर्थिक आधारभूत संरचना को मज़बूत किया जा सकेगा और यहां के स्थानीय लोगों को ज़्यादा आर्थिक अवसर मिल सकेंगे।

ज़ाहिर तौर पर इस कदम को बुनियादी बदलाव के माध्यम के तौर पर देखा गया। जैसा कि प्रधानमंत्री अक्सर कहते हैं, इस कदम का उद्देश्य 'यहां के लोगों को अपना बनाकर उन्हें गले लगाना' था। ज़मीनी स्तर पर कार्रवाई में भी यह बात देखने को मिली और सरकार ने तय लक्ष्यों और समयबद्ध परिणामों के हिसाब से काम करना शुरू किया। जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद से निपटने और फिर से शांति स्थापित करने के लिए सरकार एक साथ कई स्तरों पर रणनीति बनाकर काम कर रही है, मसलन सीमा-पार आतंकवाद पर लगाम कसना, घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम करना, आतंकवादियों से सहानुभूति रखने वालों पर कार्रवाई, मानवीय आधार पर पहल करना और भारत-विरोधी प्रोपगेंडा यानी दुष्प्रचार से सक्रियतापूर्वक निपटना।

अगर हम स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करें, तो जम्मू-कश्मीर में 2020 में आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत की शुरुआत की गई। कोविड 19 महामारी के दौरान यहां के स्वास्थ्य कर्मियों की सक्रियता तारीफ के काबिल थी। टीकाकरण अभियान को सफल बनाने के लिए यहां के स्वास्थ्यकर्मियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली। इन कर्मियों ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के दूर-दराज़ के दुर्गम इलाकों में भी इस अभियान को प्रभावी बनाने में अहम भूमिका निभाई। जम्मू-कश्मीर में स्वास्थ्य संबंधी आधारभूत संरचना को बढ़ाना देने के लिए भी हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। इसके तहत, जम्मू और अवंतीपोरा में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स की स्थापना के लिए काम चल रहा है। साथ ही, सात और नए मेडिकल कॉलेज भी खोले जाने हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान-आईआईटी और एम्स जैसे उच्च शिक्षण संस्थान युवाओं के लिए विश्वस्तरीय अवसर प्रदान करेंगे। साथ ही, इस क्षेत्र में कौशल विकास से जुड़ी योजनाओं का लाभ भी युवाओं को मिल रहा है। इस तरह, वे अपने घर के पास रहकर ही रोज़गार के लायक बन सकेंगे।

बेहतर सड़कों, रेल, रोपवे और सुरंगों के निर्माण से तीनों (जम्मू, कश्मीर और लद्दाख) अलग-अलग क्षेत्रों के बीच दूरी कम हो रही है और लोग एक-दूसरे के करीब आ रहे हैं। साथ ही, इस क्षेत्र में पर्यटकों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। आवागमन की सुविधा बेहतर होने से निवेश को भी बढ़ावा मिला है। आधारभूत संरचना पर विशेष ज़ोर, नई उद्योग नीति से जुड़ी पहल और संवैधानिक अनिश्चितता खत्म होने से उद्योग, बागवानी और हस्तकला जैसे क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर निवेश हो रहा है, जिससे रोज़गार के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। इसका फायदा युवा उद्यमियों को मिल रहा है।

यह क्षेत्र बेहद खूबसूरत है और इसकी संस्कृति भी काफी समृद्ध रही है। चाहे डल झील में शिकारे का दृश्य हो, तवी नदी के किनारे मौजूद बाहु किला या ज़ंस्कार और सिंधु नदी का संगम स्थल, ये सभी मंत्रमुग्ध करने वाले नज़ारे हैं। इस क्षेत्र और यहां के लोगों ने कई तरह के विचारों, संस्कृतियों और धार्मिक पंथों को अपनाया है। भारत की संस्कृति, इतिहास, साहित्य और दर्शन में इस क्षेत्र के लोगों का अहम योगदान है। विभिन्न काल खंडों में इस सरज़मीं पर अलग-अलग तरह की आध्यात्मिकता का प्रसार हुआ, लिहाज़ा यहां की कला, सौंदर्यशास्त्र और रहन-सहन के तौर-तरीकों में इन आस्थाओं का समावेश देखने को मिलता है। योजना के इस अंक में यहां हुए ऐतिहासिक सकारात्मक बदलाव के मद्देनज़र यहां की मिट्टी, लोगों और उनकी संस्कृति के कुछ पहलुओं को प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। इस क्षेत्र की योगिनी और कवियित्री लाल देद ने परिवर्तनशील जीवन में मौजूद कुछ खास अपरिवर्तनशीलता यानी निरंतरता को इस तरह से बयां किया है-

अतीत में हमारा अस्तित्व था;
भविष्य में भी हमारा अस्तित्व रहेगा;
हम हर युग में रहे हैं।
सूरज हमेशा से उगता और डूबता रहा है;
शिव हमेशा से सृजन और विध्वंस और फिर से सृजन करते रहे हैं। ■

Scanned with OKEN Scanner

जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ बनता माहौल

डॉ समीर पाटिल

तिरंगे में रोशन होती क्लॉक टावर, लाल चौक, श्रीनगर

भारत सरकार द्वारा तत्कालीन जम्मू-कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा समाप्त करके दो नए केंद्रशासित प्रदेश 'जम्मू-कश्मीर' और 'लद्दाख' की स्थापना किए जाने के तीन वर्ष 5 अगस्त, 2022 को पूरे हो गए।[1] इस क्षेत्र की सामरिक स्थिति को देखते हुए सुरक्षा की दृष्टि से संविधान में लाया गया यह परिवर्तन अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि वहां प्रशासनिक व्यवस्था और सुरक्षा के प्रति अब नया दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है। केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के प्रशासन तंत्र और सुरक्षा तंत्र ने अनेक नई पहलें शुरू की हैं जिससे वहां के लोगों में उज्ज्वल भविष्य की आशा का संचार हुआ है।

केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर भारत के सबसे सुंदर और मनोरम क्षेत्रों में से एक है परंतु विगत तीन दशकों से यह क्षेत्र सीमापार से चलाए जा रहे आतंकवाद, विघटनकारियों की हिंसक गतिविधियों और सशस्त्र उग्रवाद की समस्या से जूझ रहा है। 1990 के दशक के शुरू के वर्षों में आतंकवादी हिंसा का काफी ज़ोर रहा लेकिन अब आंतरिक और बाहरी ताक़तों की शह मिलने के कारण इसने और उग्र रूप ले लिया है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की प्रमुख भूमिका, कश्मीर में अलगाववाद की राजनीति के प्रसार, सभी इस्लामी आतंकी गुटों के प्रभाव और सोशल मीडिया के प्रसार जैसे कारकों ने इस समस्या को बेहद जटिल बना दिया है। इसी कारण जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद का मौजूद स्वरूप सुरक्षा व्यवस्था के लिए 1989 के मुकाबले कहीं अधिक जटिल चुनौती बन चुका है क्योंकि उस दौर में तो कुछेक कश्मीरी युवा चोरी छिपे नियंत्रण रेखा पार करके पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में जाकर आतंकवाद का

लेखक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन थिंक टैंक के सीनियर फेलो हैं। उन्होंने पूर्व में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में भी कार्य किया है। ईमेल: sameer.patil@orfonline.org

Scanned with OKEN Scanner

प्रशिक्षण लेने के बाद आतंकी गुटों या संगठनों में शामिल हो जाते थे।

हाल में धार्मिक अल्पसंख्यकों, विस्थापितों, सुरक्षा बलों के कर्मचारियों और अधिकारियों तथा आम नागरिकों को निशाना बनाकर उनकी हत्या करने की वारदातों से जम्मू-कश्मीर की सुरक्षा की स्थिति खतरनाक हो गई है। इन घटनाओं से तो लग रहा है कि इस क्षेत्र में हिंसा और अस्थिरता का बोलबाला होता जा रहा है जबकि वास्तविकता एकदम अलग है।

आज भारतीय सुरक्षा तंत्र ने जम्मू-कश्मीर की स्थिति पूरी तरह अपने नियंत्रण में ले ली है। प्रभावी और कड़ी कार्रवाई करके आतंकवादियों पर दबाव बना रखा है और उन्हें उनके समर्थकों से मिलने वाली मदद भी उन तक पहुंचने नहीं दी जा रही है। इसके लिए आतंकवादियों से सहानुभूति रखने वालों पर अंकुश लगाकर तथा भारत विरोधी दुष्प्रचार रोकने के लिए समय रहते ही कार्रवाई करके इस उद्देश्य को पाने में सफलता प्राप्त की गई है। आतंकवाद से निपटने के दृष्टिकोण से देखें तो कई नई चुनौतियां उभर रही हैं पर हमारे सुरक्षा बलों को उनसे कारगर ढंग से निपटने का पूरा विश्वास है।

आज भारतीय सुरक्षा तंत्र ने जम्मू-कश्मीर की स्थिति पूरी तरह अपने नियंत्रण में ले ली है। प्रभावी और कड़ी कार्रवाई करके आतंकवादियों पर दबाव बना रखा है और उन्हें उनके समर्थकों से मिलने वाली मदद भी उन तक पहुंचने नहीं दी जा रही है। इसके लिए आतंकवादियों से सहानुभूति रखने वालों पर अंकुश लगाकर तथा भारत विरोधी दुष्प्रचार रोकने के लिए समय रहते ही कार्रवाई करके इस उद्देश्य को पाने में सफलता प्राप्त की गई है।

इस क्षेत्र में आतंकवाद के बारे में मौजूदा दृष्टिकोण

कश्मीर घाटी में सुरक्षा की स्थिति में आए सुधार का एक अहम संकेतक है वहां सक्रिय आतंकवादियों की संख्या घटकर बेहद कम रह जाना जबकि 1990 के दशक के शुरू के दौर में इन आतंकियों की संख्या हज़ारों में थी। अब हालात बदल गए हैं। इस वक्त कश्मीर में आतंकवादियों की संख्या क़रीब 163 रह गई है जो इन दशकों में सबसे कम है (देखें तालिका-1)।

तालिका 1 : कश्मीर घाटी में आतंकवादियों की संख्या

क्षेत्र	पाकिस्तानी आतंकवादी	स्थानीय आतंकवादी	कुल
उत्तर कश्मीर	60	17	77
दक्षिण कश्मीर	18	68	86
कुल	78	85	163

स्रोत : भारतीय सेना

ये आतंकवादी मुख्य रूप से तीन आतंकी गुटों-लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) और हिज़बुल मुजाहिदीन (एचएम) के हैं। कुछ आतंकवादी पैन-इस्लामिक गुटों के स्थानीय ग्रुपों से जुड़े हैं जिनमें अल कायदा का अंसार-उल-हिंद और इस्लामिक स्टेट जेएंडके शामिल हैं। पर इनकी संख्या बहुत ही कम है। पाकिस्तानी आतंकवादियों पर कड़ा अंकुश लग जाने के फलस्वरूप अब वे उन स्थानीय आतंकवादियों को हिदायतें देने और भड़काने की ही भूमिका अदा कर पा रहे हैं जिन्होंने इस क्षेत्र में आतंकवाद की बागडोर खुद संभाल रखी है।

आतंकवाद का सबसे ज़्यादा असर दक्षिण कश्मीर में है जहां 86 आतंकवादी सक्रिय हैं। खासकर लश्कर-ए-तैयबा और हिज़बुल मुजाहिदीन की इस क्षेत्र में गहरी पैठ है और इनके नेटवर्क और संगठन भी बेहतर हैं; इसीलिए उत्तर कश्मीर नियंत्रण रेखा के उस पार से पाकिस्तानी आतंकियों की घुसपैठ का जरिया बना हुआ है और अब वहां स्थिति अपेक्षाकृत शांत है।

सीमापार से आतंकवादियों की घुसपैठ की रोकथाम

पाकिस्तान-स्थित आतंकवादी गुट उत्तरी कश्मीर के पहाड़ी इलाकों के रास्ते कश्मीर घाटी में घुस जाते हैं। पाकिस्तान का सुरक्षा तंत्र सेना के वाहनों से आतंकवादियों को ठीक नियंत्रण रेखा तक पहुंचाता है और सैनिक घुसपैठ के रास्ते की निगरानी करते रहते हैं तथा उन्हें घुसपैठ में मदद देने के लिए उसके सैनिक कवरिंग फायर भी करते हैं और आतंकियों को आधुनिकतम संचार उपकरण उपलब्ध कराए जाते हैं। पीर पंजाल रेंज (जम्मू-सांबा-कठुआ के मैदानों और रजौरी पुंछ के पर्वतीय इलाकों) के दक्षिण से भी आतंकवादी घुसपैठ करते हैं। कभी-कभी ये आतंकी सुरंगों के रास्ते घुसपैठ करते हैं जैसी कि 2012 में सांबा ज़िले में 400 मीटर लंबी सुरंग का पता चला था।[2]

इस घुसपैठ को रोकने के उद्देश्य से सुरक्षा बलों ने विगत पंद्रह वर्षों में अत्यंत प्रभावी त्रि-स्तरीय घुसपैठ-रोकथाम ग्रिड तैयार किया है। इसमें पहले टीयर या स्तर पर नियंत्रण रेखा पर भारतीय सेना सतर्क रहती है और दूसरे टीयर या स्तर पर केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल-सीआरपीएफ जैसे अर्धसैनिक बल तैनात रहते हैं और तीसरे स्तर पर जम्मू-कश्मीर पुलिस जिम्मा संभालती है। इसके साथ ही सुरक्षा बलों ने आतंकवाद रोधक बाधा प्रणाली एआईडीएस के अंतर्गत बाड़ लगाने के साथ-साथ ड्रोन निगरानी व्यवस्था और रात में देखभाल के उपकरण तथा हाथ में रखने वाले थर्मल इमेजिंग उपकरण तैनात किए हैं।[3]

इन उपायों से घुसपैठ की कार्रवाइयां बहुत कम हो गई हैं जैसा कि तालिका-2 में दर्शाया भी गया है, खासकर घुसपैठ के कामयाब

तालिका 2 : जम्मू-कश्मीर में सीमापार से घुसपैठ

वर्ष	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022*
घुसपैठ की कोशिशें	222	229	183	92	349	323	339	171	62	38	5
सफल घुसपैठ	121	97	65	33	112	120	143	130	36	36	3

स्रोत : गृह मंत्रालय और भारतीय सेना
(जनवरी से जून 2022 की अवधि के आंकड़े)

Scanned with OKEN Scanner

होने पर लगाम कसी गई है। उदाहरण के तौर पर 2020 और 2021 में घुसपैठ की कोशिशों की संख्या घटकर दो अंकों में सिमट गई और 2020 में सिर्फ़ 62 और 2021 में 58 कोशिशें हुई तथा दोनों वर्षों में कुल मिलाकर 72 आतंकी घुसपैठ करने में कामयाब हो सके। 2022 में जून तक घुसपैठ की महज 5 कोशिशें की गईं और सिर्फ़ तीन आतंकी ही घुसपैठ करने में कामयाब हुए। बाद में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में इन आतंकवादियों को भी मार गिराया।

आतंकवादी गुटों और उनके तंत्र (इकोसिस्टम) पर प्रहार

इस बीच सुरक्षा बलों ने घुसपैठ रोकने के अनेक अभियान चलाकर भीतरी इलाकों में आतंकवादियों पर दबाव बढ़ा रखा है। इन उपायों से आतंकवादियों के सरगना और कमांडरों को मारकर और उनकी साजिशों को नाकाम करके सुरक्षाबलों ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। इस प्रकार देखा जाए तो फरवरी, 2019 में पुलवामा के लेथपुरा में सीआरपीएफ के काफ़िले पर आतंकवादियों के आत्मघाती हमले को छोड़कर आतंकवादियों की कार्रवाइयों पर खासा अंकुश लगा है और वे कभी-कभार ही निशाना बनाकर निर्दोष लोगों की हत्या को अंजाम दे पाते हैं जिससे उनमें आई हताशा का पता चलता है और कश्मीर के बदलते सुरक्षा परिवेश में वे सिर्फ़ अपना वजूद बनाए रखने के लिए हिंसक वारदातें करते हैं। सेना के अधिकारियों के अनुसार लगातार आतंकवाद विरोधी अभियान के दबाव से आतंकवादी गुट घुटनों के बल होकर आपस में एकजुट हो रहे हैं और यह भी पाकिस्तानी खुफ़िया एजेंसी आईएसआई के कहने पर हो रहा है।

> इस घुसपैठ को रोकने के उद्देश्य से सुरक्षा बलों ने विगत पंद्रह वर्षों में अत्यंत प्रभावी त्रि-स्तरीय घुसपैठ-रोकथाम ग्रिड तैयार किया है। इसमें पहले टीयर या स्तर पर नियंत्रण रेखा पर भारतीय सेना सतर्क रहती है और दूसरे टीयर या स्तर पर केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल-सीआरपीएफ जैसे अर्धसैनिक बल तैनात रहते हैं और तीसरे स्तर पर जम्मू-कश्मीर पुलिस जिम्मा संभालती है। इसके साथ ही सुरक्षा बलों ने आतंकवाद रोधक बाधा प्रणाली एआईडीएस के अंतर्गत बाड़ लगाने के साथ-साथ ड्रोन निगरानी व्यवस्था और रात में देखभाल के उपकरण तथा हाथ में रखने वाले थर्मल इमेजिंग उपकरण तैनात किए हैं।

इस सुरक्षा कार्रवाई का एक अहम हिस्सा है आतंकवादियों का समर्थन करने वाली व्यवस्था में शामिल विघटनकारी तत्वों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करना। इसमें जमीन पर खुलेआम काम करने वाले लोगों का नेटवर्क तो शामिल था ही, साथ में जमात-ए-इस्लामी का समूचा काडर भी इससे मिल चुका था। हिज़्बुल मुजाहिदीन से जुड़ा यह धार्मिक संगठन काफी लंबे अर्से से खुलकर विघटनकारी गतिविधियां चलाने में लगा था। फरवरी, 2019 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जमात-ए-इस्लामी को 'गैरकानूनी' संस्था घोषित करके उस पर प्रतिबंध लगा दिया।[4] इसी के साथ सरकार ने अलगाववादी और आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा और समर्थन देने वाले कर्मचारियों को सरकार से निकाल दिया।

सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों को विभिन्न सेवाएं उपलब्ध कराने वाले लोगों को भी निशाना बनाया जो आतंकियों के लिए उनके फोन रिचार्ज कराने, उन्हें शरण देने और आतंकवादियों को सुरक्षाबलों की गतिविधियों की जानकारी पहुंचाने जैसे कामों में लगे थे। 2019 के बाद से जम्मू-कश्मीर पुलिस ने सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम और गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत ज़मीन पर काम करने वाले 900 से अधिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है।

तालिका 3 : गिरफ्तार किए गए आतंकी कार्यकर्ताओं की वर्षवार संख्या

वर्ष	2019	2020	2021	2022'
गिरफ्तारियां	372	277	184	90

स्रोत : गृह मंत्रालय और भारतीय सेना

(जनवरी से जून 2022 की अवधि के आंकड़े)

आतंकवादियों को मिलने वाले फंड और आर्थिक सहायता को रोकना भी सुरक्षा व्यवस्था के लिए बड़ी समस्या बनी हुई है। इस उद्देश्य के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने आतंकवादी फंडिंग के मामलों में पूछताछ शुरू की है।[5] इनके साथ ही गृह मंत्रालय ने एनआईए, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई), गुप्तचर ब्यूरो आईबी और जम्मू-कश्मीर पुलिस के प्रतिनिधियों तथा वित्तीय एजेंसियों (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड और कस्टम विभाग) के सहयोग से आतंक मॉनीटरन ग्रुप का गठन किया है जो आतंकवादियों को मिलने वाले धन पर कड़ी निगाह रखेगा।[6] इन उपायों से पाकिस्तान की आईएसआई और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर के आतंकवादियों के सरगनाओं तथा कश्मीर में उनके हिमायतियों के बीच की मिलीभगत का पर्दाफाश हो गया जो अलगाववादी भावनाएं भड़काने और आतंकी हिंसा फैलाने के लिए एकजुट हो रहे थे। सुरक्षा बलों की इस कार्रवाई से कश्मीर घाटी में अशांति का बड़ा कारण बन चुकीं पत्थरबाजी की घटनाएं एकदम से कम हो गईं। पाकिस्तान हर मंच पर और हर मौके पर पत्थरबाजी की

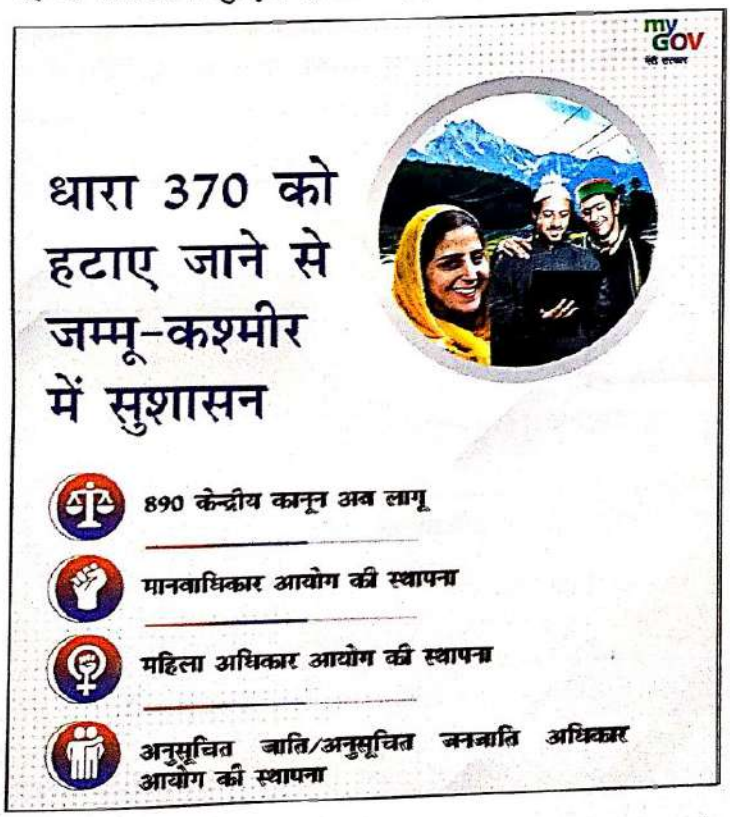

Scanned with OKEN Scanner

इन घटनाओं को भारत-विरोधी तथा कश्मीरियों के आज़ाद होने की भावनाओं का आधार बताता रहता था।

विशेष बात यह है कि सुरक्षा बलों ने आतंकवाद से निपटने के इस अभियान में केवल कठोर उपायों का सहारा ही नहीं लिया बल्कि अनेक उदार तरीके भी अपनाए जिनकी स्थानीय लोगों ने सराहना भी की। इनमें भरपूर संयम बरतना, पेलेट गन इस्तेमाल न करना और आतंकवाद रोकने की कार्रवाई और विरोध प्रदर्शन रोकने के दौरान कम से कम नुकसान पहुंचाने पर पूरा ध्यान देना। नतीज़ा यह हुआ कि अगस्त, 2019 के बाद से मुठभेड़ के दौरान या विरोध-प्रदर्शनों पर पेलेट गन चलाए जाने के दौरान कोई नागरिक हताहत नहीं हुआ। बल्कि, उच्च सुरक्षा अधिकारी सक्रिय आतंकवादियों के घरवालों को समझाने उनके घर गए कि वे अपने बच्चों को आतंकवाद छोड़ने और हथियार डालने के लिए राज़ी करें। ऐसे ही एक मौके पर सितम्बर, 2021 में सेना और पुलिस के उच्च अधिकारियों ने दक्षिण कश्मीर के शोपियां में सक्रिय आतंकवादियों के 80 परिवारों से मुलाकात करके उनसे अनुरोध किया कि वे अपने बेटों को आतंकवाद का रास्ता छोड़ने के लिए समझाएं।[7] इस तरह की पहलों सें आईएसआई और आतंकवादियों के आकाओं को दुष्प्रचार की सामग्री और अवसर से वंचित रहना पड़ा।

उच्च सुरक्षा अधिकारी सक्रिय आतंकवादियों के घरवालों को समझाने उनके घर गए कि वे अपने बच्चों को आतंकवाद छोड़ने और हथियार डालने के लिए राज़ी करें। ऐसे ही एक मौके पर सितम्बर, 2021 में सेना और पुलिस के उच्च अधिकारियों ने दक्षिण कश्मीर के शोपियां में सक्रिय आतंकवादियों के 80 परिवारों से मुलाकात करके उनसे अनुरोध किया कि वे अपने बेटों को आतंकवाद का रास्ता छोड़ने के लिए समझाएं।

सुरक्षा एजेंसियों के इन उपायों का घाटी में सुरक्षा की स्थिति पर सीधा असर पड़ा है। इससे वहां स्थानीय पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिला और 2022 की पहली छमाही में बड़ी संख्या में पर्यटक वहां गए; छह महीने की इस अवधि में एक करोड़ से ज़्यादा सैलानी इस क्षेत्र में घूमने गए। कश्मीर घाटी के अब तक के इतिहास में पर्यटकों की यह सर्वाधिक संख्या है।[8]

आतंकवाद की रोकथाम के दौरान उभरती चुनौतियां

इसी दौरान पाकिस्तान स्थित तत्वों के स्थिति बिगाड़ने की कोशिशें जारी रखने के कारण इस क्षेत्र में नई चुनौतियां उभरकर सामने आ रही हैं।

1. कट्टरपंथी बनाना और आतंकियों की भर्ती करना : जहां सुरक्षाबलों ने मोटे तौर पर स्थिति पर नियंत्रण पा लिया है वहीं उनके लिए बड़ी चिंता का विषय है। स्थानीय स्तर पर और मुख्य रूप से दक्षिण कश्मीर के चार पुलिस जिलों- पुलवामा, शोपियां, कुलगाम और अवंतिपुरा में आतंकवादियों की भर्ती में बढ़ोतरी।

आतंवादियों की स्थानीय भर्ती में अहम भूमिका स्थानीय युवाओं को कट्टरवादी बनाने में कामयाबी हासिल की है और यही सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा चुनौती बनकर उभरी है। कट्टरवाद फैलाने की प्रक्रिया में हमउम्र साथियों का दबाव, पीड़ित बने रहने की भावना और सलाफी तथा वहाबी प्रोपेगंडा से प्रभावित होकर खुद ही कट्टरवादी बनने का जज़्बा बहुत मददगार बना हुआ है। कश्मीर घाटी में कुछ वर्षों के दौरान धार्मिक प्रचारकों की संख्या लगभग दुगुनी हो गई है। साइबर स्पेस (डार्क वेब सहित) और स्पेशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी उनके धार्मिक प्रचार को और प्रसारित करके कट्टरवाद फैलाने की प्रक्रिया की गति और तेज करने में सहायक बनते हैं।

कट्टरवाद फैलाने की इस प्रक्रिया से निपटने का काम चल रहा है और सुरक्षा बलों द्वारा इस प्रवृत्ति को पलटने की अनेक पहलें शुरू की हैं। उदाहरण के तौर पर भारतीय सेना की पहल 'सही रास्ता' का उद्देश्य गुमराह युवाओं को राष्ट्रीय एकता दौरों, खेल प्रशिक्षण कार्यक्रमों और त्यौहारों तथा कौशल विकास कार्यशालाओं के माध्यम से सही रास्ते पर वापिस लाने का प्रयास किया जा रहा है।[9]

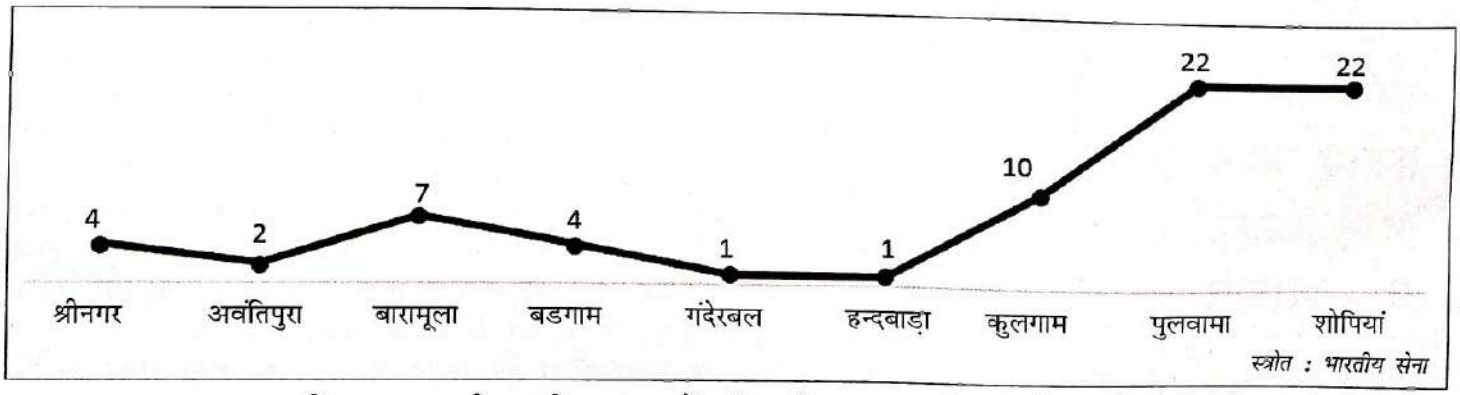

चित्र 1 : कश्मीर घाटी : 2022 में पुलिस जिलावार आतंकवादियों की भर्ती

तालिका-4 : स्थानीय स्तर पर आतंकवादियों की भर्ती

वर्ष	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022*
भर्ती	19	31	63	83	86	128	210	117	178	142	74

स्रोत : गृह मंत्रालय और भारतीय सेना

** (जनवरी से जून 2022 की अवधि के आंकड़े)*

Scanned with OKEN Scanner

2. हाईब्रिड आतंकवादी और वर्चुअल आतंकवादी संगठन : घुसपैठ रोकथाम की कार्रवाइयां बढ़ने और कई सक्रिय आतंकवादियों के मारे जाने के बाद अब उस क्षेत्र के आतंकी संगठनों ने अपनी नीति बदल ली है ताकि उनकी गतिविधियों के बारे में उलझन बनी रहे। अब ये लोग हिंसा करने के लिए आतंकवादियों से सहानुभूति रखने वालों की आड़ ले रहे हैं। ऐसे लोगों में से अधिकांश का कोई पुलिस रिकॉर्ड ही नहीं होता है जिसकी वजह से वे साफ बच निकलते हैं। 'हाईब्रिड' आतंकवादी वे हैं जो हाल में श्रीनगर और आसपास के इलाकों में निशाना बनाकर की गई हत्याओं के लिए जिम्मेदार हैं। साथ ही, सुरक्षा बलों ने जम्मू-कश्मीर गजनबी फोर्स और द रजिस्टेंट फ्रंट जैसे वर्चुअल आतंकी गुटों के विस्तार का भी पता लगाया है जो असल में लश्करे तैयबा (एलईटी) और अन्य बड़े आतंकवादी गुटों के ही प्रतिरूप हैं। इस समस्या से निपटने के लिए जम्मू-कश्मीर पुलिस अपनी मानव और तकनीकी गुप्तचर क्षमता बढ़ा रही है जिससे इन हाइब्रिड आतंकवादियों की धरपकड़ में बहुत मदद मिल रही है।

3. पाकिस्तान का सूचना युद्ध : पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का दुष्प्रचार तंत्र अगस्त, 2019 के बाद से सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर भारत विरोधी प्रोपेगंडा फैलाने में पूरे ज़ोर-शोर से जुटा हुआ है। लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे भारत-विरोधी आतंकी गुटों को साजसामान और आर्थिक सहायता दिए जाने का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खुलासा हो जाने के बाद आईएसआई ने कश्मीर के आतंकवाद को वहां के लोगों का विरोध बताना शुरू कर दिया है और पाकिस्तान अब भारत पर मानवाधिकारों के उल्लंघन का दोष लगाने में जुट गया है। इस समूचे दुष्प्रचार का असल मकसद कश्मीर की ओर ध्यान खींचकर अन्य देशों की सहानुभूति प्राप्त करना है।

सूचना युद्ध के इस अभियान के जरिए पाकिस्तान एक बड़ी चुनौती खड़ी कर रहा है क्योंकि वह किसी भी मामूली घटना को तूल देकर भारत और सुरक्षा बलों के खिलाफ़ झूठा नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश करता है। इस तरह की कुचेष्टाओं से कश्मीर क्षेत्र में अगस्त, 2019 के बाद मिली कामयाबी बेकार हो सकती है। इन झूठे नैरेटिव्ज से निपटने के लिए भारत को अपने स्थापित लोकतांत्रिक मूल्यों को अपनाने के साथ व्यापक राष्ट्रीय प्रयास भी करने होंगे और पाकिस्तान के इस झूठ का पर्दाफाश करके सच्चाई दुनिया के सामने लानी होगी। सेना की श्रीनगर स्थित चिनार कोर इस दुष्प्रचार को रोकने के उपाय लागू कर रही है पर इसके प्रयासों को सफल बनाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन जुटाना और जागरूकता लाना जरूरी है।

यह तो स्पष्ट है कि क्षेत्रीय सुरक्षा परिवेश में प्रवाह आने और कश्मीर में सुरक्षा स्थिति बिगाड़ने की पाकिस्तान की सभी हरकतों के बावजूद वहां स्थिति काफी हद तक शांत और स्थिर बनी हुई है। सुरक्षाबलों ने निश्चित रूप से पासा पलटकर पाकिस्तान के इरादे नाकाम कर दिए हैं और वहां पाकिस्तान-समर्थित और सीमापार से चलाए जा रहे आतंकवाद को और उसके अप्रत्यक्ष खतरे को काफी हद तक कुचल दिया है। इस सफलता की स्थिति को बनाए रखने के लिए अन्य सरकारी एजेंसियों को बेहतर प्रशासन व्यवस्था अपनाकर इस प्रगति को आगे जारी रखना होगा। ■

संदर्भ

1. सुब्रमण्यण जयशंकर, "जम्मू-कश्मीर का दर्जा बदलने से समूचे भारत को लाभ होगा," फाइनेंशियल टाइम्स 24 सितंबर, 2019. https://www.ft.com/content/4f0e297a-d3bd-11e9-8d46-8def889b4137
2. "पाकिस्तान से जम्मू-कश्मीर के सांबा ज़िले तक आने वाली सुरंग का पता लगा," https://economictimes.indiatimes.com/nation-world/tunnel-from-pakistan-found-in-samba-district-of-jammu-and-kashmir/the-tunnel-was-400-metre-long-on-the-indian-side/slideshow/15337823.cms
3. प्रेस सूचना कार्यालय, भारत सरकार, "सीमा पर घुसपैठ रोकने के उपाय," 10 मार्च, 2021, https://pib.gov.in/Pressreleaseshare.aspx?PRID=1703760
4. गृह मंत्रालय, अधिसूचना दिनांक 28 फरवरी, 2019, https://www.mha.gov.in/sites/default/files/IS_I_DeclarationofJeIasunlawfulAssociation_06092019.pdf
5. गृह मंत्रालय, केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने नई दिल्ली में आज गुप्तचर एजेंसी एनआईए के 13वें स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया", पीआईबी दिल्ली, 21 अप्रैल, 2022, https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1818770
6. राहुल त्रिपाठी, "कश्मीर में अवैध धन का प्रवाह रोकने के लिए गृह मंत्रालय ने आतंक निगरानी समूह का गठन किया," द इंडियन एक्सप्रेस, 30 मार्च, 2019, https://indianexpress.com/article/india/mha-sets-up-terror-monitoring-group-to-check-flow-of-illegal-funds-in-kashmir-5649526/
7. बशारत मसूद, "सेना और पुलिस के उच्च अधिकारियों ने कश्मीर में सक्रिय आतंकवादियों के परिवारों से मुलाकात की," द इंडियन एक्सप्रेस, 1 सितंबर, 2021, https://indianexpress.com/article/india/top-army-police-officers-meet-families-of-active-kashmir-militants-7481243/
8. ज़ैद बिन शबीर, "1.05 करोड़ पर्यटक इस वर्ष के पहले छह महीनों में कश्मीर घूमने गए : भारत सरकार," कश्मीर ऑब्जर्वर, 18 जुलाई, 2022, https://kashmirobserver.net/2022/07/18/1-5-crore-tourists-visited-jk-in-first-six-months-of-2022-goi/
9. चिनार कोर-भारतीय सेना, "The 'Sahi Raasta' initiative," Facebook post, 10 April 2022, https://ms-my.facebook.com/chinarcorpsIA/videos/the-sahi-raasta-initiative-has-brought-a-change-in-the-lives-perspectives-of-mor/684341849501189/

हमारी पत्रिकाएं

योजना, कुरुक्षेत्र, आजकल, बाल भारती

में विज्ञापन देने हेतु

संपर्क करें :
अभिषेक चतुर्वेदी, संपादक
प्रकाशन विभाग
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार
सूचना भवन, सी जी ओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
दूरभाष : 011-24367453
ई मेल : pdjucir@gmail.com

Scanned with OKEN Scanner

निवेश को प्रोत्साहन

रोहित कंसल
दीपंकर सेनगुप्त

जम्मू और कश्मीर औद्योगिक नीति – 2021-30 इस केंद्र-शासित क्षेत्र में निवेश तथा औद्योगिक वृद्धि की अग्रणी नीति है। नई औद्योगिक विकास योजना अपनी तरह की सबसे आकर्षक योजना तो है ही, बल्कि इसमें पिछली योजनाओं की कमियाँ भी दूर की गई हैं। इसमें दूर-दराज के इलाकों को अधिक प्रोत्साहन देने का प्रावधान है जिससे संतुलित विकास को बल मिलेगा और अब तक उपेक्षित क्षेत्रों में खाली पड़ी जमीन का बेहतर उपयोग हो सकेगा। इस नीति में निवेश, वृद्धि और रोज़गार – इन सभी पक्षों पर विवेकपूर्ण तरीके से ध्यान दिया गया हैं। रोज़गार पैदा करने के प्रमुख उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, इस नीति में ऐसे उद्योगों पर ज़ोर दिया गया है जिनमें ज्यादा श्रमिक काम कर सकें और तैयार होने वाला उत्पाद ज्यादा मूल्य और गुणवत्ता का हो।

केंद्र सरकार ने तीन साल पहले विभिन्न कानूनी प्रक्रियाओं के अंतर्गत 'संविधान के समय-समय पर संशोधित प्रावधानों सहित सभी प्रावधान' जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू कर दिए। साथ ही, पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य को निम्न दो केंद्र-शासित क्षेत्रों में पुनर्गठित कर दिया- लद्दाख तथा जम्मू और कश्मीर। दीर्घकालीन नीति इस क्षेत्र और इसकी अर्थव्यवस्था में आमूल बदलाव लाने की थी। इस क्षेत्र में अनेक संभावनाएं तथा क्षमताएँ हैं लेकिन उनके अपेक्षाकृत कम परिणाम निकले हैं।

क्षेत्र के उक्त पुनर्गठन से तुरंत पहले इसकी स्थिति काफी खराब थी। 2018-19 में जम्मू और कश्मीर सरकार का व्यय राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 57 प्रतिशत था जिसके लिए अधिकतर धन केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जा रहा था। सरकार पर निर्भरता बहुत अधिक थी और निजी क्षेत्र कमजोर था। (लगभग समान विशेषताओं वाले हिमाचल प्रदेश में सरकारी व्यय मात्र 28 प्रतिशत था।) उस समय, तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य की प्राप्तियों का 40 प्रतिशत केंद्र सरकार से मिलता था। बहुत बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारियों (करीब 5 लाख) के होने से राज्य की कुल प्राप्तियों का एक चौथाई वेतन और पेंशन में चला जाता था। जम्मू और कश्मीर का प्रति व्यक्ति नेट घरेलू उत्पाद करीब 94,000 रुपये था जो हिमाचल प्रदेश के 1,76,000 रुपये की तुलना में करीब आधा था। जम्मू और कश्मीर में सड़कों का घनत्व हिमाचल प्रदेश की तुलना में पाँचवाँ हिस्सा था और हिमाचल प्रदेश के विपरीत, जम्मू और कश्मीर अपनी विशाल जल-विद्युत क्षमता का भी उपयोग नहीं कर पा रहा था।

यह टिकाऊ स्थिति नहीं था और इसे बदलना ज़रूरी था। जम्मू और कश्मीर को ऐसी स्थिति में लाना ज़रूरी था ताकि निजी उद्यम और निवेश यहाँ आएं और ज्यादा नौकरियाँ तथा आय सृजित होने से अर्थव्यवस्था मजबूत हो। ऐसे बदलाव के लिए उपयुक्त आर्थिक रणनीति ज़रूरी थी।

रोहित कंसल जम्मू और कश्मीर में कार्यरत वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं। ईमेल: rohitkansal1@gmail.com
दीपंकर सेनगुप्त जम्मू विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं। ईमेल: dsen68@gmail.com

Scanned with OKEN Scanner

आर्थिक नीतियों का निर्माण

किसी क्षेत्र के लिए उचित आर्थिक नीति के निर्माण के लिए उस क्षेत्र की सकारात्मक और नकारात्मक स्थितियों का जायजा लेना ज़रूरी होता है। यह बात जम्मू और कश्मीर पर भी लागू होती है। इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि जम्मू और कश्मीर की स्थिति और भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है कि यहाँ उत्पादित वस्तुओं की परिवहन लागत अधिक होगी जिससे उनकी कीमत भी बढ़ेगी। इसलिए महंगी वस्तुओं के कारोबार के लिए उचित आर्थिक रणनीति ऐसी होनी चाहिए जिसमें निवेशकों तथा नीति-निर्माताओं को इस तरह निर्देशित किया जाए कि वे ऐसी विशिष्ट वस्तुओं/सेवाओं के उत्पादन को बढ़ावा दें जो ऐसे खास ग्राहकों की पसंद की हों जो परिवहन लागत के कारण अधिक कीमत होने पर भी इन वस्तुओं/सेवाओं को खरीदें।

ऐसे अनेक उत्पाद/सेवाएँ हो सकती हैं जिनका क्षेत्र-विशेष में उत्पादन/निर्माण दीर्घ कालावधि में सम्बन्धित कौशल। स्थानीय जानकारी के विकास से संभव हुआ है और उस क्षेत्र की प्राकृतिक स्थिति की वजह से स्वाभाविक रूप से वहाँ वह उत्पादन/निर्माण होता हो। जम्मू और कश्मीर में अनेक उत्पादों/सेवाओं से सम्बन्धित कौशल और स्वाभाविक स्थितियाँ मौजूद हैं और उनपर ध्यान दिए जाने से इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में बदलाव की शुरूआत हो सकती है।

जहां तक स्थानीय उत्पादों का प्रश्न है, इस क्षेत्र के हस्तशिल्पों की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा है। जम्मू और कश्मीर में बड़ी मात्रा में सेब पैदा होता है और यहाँ अखरोट और केसर जैसे उत्पाद भी हैं जो जिनका आकार और वजन कम लेकिन कीमत ज्यादा होती है। पाँच हजार वर्ष से मशहूर यहाँ का प्राकृतिक सौन्दर्य, हथकरघे और हस्तशिल्प के अनूठे उत्पाद और अद्भुत पकवान जम्मू और कश्मीर को लाखों पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना देता है। यहाँ प्रचुर मात्रा में जल-विद्युत संसाधन और बढ़िया काम करने वाले लोग हैं और कुछ दुर्लभ खनिज भी यहाँ मिलते हैं।

केंद्र-शासित जम्मू और कश्मीर क्षेत्र के प्रशासन ने केंद्र सरकार की सलाह से ऐसी अनेक नीतियाँ लागू की हैं जो निवेशकों के अनुकूल और उद्यमियों को बढ़ावा देने वाली हैं। इन नीतियों में क्षेत्र की उक्त स्वाभाविक अनुकूलताओं और रुकावटों का पूरा ध्यान रखा गया है।

निवेश को बढ़ावा

जम्मू और कश्मीर औद्योगिक नीति – 2021-30 इस केंद्र-शासित क्षेत्र में निवेश तथा औद्योगिक वृद्धि की अग्रणी नीति है। नई औद्योगिक विकास योजना अपनी तरह की सबसे आकर्षक योजना तो है ही, बल्कि इसमें पिछली योजनाओं की कमियाँ भी दूर की गई हैं। इसमें दूर-दराज के इलाकों को अधिक प्रोत्साहन देने का प्रावधान है जिससे संतुलित विकास को बल मिलेगा और अब तक उपेक्षित क्षेत्रों में खाली पड़ी जमीन का बेहतर उपयोग हो सकेगा। इस नीति में निवेश, वृद्धि और रोज़गार– इन सभी पक्षों पर विवेकपूर्ण तरीके से ध्यान दिया गया हैं। रोज़गार पैदा करने के प्रमुख उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, इस नीति में ऐसे उद्योगों पर ज़ोर दिया गया है जिनमें ज्यादा श्रमिक काम कर सकें और तैयार होने वाला उत्पाद ज्यादा मूल्य और गुणवत्ता का हो।

इनमें इस केंद्र-शासित क्षेत्र के पारम्परिक रूप से सशक्त उद्योग, जैसे पर्यटन, हस्तशिल्प और बागवानी तो शामिल हैं ही, सूचना प्रौद्योगिकी तथा इससे जुड़ी सेवाएँ और स्वास्थ्य सेवा आदि शामिल हैं। इस नीति में वर्तमान सशक्त उद्यमों से जुड़े क्षेत्रों के विकास पर भी ध्यान दिया गया है – जैसे बागवानी में फसल तैयार होने के बाद उसके प्रबंधन से जुड़े काम तथा फिल्म पर्यटन जैसे पर्यटन के विविध रूप आदि।

पुराने अनुभवों को देखते हुए, इस नीति में वित्तीय सहायता को लेकर भी पिछली नीतियों की तुलना में ज्यादा विवेकपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया गया है। पिछली नीतियों में राज्य में निवेश लाने के लिए बड़े पैमाने पर सब्सिडी और करों में छूट दी गईं। लेकिन वित्तीय प्रोत्साहनों पर आधारित ऐसे अनेक निवेशों को उन क्षेत्रों से नहीं जोड़ा गया जिनमें जम्मू और कश्मीर स्वाभाविक रूप से सशक्त था। इसलिए वित्तीय मदद समाप्त होते ही ऐसे उद्यम टिक नहीं सके और उन्हें बंद करना पड़ा। नई नीति में उन क्षेत्रों पर ज्यादा ध्यान दिया गया है जिनमें राज्य की स्थिति स्वाभाविक रूप से अच्छी है। सेवा क्षेत्र राज्य की अर्थव्यवस्था का 53 प्रतिशत हिस्सा है इसलिए इस नीति में एक स्पष्ट सकारात्मक सेवा क्षेत्र सूची बनाई गई है जिसमें शामिल उद्यमों को प्रोत्साहन दिए जाएंगे। इनमें पर्यटन, फिल्म पर्यटन, स्वास्थ्य सेवाएँ, शिक्षा और कौशल विकास आदि शामिल हैं।

किसी क्षेत्र के लिए उचित आर्थिक नीति के निर्माण के लिए उस क्षेत्र की सकारात्मक और नकारात्मक स्थितियों का जायजा लेना ज़रूरी होता है। यह बात जम्मू और कश्मीर पर भी लागू होती है। इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि जम्मू और कश्मीर की स्थिति और भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है कि यहाँ उत्पादित वस्तुओं की परिवहन लागत अधिक होगी जिससे उनकी कीमत भी बढ़ेगी। इसलिए महंगी वस्तुओं के कारोबार के लिए उचित आर्थिक रणनीति ऐसी होनी चाहिए जिसमें निवेशकों तथा नीति-निर्माताओं को इस तरह निर्देशित किया जाए कि वे ऐसी विशिष्ट वस्तुओं/सेवाओं के उत्पादन को बढ़ावा दें जो ऐसे खास ग्राहकों की पसंद की हों जो परिवहन लागत के कारण अधिक कीमत होने पर भी इन वस्तुओं/सेवाओं को खरीदें।

इस औद्योगिक नीति के प्रारम्भ के बाद की नीतिगत घोषणाओं और बजट प्रावधानों में इसी नीति के मूलभूत पक्षों को ही सशक्त किया गया है। उक्त घोषणाओं और बजट प्रावधानों का उद्देश्य इसी नीति के विविध पक्षों का विस्तार करना और उन्हें सशक्त बनाना है। यह एक सुस्थापित तथ्य है कि उचित नीति तथा सुसंगत बजट प्रावधानों में सही ताल-मेल होने से कई गुना अच्छे परिणाम मिलते हैं। इसीलिए इस वर्ष के बजट के अनेक प्रावधानों में निवेश आकर्षित करने तथा विभिन्न क्षेत्रों के लिए विशिष्ट प्रावधान करने पर ज़ोर दिया गया है।

पर्यटन

जम्मू और कश्मीर को लंबे समय से पर्यटन के साथ जोड़ा जाता है लेकिन यह आश्चर्यजनक है कि पर्यटकों की

Scanned with OKEN Scanner

कुल संख्या अथवा जनसंख्या के अनुपात में पर्यटकों की आमद के मामले में यह तत्कालीन राज्य कभी भी देश के चोटी के दस राज्यों में नहीं रहा। इस केंद्र-शासित क्षेत्र के वर्तमान बजट में 75 नए पर्यटन-केन्द्रों के लिए मदद और संसाधन दिए गए हैं ताकि क्षेत्र की पर्यटन अर्थव्यवस्था का विस्तार हो और बहुत अधिक रोज़गार की संभावना वाले इस क्षेत्र में ज्यादा रकम आए। इससे जुड़े दूसरे विभागों के कार्यों और उनको दिए गए वित्तीय प्रावधानों के साथ समझदारी से ताल-मेल बिठाया जा रहा है, जैसे संस्कृति विभाग परम्परागत मेलों और सूफी समारोहों को नए सिरे से प्रोत्साहित कर रहा है। इनमें से अनेक दूर-दराज के अनजान इलाकों में हैं जो जम्मू और कश्मीर के ग्रामीण पर्यटन नेटवर्क का हिस्सा हैं। इनसे स्थानीय युवाओं को प्रोत्साहन और ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इन प्रयासों के साथ तालमेल से बेहतर परिणाम मिलने की उम्मीद है। आंकड़ों को देखने से लगता है कि इन प्रयासों का लाभ मिल रहा है। पिछले वर्ष नवंबर में जम्मू और कश्मीर में पिछले सात वर्षों में सबसे अधिक संख्या में पर्यटक आए। 27 मार्च को 36,473 पर्यटक ट्यूलिप गार्डन देखने आए। यह अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। इस वर्ष 4 अप्रैल श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के इतिहास में व्यस्ततम दिन रहा। उस दिन 90 उड़ानों में 15,014 लोग या तो श्रीनगर आए या यहाँ से गए।

जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने एक और पहल की है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के बीच पिछले दिनों व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (सीईपीए) हुआ है। इसमें कारोबार के लिए बाज़ार, निवेश और पर्यटन का विस्तार करने के प्रावधान हैं।

बागवानी

बागवानी के लिए बजट में उत्पादकता और आमदनी – दोनों बातों पर ध्यान दिया गया है। बजट में प्रोत्साहित किए गए क्षेत्रों में शामिल हैं -कोल्ड स्टोरेज की क्षमता को बढ़ावा देना;ज्यादा बगीचे लगाकर सेब की उत्पादकता बढ़ाना, कम जगह में आ जाने वाले और ज्यादा दाम देने वाले कृषि-उत्पादों, जैसे सुगंध वाली और नकदी फसलों तथा सब्जियों को प्रोत्साहित करना आदि। केसर और अन्य उत्पादों के लिए जीआई प्रमाणन प्राप्त करने की प्रक्रिया चल रही है। इन प्रयासों से इस क्षेत्र में संभावनाएं बढ़ेंगी। अगर इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप उत्पादकता बढ़ सकेगी तो इस क्षेत्र का विस्तार चार गुना हो जाएगा। फलों से विभिन्न उत्पाद तैयार कर इसके मूल्य-संवर्धन से (जो इस समय बहुत कम है) बागवानी में काफी वृद्धि हो सकेगी और बहुत लोगों को रोज़गार मिल सकेगा।

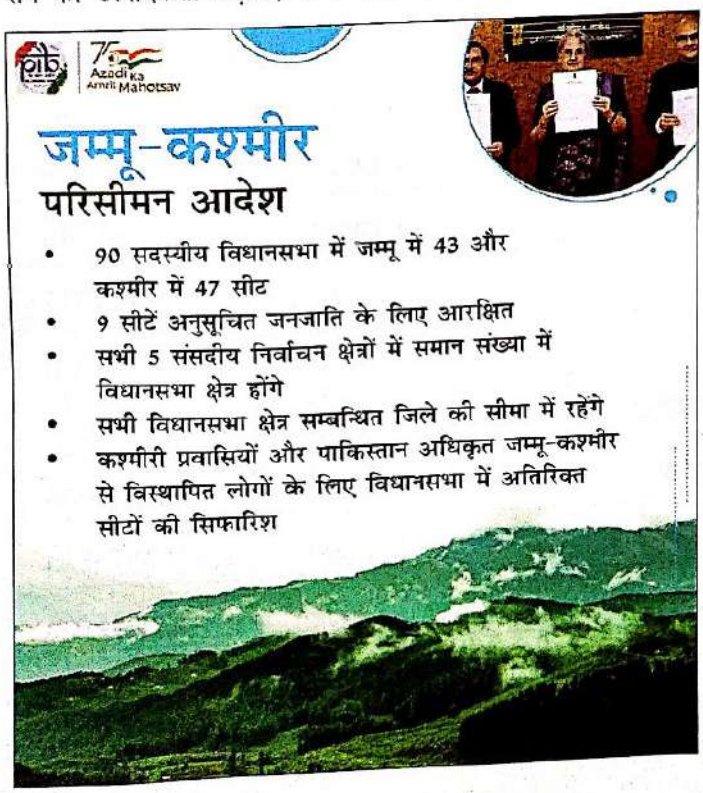

विदेश व्यापार और निवेश

जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने एक और पहल की है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के बीच पिछले दिनों व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (सीईपीए) हुआ है। इसमें कारोबार के लिए बाज़ार, निवेश और पर्यटन का विस्तार करने के प्रावधान हैं। जम्मू और कश्मीर को इस समझौते से लाभान्वित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। यूएई कश्मीर से घनिष्ठता के साथ सुपरिचित है। अतः इन संपर्कों और संभावनाओं का लाभ उठाते हुए, खाड़ी क्षेत्र से निवेश प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

जम्मू और कश्मीर में निवेश बढ़ाना

इन नीतियों का जम्मू और कश्मीर में निवेश के लिए इच्छुक निवेशकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इस क्षेत्र में संवैधानिक अनिश्चितता समाप्त होने, कानून और व्यवस्था की बेहतर स्थिति, मूलभूत सुविधाओं पर बहुत अधिक ध्यान दिए जाने तथा आर्थिक विकास पर केन्द्रित कार्य-नीति अपनाए जाने से निवेशकों की इस क्षेत्र में दिलचस्पी बढ़ी है और अनेक नीतियों के प्रति उनका रुख उत्साहजनक रहा है।

जो निवेशक पहले तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य में निवेश करने से कतराते थे, वे अब नवगठित केंद्र-शासित क्षेत्र में निवेश करने के लिए उत्साहित नज़र आ रहे हैं। यहाँ के प्रशासन को 51,000 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले हैं जिनसे 2.37 लाख लोगों को रोज़गार मिलने का अनुमान है। केंद्र-शासित क्षेत्र की औद्योगिक नीति में 10 साल में 28,400 करोड़ रुपये किए जाने का प्रावधान है। इसे देखते हुए निवेश की उक्त संभावनाएं, हर तरह से प्रभावशाली लगती हैं। साथ ही, यह भी महत्वपूर्ण है कि अब इस क्षेत्र में विदेशी, खास तौर से यूएई के सुपरिचित नामों और ब्रांडों की दिलचस्पी बढ़ी है। यह बात भी महत्वपूर्ण है कि जिन क्षेत्रों में निवेश की पेशकश हुई है और प्रस्ताव मिले हैं उनमें से अधिकतर सरकार की औद्योगिक नीति के अंतर्गत सकारात्मक क्षेत्रों की सूची में शामिल हैं। ये तथ्य इस क्षेत्र और निवेशकों – दोनों के लिए उत्साहवर्धक हैं।

लाभदायक क्षेत्रों में निवेश की रणनीति

जम्मू और कश्मीर में धन लगाने से पहले निजी निवेशक क्या अपेक्षा रखता है? इसका स्पष्ट उत्तर यही है कि उसे उसके निवेश पर लाभ मिले। इसके किए ज़रूरी है कि निवेशक की व्यावसायिक योजना राज्य की प्राकृतिक, पारम्परिक और मानव संसाधनों से कितनी घनिष्ठता से जुड़ी है। एक सुव्यवस्थित कारोबार ऐसे ही पुख्ता आधार पर लाभदायक बना रहता है, हमेशा सरकारी सब्सिडी

Scanned with OKEN Scanner

के भरोसे नहीं टिका रहता। जम्मू और कश्मीर में पिछले दिनों पर्यटकों की भीड़ ने सारे पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए। इससे पता चलता है कि यह क्षेत्र निवेशकों के लिए कितना लाभदायक हो सकता है। इसलिए, इस क्षेत्र में, खास कर अब तक अनजाने रहे इलाकों में, निवेश करना काफी लाभदायक हो सकता है। बागवानी और फसल के बाद उत्पाद के मूल्य-संवर्धन की प्रक्रियाओं में निवेश भी फायदेमंद हो सकता है। इन दोनों क्षेत्रों में यह केंद्र-शासित क्षेत्र प्राकृतिक रूप से समृद्ध है, साथ ही इन उद्यमों के बारे में स्थानीय लोगों को जानकारी भी है और ये पारम्परिक क्षेत्र भी हैं। इसलिए इन क्षेत्रों में निवेश पर अच्छा मुनाफा हो सकता है।

निवेशक मुनाफे की अच्छे संभावनाओं वाले अनेक अन्य क्षेत्रों में भी निवेश कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, सूचना टेक्नोलॉजी और इससे जुड़ी सेवाओं में बड़ी संख्या में कुशल स्थानीय युवाओं को काम पर लिया जा सकता है। सूचना टेक्नोलॉजी की प्रगति तथा कोविड-19 की वजह से, इस क्षेत्र में घर से ही काम करने का रुझान बढ़ गया है। इन सारी स्थितियों को देखते हुए इस क्षेत्र में निवेश में मुनाफे की अच्छी संभावनाएं हो गई हैं।

निवेशक मुनाफे की अच्छे संभावनाओं वाले अनेक अन्य क्षेत्रों में भी निवेश कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, सूचना टेक्नोलॉजी और इससे जुड़ी सेवाओं में बड़ी संख्या में कुशल स्थानीय युवाओं को काम पर लिया जा सकता है। सूचना टेक्नोलॉजी की प्रगति तथा कोविड-19 की वजह से, इस क्षेत्र में घर से ही काम करने का रुझान बढ़ गया है। इन सारी स्थितियों को देखते हुए इस क्षेत्र में निवेश में मुनाफे की अच्छी संभावनाएं हो गई हैं।

जम्मू और कश्मीर में ऐसे ही नवीन संभावनाओं वाले क्षेत्रों में सेवा, शिक्षा और स्वास्थ्य और समग्र आरोग्य से जुड़े उद्यम शामिल हैं।

लेकिन मात्र सब्सिडी का फायदा उठाने के लिए जम्मू और कश्मीर में निवेश करना अविवेकपूर्ण होगा और इससे लंबे समय में नुकसान ही होगा। इस केंद्र-शासित क्षेत्र की नई आर्थिक व्यवस्था को देखते हुए निवेशकों के लिए यही फायदेमंद होगा कि वे यहाँ निवेश करते समय यहाँ के लोगों और परिस्थितियों से जुड़ा रहे।

उज्ज्वल भविष्य की ओर

सरकार की आर्थिक नीति का उद्देश्य ऐसा बदलाव लाना है जिसमें नया जम्मू और कश्मीर निरंतर प्रगतिशील भारत के साथ-साथ चले और जहां घूमने तथा संभावनाएं तलाशने के नए-नए इलाके हों। यहाँ का बागवानी क्षेत्र ऐसे फल उपजाए और फलों से बनने वाले उत्पाद तैयार करे जो गुणवत्ता में विश्व-स्तर के हों। सदियों के अनुभव और संस्कृति के बीच विकसित यहाँ के हस्तशिल्पों का दुनिया भर में नई ऊर्जा से निर्यात किया जाए। इस क्षेत्र को भारत की एक-तिहाई जल-विद्युत पैदा करनी होगी। इस क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी और सम्बन्धित सेवाओं, औषधि उद्योग, वस्त्र उद्योग और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों के विकास की भी बहुत संभावनाएं हैं। स्वास्थ्य, आरोग्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी यह क्षेत्र देश भर में बेजोड़ हो सकता है।

सरकार की नीति इन सभी संभावनाओं को सफल बनाने की है। निजी निवेशक अगर सरकार के साथ ताल-मेल से अपनी निवेश-नीतियाँ बनाएंगे तो इस केंद्र-शासित क्षेत्र में निवेश करने से उन्हें निश्चित रूप से लाभ होगा। ■

(इस लेख में व्यक्त विचार लेखकों के पूर्णतः निजी विचार हैं।)

प्रकाशन विभाग के विक्रय केंद्र			
नई दिल्ली	पुस्तक दीर्घा, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड	110003	011-24367260
नवी मुंबई	701, सी- विंग, सातवीं मंज़िल, केंद्रीय सदन, बेलापुर	400614	022-27570686
कोलकाता	8, एसप्लानेड ईस्ट	700069	033-22488030
चेन्नई	'ए' विंग, राजाजी भवन, बसंत नगर	600090	044-24917673
तिरुअनंतपुरम	प्रेस रोड, नयी गवर्नमेंट प्रेस के निकट	695001	0471-2330650
हैदराबाद	कमरा सं. 204, दूसरा तल, सीजीओ टावर, कवाड़ीगुड़ा, सिकंदराबाद	500080	040-27535383
बेंगलुरु	फर्स्ट फ्लोर, 'एफ' विंग, केंद्रीय सदन, कोरामंगला	560034	080-25537244
पटना	बिहार राज्य कोऑपरेटिव बैंक भवन, अशोक राजपथ	800004	0612-2675823
लखनऊ	हॉल सं-1, दूसरा तल, केंद्रीय भवन, क्षेत्र-एच, अलीगंज	226024	0522-2325455
अहमदाबाद	4-सी, नेप्चून टॉवर, चौथी मंज़िल, नेहरू ब्रिज कॉर्नर, आश्रम रोड	380009	079-26588669
गुवाहाटी	असम खाड़ी एवं ग्रामीण उद्योग बोर्ड, भूतल, एमआरडी रोड, चांदमारी	781003	0361.2668237

Scanned with OKEN Scanner

फ़िल्मांकन की पसंदीदा जगह

नीतीश्वर कुमार

फिल्म और फिल्म निर्माण के साथ जम्मू-कश्मीर का अनोखा और यादगार जुड़ाव रहा है। 'कश्मीर की कली', 'जब-जब फूल खिले', 'हिमालय की गोद में', 'जानवर' जैसी फिल्में सिनेमा और जम्मू-कश्मीर के लोगों के बीच इस खूबसूरत रिश्ते का गवाह हैं। जम्मू-कश्मीर सरकार ने अब 'जम्मू-कश्मीर की फिल्म नीति' बनाई है। इस नीति के तहत इस केंद्रशासित प्रदेश में फिल्मों की शूटिंग को बढ़ावा देने पर ज़ोर होगा और इसके लिए वित्तीय व अन्य सुविधाएं भी मुहैया कराई जाएंगी। साथ ही, यहां की सरकार फिल्मों से जुड़ी विश्वस्तरीय आधारभूत संरचना बनाने में भी सहयोग करेगी।

लेखक भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं और फिलहाल जम्मू-कश्मीर विकास परिषद के चेयरमैन और जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल के प्रधान सचिव हैं।
ईमेल: ps.rb-jk@nic.in

Scanned with OKEN Scanner

'तुमसे अच्छा कौन है', 'जय-जय शिव शंकर', 'नूरी..नूरी', 'कभी-कभी मेरे दिल में खयाल आता है'..., 'चली रे चली', 'जिया रे जिया रे', 'ज़िंदगी कुछ तो बता ज़िंदगी'...'कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है', इन सभी गानों में एक चीज़ समान है। इन सभी गानों की शूटिंग कश्मीर में हुई है।

कश्मीर में फिल्मों की शूटिंग का सिलसिला अब फिर से शुरू हो गया है। जम्मू-कश्मीर सरकार ने फिल्म क्षेत्र को प्राथमिकता सूची में रखते हुए अगस्त 2021 में 'जम्मू-कश्मीर की फिल्म नीति' बनाई थी। इस नीति का मकसद जम्मू-कश्मीर को भारत के फिल्म निर्माण का लोकप्रिय ठिकाना बनाना और इस क्षेत्र के ज़रिए बड़े पैमाने पर लोगों को रोज़गार मुहैया कराना है। नीति के तहत, इस केंद्रशासित प्रदेश में फिल्म निर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देकर यहां पर्यटन संबंधी गतिविधियों का विस्तार करने और निवेश के विकल्प पेश करने की बात है।

इस नीति को पेश करने से पहले जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अगुवाई में सम्बन्धित पक्षों से गहन विचार-विमर्श किया गया। मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई और कोलकाता में मौजूद फिल्म इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों से भी विशेष तौर पर सलाह ली गई। साथ ही, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अलग-अलग फिल्म नीतियों की समीक्षा की गई, ताकि फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी बेहतर परम्पराओं के बारे में जानकारी हासिल कर जम्मू-कश्मीर की फिल्म नीति में विजन, मकसद, रोडमैप और प्रोत्साहन का बेहतर समावेश किया जा सके। इस नीति की वजह से जम्मू-कश्मीर में बड़े बजट वाली फिल्मों की शूटिंग का प्रचलन बढ़ रहा है और दिग्गज कलाकार, निर्देशक आदि इस केंद्रशासित प्रदेश में फिल्म निर्माण को लेकर दिलचस्पी दिखा रहे हैं। इस नीति और सिंगल विंडो प्रणाली से मिल रही मदद से फिल्म उद्योग भी संतुष्ट है।

फिल्म और फिल्म निर्माण के साथ जम्मू-कश्मीर का अनोखा और यादगार जुड़ाव रहा है। फिल्म उद्योग ने हमेशा से बर्फ से ढंके पहाड़, खूबसूरत वादियां, मनोरम झरने, यहां की समृद्ध विरासत, दिलचस्प खान-पान, खूबसूरत परम्पराओं और रूहानी संगीत को अपने दायरे में समेटने की कोशिश की है। साथ ही, यहां के स्थानीय लोग भी हमेशा शानदार मेज़बान साबित हुए हैं और उन्होंने फिल्म उद्योग की ज़रूरतों को भी पूरा किया है। 'कश्मीर की कली', 'जब-जब फूल खिले', 'हिमालय की गोद में', 'जानवर' जैसी फिल्में सिनेमा और जम्मू-कश्मीर के लोगों के बीच इस खूबसूरत रिश्ते का गवाह हैं। हालांकि, इस जुड़ाव की कहानी अपने-आप में फिल्मी है। इस क्षेत्र में बंदूक की संस्कृति पनपने के कारण कुछ समय के लिए यहां फिल्मों से जुड़ी गतिविधियों पर विराम लग गया था। जम्मू-कश्मीर में हिंसात्मक गतिविधियों का प्रकोप बढ़ गया था, लेकिन पुरानी हिन्दी

Scanned with OKEN Scanner

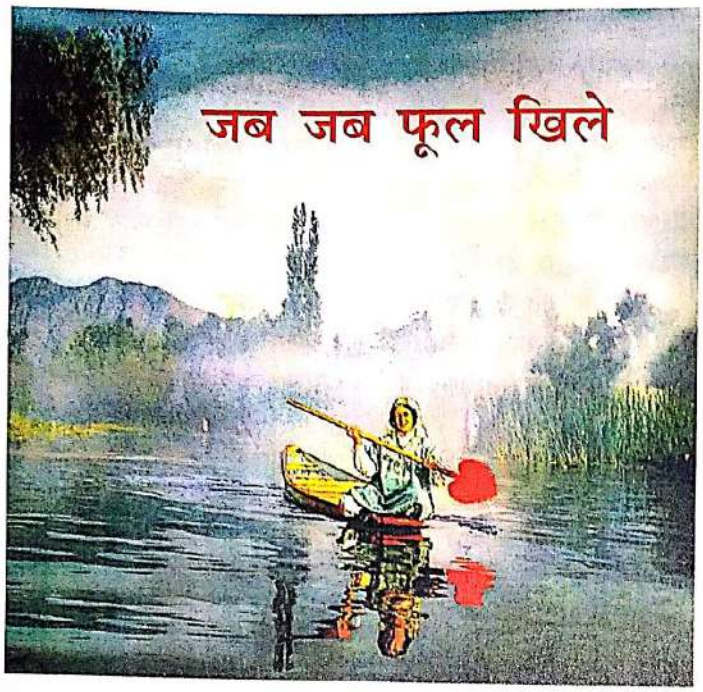

फिल्मों की तरह ही यहां भी आखिरकार प्यार की जीत हुई और ऐसा लगा मानो ज़ंज़ीरें धीरे-धीरे खुल रही हों और प्यार करने वाले एकजुट हो रहे हों!

नीति में शानदार ऑफरों की भरमार

जम्मू-कश्मीर फिल्म नीति का मसौदा काफी व्यापक है। मसौदे के 12 से भी ज़्यादा खंडों में बताया गया है कि राज्य में फिल्म उद्योग को किस तरह पुनर्जीवित करके उसे भारत का लोकप्रिय फिल्म निर्माण ठिकाना बनाया जा सकता है। इसके लिए साल 2026 तक हर वित्त वर्ष में 100 करोड़ रुपये का वित्तीय आवंटन भी किया जाएगा। जम्मू-कश्मीर में फिल्मों की शूटिंग करने पर सब्सिडी पैकेज का भी ऐलान किया गया है, मसलन अगर यहां कोई शख्स अपनी पहली फिल्म की शूटिंग करता है, तो उसे 1 करोड़ रुपये तक की सब्सिडी दी जा सकती है, जबकि तीसरी फिल्म की शूटिंग पर 2 करोड़ तक की सब्सिडी उपलब्ध कराई जा सकती है। ओटीटी फिल्मों और वेब सीरीज़ जैसी नई श्रेणियों में भी सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, देशभक्ति थीम वाली फिल्मों, एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम और स्थानीय कलाकारों का उपयोग करने वाली फिल्मों को भी विशेष प्रोत्साहन देने की बात कही गई है। इस नीति में, फिल्मों की शूटिंग, वित्तीय और अन्य तरह की गतिविधियों के लिए बड़े पैमाने पर मदद और प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया है। साथ ही, विश्वस्तरीय आधारभूत संरचना तैयार करने यानी फिल्म सिटी, स्टूडियो, मल्टीप्लेक्स आदि बनाने के लिए सरकारी मदद उपलब्ध कराई जाएगी।

इसके अलावा, कुछ और सुविधाएं भी देने का ऐलान किया गया है जिनमें जगह, मानव संसाधन और उपकरण उपलब्ध कराने के लिए सिंगल विंडो प्रणाली तैयार करना, जम्मू-कश्मीर में फिल्म निर्माण की प्रक्रिया को आसान बनाना और प्रशासनिक स्तर पर बेहतर सेवाओं के लिए एकीकृत पोर्टल की सुविधा उपलब्ध कराना शामिल हैं। साथ ही, यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि तय समयसीमा के भीतर जम्मू-कश्मीर में फिल्म शूटिंग की अनुमति मिल सके। नीति के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर सरकार जम्मू-कश्मीर फिल्म विकास परिषद भी स्थापित करेगी। यह परिषद नीति में तय किए गए लक्ष्यों को युद्धस्तर पर लागू करेगी। जम्मू-कश्मीर फिल्म विकास परिषद की स्थापना, सिंगल विंडो प्रणाली के संचालन आदि से फिल्म शूटिंग की रफ्तार तेज़ होगी और शूटिंग से जुड़ी अन्य सहूलियतें बढ़ेंगी।

जम्मू-कश्मीर फिल्म विकास परिषद का मकसद फिल्म नीति में तय किए गए लक्ष्यों को हासिल करना है। यह परिषद अलग इकाई के तौर पर काम करती है। यह परिषद एक उच्चस्तरीय कमेटी है, जिसकी अगुवाई प्रधान सचिव करते हैं। केंद्रशासित प्रदेश के उपराज्यपाल इसके चेयरमैन हैं और इसके सदस्यों में वरिष्ठ, अधिकारी और अन्य अहम शख्सियतें शामिल हैं। जैसा कि नीति में बताया गया है, सिंगल विंडो प्रणाली को भी काफी कम समय में तैयार कर लिया गया, ताकि जम्मू-कश्मीर मे शूटिंग के लिए इच्छुक फिल्मकारों को सहूलियतें मिल सकें। इसके अलावा, एकीकृत पोर्टल भी तैयार किया गया है, जो जगह उपलब्ध कराने, स्थानीय कलाकारों और प्रतिभाओं की खोज, उपकरण उपलब्ध कराने, फिल्म शूटिंग के लिए जल्द अनुमति दिलाने और तय समयसीमा के भीतर सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए प्लैटफॉर्म की तरह काम करेगा।

यह नीति 5 अगस्त, 2021 को पेश की गई थी और इसके बाद से अब तक फिल्मों की शूटिंग के लिए पोर्टल पर 125 से भी ज्यादा आवेदन मिल चुके हैं। इनमें से 122 से भी ज्यादा आवेदनों को सिर्फ 4-5 कामकाजी दिनों में ही मंजूरी दे दी गई, जो देश में फिल्मों की शूटिंग की अनुमति हासिल करने में लगने वाले औसत समय से काफी कम है। हालांकि, पहले शूटिंग की अनुमति के लिए हर महीने सिर्फ 1-2 आवेदन ही मिलते थे और मंजूरी मिलने की प्रक्रिया पूरी होने में भी 20-25 दिन लगते थे।

फिल्म और फिल्म निर्माण के साथ जम्मू-कश्मीर का अनोखा और यादगार जुड़ाव रहा है। फिल्म उद्योग ने हमेशा से बर्फ से ढंके पहाड़, खूबसूरत वादियों, मनोरम झरने, यहां की समृद्ध विरासत, दिलचस्प खान-पान, खूबसूरत परम्पराओं और रूहानी संगीत को अपने दायरे में समेटने की कोशिश की है। साथ ही, यहां के स्थानीय लोग भी हमेशा शानदार मेज़बान साबित हुए हैं और उन्होंने फिल्म उद्योग की ज़रूरतों को भी पूरा किया है।

आगे की राह

फिल्म सिटी का संकल्प

जम्मू-कश्मीर सरकार अपने यहां फिल्म निर्माण के लिए बेहतरीन माहौल और राष्ट्रीय स्तर की आधारभूत संरचना तैयार करना चाहती है। इसके लिए यह सरकार फिल्म सिटी स्थापित करने की कोशिश में जुटी है, जहां म्यूजिक स्टूडियो, प्रशिक्षण संस्थान, सेट, उपकरण वेयरहाउस, ठहरने का इंतज़ाम आदि सुविधाएं होंगी। फिल्म उद्योग की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर तैयार की जाने वाली इस आधारभूत संरचना के ज़रिये जम्मू-कश्मीर को फिल्म निर्माण के लिए देश का एक बेहतर और लोकप्रिय ठिकाना बनाने में मदद मिलेगी।

Scanned with OKEN Scanner

हर साल फिल्म महोत्सव का आयोजन

फिल्म नीति में हर साल जम्मू-कश्मीर फिल्म महोत्सव के आयोजन की भी बात की गई है, ताकि फिल्मकार समुदाय को अपने आइडिया का आदान-प्रदान करने, अपना काम दिखाने और इस केंद्रशासित प्रदेश में फिल्मों के लिए अनूकूल माहौल बनाने में मदद मिले।

महोत्सव का मकसद दुनिया को जम्मू-कश्मीर की कला, संस्कृति, इतिहास, विरासत, आजीविका के साधनों और शानदार परम्पराओं से रूबरू कराना भी होगा।

जम्मू-कश्मीर फिल्म पुरस्कार

जम्मू-कश्मीर सरकार का इरादा फिल्मों और फिल्मकारों को पुरस्कार देने का भी है। पुरस्कारों की श्रेणियां कुछ इस तरह हो सकती हैं- जम्मू-कश्मीर की फिल्मों के लिए सर्वश्रेष्ठ, पुरस्कार (अवाड्र्स ऑफ एक्सीलेंस फॉर जेएंडके फिल्म्स) शूटिंग के लिए बेहतर ठिकाने के तौर पर जम्मू-कश्मीर का प्रचार करने वाली फिल्म आदि।

जम्मू-कश्मीर की फिल्मों का संरक्षण

सूचना और जनसंपर्क निदेशालय में जम्मू-कश्मीर फिल्म आर्काइव (अभिलेखागार) स्थापित करने का काम पहले से ही चल रहा है। इससे सरकार को न सिर्फ अच्छे कामों का रिकॉर्ड बनाए रखने में मदद मिलेगी, बल्कि आगे चलकर फिल्म उद्योग का डेटाबेस भी तैयार किया जा सकेगा। इसके अलावा, अगर कमेटी को मौजूदा आर्काइव (डिजिटल और एनालॉग दोनों) प्रासंगिक लगता है, तो उसे फिर से चालू किया जाएगा। निर्माताओं से अनुरोध किया जाएगा कि वे अपने फिल्म और प्रसार सामग्री की प्रति आर्काइव में जमा करें।

दौरे का आयोजन

सरकार आगामी महीनों में संभावित निवेशकों, फिल्मकारों, नीति-निर्माताओं, क्षेत्रीय फिल्मों के निर्माताओं और अन्य सम्बन्धित पक्षों का दौरा सुनिश्चित करने की योजना बना रही है, ताकि इस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिल सके।

शूटिंग वाली जगहें तैयार करना

जम्मू-कश्मीर फिल्म विकास परिषद शूटिंग के लिए संभावित जगहों की तलाश कर उसे विकसित करने में जुटी है। सिनेमा और खूबसूरती के हिसाब से अनुकूल इन जगहों को पर्यटन विभाग और निजी निवेशकों के साथ मिलकर विकसित किया जाएगा।

जम्मू-कश्मीर फिल्म विकास परिषद की स्थापना के साथ ही इन लक्ष्यों पर तेज़ी से काम शुरू हो गया है, ताकि फिल्म उद्योग और इससे जुड़े क्षेत्रों की राह आसान हो सके और ज़रूरी निवेश भी सुनिश्चित हो सके। साथ ही, परिषद का मकसद फिल्म उद्योग को नई ताकत प्रदान करना और जम्मू-कश्मीर के लोगों के बीच फिल्म और फिल्म निर्माण को लेकर उत्साह पैदा करना है।

इसके अलावा, स्थानीय प्रतिभाओं को बढ़ावा देने, शूटिंग के अनुकूल जगहों की तलाश और पर्यटन गतिविधियों से जुड़े जम्मू-कश्मीर के गाँवों की संभावनाओं के इस्तेमाल के लिए मिशन यूथ (युवा मिशन) अभियान और जम्मू-कश्मीर फिल्म विकास परिषद की तरफ से फ्लैगशिप कार्यक्रम चलाया गया है। इस अभियान के तहत, जम्मू-कश्मीर के चुनिंदा गाँवों में गाने और फिल्मों की शूटिंग को बढ़ावा दिया जाता है। जम्मू-कश्मीर की फिल्म नीति के मुताबिक, स्थानीय प्रतिभाओं और प्राकृतिक खूबसूरती को बढ़ावा देने जैसी किसी भी पहल के लिए 10 लाख रुपये की वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। इस कार्यक्रम के तहत जम्मू-कश्मीर के स्थानीय युवा समूहों को वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा। उन्हें यह वित्तीय प्रोत्साहन ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देकर रोज़गार पैदा करने और नई-नई जगहों का प्रचार करने के लिए मिलेगा। इसके अलावा, इस पहल से जम्मू-कश्मीर में फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए अंतर-विभागीय सहयोग की भी गुंजाइश बनेगी।

यह नीति कश्मीर घाटी और भारत में फिल्मों के लिए अनुकूल माहौल तैयार करने में अहम भूमिका निभा सकती है। इस नीति में स्थानीय फिल्मी प्रतिभा, सिनेमा से जुड़ी आधारभूत संरचना और टिकाऊ सेवा अर्थव्यवस्था पर ज़ोर है, जो अपने-आप में अनोखी बात है।

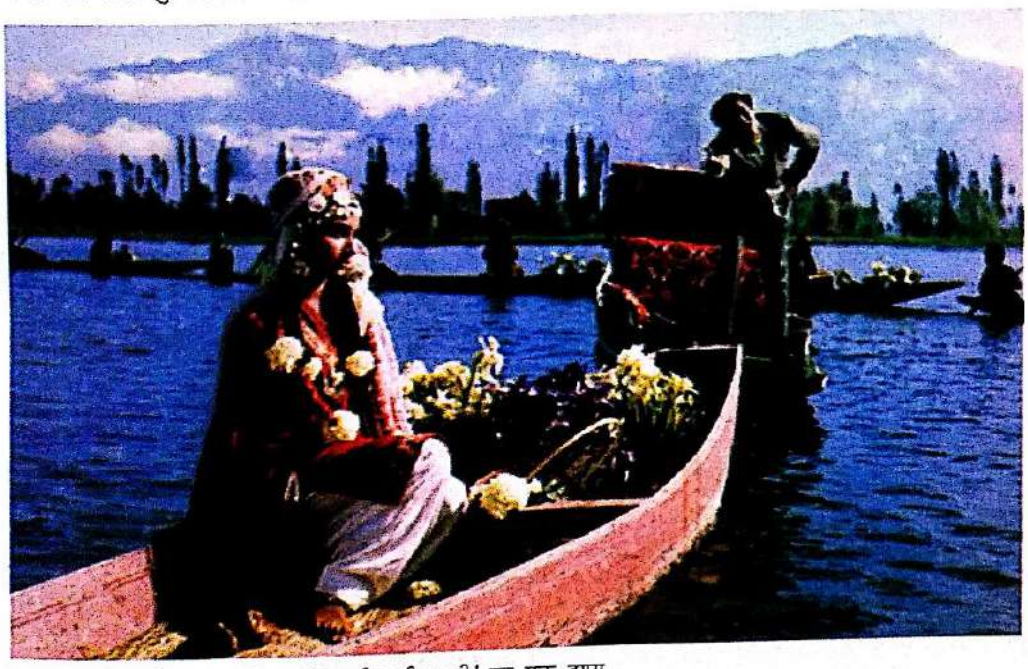

फ़िल्म 'कश्मीर की कली' का एक दृश्य

जम्मू-कश्मीर फिल्म नीति 2021 में न सिर्फ इस केंद्रशासित प्रदेश में फिल्म निर्माण के लिए विश्वस्तरीय सुविधाएं तैयार करने का लक्ष्य तय किया गया है, बल्कि जम्मू-कश्मीर और फिल्मों के बीच पुराने जुड़ाव को याद करते हुए इसे फिर से बहाल करने की बात भी कही गई है, ताकि अलग-अलग माध्यमों से पूरी दुनिया में इसकी गूंज सुनाई पड़े। ■

Scanned with OKEN Scanner

जीवन-यापन में सुगमता

अगस्त 2019 में जम्मू-कश्मीर में संवैधानिक सुधार होने के बाद से सरकार अभूतपूर्व गति से क्षेत्र के लोगों के लिए शासन में सुधार और जीवन यापन की सुगमता बढ़ाने के लिए व्यापक सुधार लाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

- बनिहाल काजीगुंड सुरंग का निर्माण 3,100 करोड़ रुपये की लागत से किया गया है और यह चालू हो गया है। 8.45 किलोमीटर लंबी इस सुरंग के बनने के बाद बनिहाल और काजीगुंड के बीच की दूरी 16 किलोमीटर तक घट गई है और यात्रा के समय में डेढ़ घंटे की बचत होगी। इस सुरंग से किसी भी मौसम में जम्मू और कश्मीर का संपर्क बना रहेगा और दोनों क्षेत्रों के बीच दूरी कम करने में मदद मिलेगी।
- प्रधानमंत्री ने जम्मू के पल्ली गांव में 500 किलोवाट के सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है। इस तरह यह देश की पहली कार्बन मुक्त पंचायत होगी।
- श्रीनगर का बहुप्रतीक्षित रामबाग फ्लाइओवर चालू हो गया है।
- मौजूदा सड़क और परिवहन परियोजनाएं:
  - बारामुला-गुलमर्ग: जम्मू-कश्मीर केंद्रशासित क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग-701 ए के तहत मौजूद सड़कों को अपग्रेड करना। कुल लंबाई 43 किलोमीटर, राष्ट्रीय राजमार्ग की गुणवत्ता में सुधार के लिए 85 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। इससे गुलमर्ग जाने वाले सैलानियों को सहूलियत होगी।
  - वेलू से दोनीपावा (पी-VI): जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-244 से जुड़ी सड़कों का निर्माण और चौड़ीकरण। कुल लंबाई 28 किलोमीटर, जिसके लिए 158 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके ज़रिये कोकरनाग और वेलू का संपर्क बेहतर हो सकेगा।
  - दोनीपावा से आशाजीप्रा (पी-VII): अनंतनाग में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-244 को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-44 से जोड़ा जाएगा। नए बाईपास का निर्माण होगा। सड़क की कुल लंबाई 8.5 किलोमीटर है और अनंतनाग शहर के पास बाइपास बनाने के लिए 57 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
  - श्रीनगर के आसपास 4 लेन वाले रिंग रोड का निर्माण (42 किलोमीटर), श्रीनगर शहर में भीड़-भाड़ और ट्रैफिक को कम करने के लिए 2948.72 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
- श्री अमरनाथ यात्रा को सुगम बनाने के लिए कई तरह के कदम उठाए गए हैं, ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कत न हो।
- जम्मू-रोपवे का काम पूरा हो चुका है और इसके दूसरे चरण के तहत बाबे-बाहु खंड तक का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है।
- केंद्र की योजना 'प्रसाद' के तहत, दरगाह हज़रतबल में पर्यटक प्रस्तुतीकरण केंद्र (टूरिस्ट इंटरप्रिटेशन सेंटर) का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है।
- केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर केंद्रशासित क्षेत्र के औद्योगिक विकास के लिए 19 फरवरी 2021 को नई योजना की शुरुआत की थी, जिस पर कुल 28,400 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसका मकसद जम्मू-कश्मीर के औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। इस योजना से 4.5 लाख लोगों को रोज़गार मिलने की संभावना है।
- स्वच्छ भारत मिशन के तहत जम्मू-कश्मीर को खुले में शौच की समस्या से मुक्त कर दिया गया है।
- सौभाग्य, उजाला, उज्ज्वला और इंद्रधनुष समेत केंद्र की कुल 17 व्यक्तिगत लाभार्थी योजनाओं में सफलता का शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल कर लिया गया है।
- वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान 1,638 करोड़ रुपये की लागत से कुल 1,289 सड़कों का निर्माण कार्य पूरा हुआ। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत अब तक 14,500 किलोमीटर सड़कों का निर्माण पूरा हो चुका है। इसके तहत, 2,000 जगहों को बेहतर सड़कों से जोड़ा गया है।
- 23 अक्टूबर 2021 को श्रीनगर से शारजाह की अंतरराष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू की गई। इसके अलावा, जम्मू और श्रीनगर से रात्रिकालीन उड़ान सेवाएं भी शुरू की गई हैं।
- सेब के लिए शुरू की गई उच्च-घनत्व पौधारोपण योजना का दायरा बढ़ाकर अब इसमें आम, लीची, चेरी, काजू आदि फलों को भी शामिल किया गया है। कश्मीरी केसर को जीआई टैग दिया गया है।
- फास्ट ट्रैक भर्ती के तहत, जम्मू-कश्मीर के विभिन्न विभागों में 26,330 पदों की पहचान की गई है। इन पदों के लिए भर्ती अभियान चलाया जा रहा है। फिलहाल, 11,324 पदों के लिए चयन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।

जम्मू-कश्मीर केंद्रशासित क्षेत्र में साल 2019 से अब तक विभिन्न क्षेत्रों/योजनाओं के तहत कुल 1,41,815 कार्यों/परियोजनाओं को शुरू किया गया है। इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 27,274 करोड़ रुपये का फंड आवंटित किया गया है। परियोजनाओं से जुड़ी निर्माण और अन्य तरह की गतिविधियों से बड़े पैमाने पर रोज़गार के अवसर पैदा हो रहे हैं। कौशल से लैस कर्मचारियों के अलावा अकुशल मजदूरों, छोटे कारोबारियों, माल ढुलाई करने वालों, इंजीनियरों और अलग-अलग तरह की सामग्री की आपूर्ति करने वालों को भी इसका फायदा मिल रहा है। एक अनुमान के मुताबिक, इस निवेश से 1,169 लाख श्रम दिन का रोज़गार सृजित हुआ। आधारभूत संरचना से जुड़े क्षेत्रों की स्थिति के बारे में नीचे बताया गया है:

1. **पीएमडीपी-2015** – जम्मू-कश्मीर केंद्रशासित क्षेत्र में पीएम विकास पैकेज 2015 के तहत चल रही परियोजनाओं पर काम तेज़ हुआ है। सड़क, ऊर्जा, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, कृषि, कौशल विकास जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 58,477 करोड़ की लागत से कुल 53 परियोजनाओं को लागू किया जा रहा है। ये परियोजनाएं 15 मंत्रालयों से संबंधित हैं। इनमें से 25 परियोजनाएं ऐसी हैं जो पूरी हो चुकी हैं या पूरी होने के करीब हैं।
2. **देरी से चल रही परियोजनाएं**- इस श्रेणी में आने वाली कुल 1,193 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं जिनकी कुल लागत 1,984 करोड़ रुपये हैं। इनमें से 5 परियोजनाएं ऐसी थीं जो 20 साल से भी ज्यादा से अटकी पड़ी थीं। इसके अलावा, 15 परियोजनाएं 15 साल से भी ज़्यादा से लंबित थीं और 165 परियोजनाएं 10 साल से भी ज्यादा से अटकी थीं।

Scanned with OKEN Scanner

सारणी 1: जम्मू-कश्मीर केंद्रशासित क्षेत्र में आधारभूत संरचना की स्थिति (सड़क और ऊर्जा)

विवरण	2019 से पहले की स्थिति	मौजूदा स्थिति
	1. सड़क	
सड़कों की लंबाई	39,345 किलोमीटर	43,141 किलोमीटर
तारकोल वाली सड़कों का %	66%	74%
सड़कों का औसत निर्माण	6.54 किलोमीटर प्रति दिन	20.68 किलोमीटर प्रति दिन
गड्ढों की मरम्मत के लिए योजना	नहीं	सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने से जुड़े अभियान पर काम किया गया। 2021-22 के लिए 5,900 किलोमीटर सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने का लक्ष्य तय किया है (4,600 किलोमीटर का लक्ष्य हासिल किया जा चुका है)।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत एक साल में सड़कों का निर्माण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के मामले में राष्ट्रीय स्तर पर रैंक	1,622 किलोमीटर 12वीं रैंक	2,127 किलोमीट चौथी रैंक
श्रीनगर-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग ट्रकों के लिए लगने वाला औसत समय यात्रियों को लगने वाला औसत समय	24-72 घंटे 7-12 घंटे	12 घंटे से कम 5.50 घंटे
जम्मू-डोडा यात्रा में लगने वाला समय	5.50 घंटे	3.50 घंटे
जम्मू-किस्तवार यात्रा में लगने वाला समय	7.50 घंटे	5.00 घंटे
चेनाब नदी पर 1,315 मीटर लंबे रेल पुल का निर्माण, ताकि कश्मीर को ट्रेन की सुविधा मिल सके		काम पूरा होने के लिए तय की गई तारीख सितंबर 2022
अन्य उपलब्धियां		• 2022 में राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ी 4 परियोजनाएं पूरी हो रही हैं। • दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेसवे पर काम चल रहा है। • सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने भारत माला के तहत, 10 नई सड़क/सुरंग परियोजनाओं पर सहमति जताई है।
विवरण	**2019 से पहले की स्थिति**	**मौजूदा स्थिति**
	2. ऊर्जा	
जल विद्युत (क्षमता निर्माण)	3,505 मेगावाट	अगले 5 साल में 21 जल विद्युत परियोजनाओं को पूरा किया जाना है, जिनकी कुल क्षमता 5,186 मेगावाट है। प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं में पाकलडल, किरु, क्वार, उरी (दूसरा चरण), दुलहस्ती (दूसरा चरण), स्वालकोटे, किरथई-2 और रतल परियोजनाएं शामिल हैं।
ट्रांसमिशन प्रणाली ट्रांसमिशन क्षमता 220 केवी 132 केवी	8,234 एमवीए 804 सीकेएमएस 1,955 सीकेएमएस	10,264 एमवीए 1,220 सीकेएमएस 2,265 सीकेएमएस
वितरण प्रणाली रूपांतरण क्षमता एचटीलाइन लैंथ एलटीलाइन लेंथ	12,745 एमवीए 41,204 सीकेएम 79,754 सीकेएम	16,574 एमवीए 45,101 सीकेएम 96,017 सीकेएम (सीकेएम-सर्किल किलोमीटर)
पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना		तकनीकी नुकसान, बिजली चोरी आदि रोकने और चौबीस घंटे बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 'पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना' और 11,767 करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई।

3. **स्वास्थ्य**- हाल में 2 नए एम्स, 7 नए मेडिकल कॉलेज, 2 राज्य स्तरीय कैंसर संस्थान और 15 नर्सिंग कॉलेजों को चालू किया गया है। मेडिकल कॉलेजों में 854 सीटें बढ़ाई गईं, जिनमें एमबीबीएस कोर्स में 600 सीटें, पीजी कोर्स में 50 सीटें, बीडीएस में 26 सीटें, एमडीएस में 38 सीटें और डीएमबी में 140 सीटें बढ़ाई गई हैं।

4. **जल जीवन मिशन**- पहले जहां कुल 5.75 लाख घरों (31 प्रतिशत) में पानी की कनेक्शन था, वहीं अब कुल 10.55 लाख घरों (57 प्रतिशत) में पानी का कनेक्शन है। दो जिलों (श्रीनगर और गांदरबल) को हर घर जल जिला भी घोषित किया जा चुका है। सभी ग्रामीण स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों और स्वास्थ्य संस्थानों में पानी का कनेक्शन उपलब्ध कराया गया है।

5. **सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण**- तीन अहम सिंचाई परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। इसके तहत, मुख्य रावी नहर (लागत 62 करोड़ रुपये) परियोजना, त्राल लिफ्ट सिंचाई परियोजना (लागत 45 करोड़ रुपये) के तीसरे चरण और झेलम और उसकी सहायक नदियों से जुड़ी बाढ़ प्रबंधन योजना के पहले चरण को पूरा किया गया है।

6. **शिक्षा**- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), जम्मू और भारतीय प्रबंधन संस्थान, जम्मू का संचालन शुरू हो गया है। सरकारी डिग्री कॉलेजों/इंजीनियरिंग कॉलेजों की संख्या बढ़कर 96 से 147 हो गई हैं। ■

स्रोत: पत्र सूचना कार्यालय

Scanned with OKEN Scanner

सतत पर्यटन

अविनाश मिश्रा
मधुबंती दत्ता

भारत पारिस्थितिकीय दृष्टि से सर्वाधिक विविधताओं वाले देशों में से एक है, जिसमें शानदार पहाड़, महासागर, आकर्षक रेगिस्तान और समृद्ध वन शामिल हैं। ऐसी ही एक खास जगह अत्यंत ऊँचाई पर स्थित लद्दाख का रेगिस्तान है, जिसे आमतौर पर 'मून लैंड' कहा जाता है, जो भारत के सबसे उत्तरी दूरस्थ स्थान में स्थित है। यह स्थान बेहद ऊँचे पहाड़ों और ठंडे रेगिस्तानी मैदानों के जादुई परिदृश्य में स्थित कुछ अत्यंत खूबसूरत और प्राचीन मठों के लिए विख्यात है। लद्दाख अपने स्थान और सुदूरता के कारण पारिस्थितिकीय दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील जगह है, जो अपने पर्यटन उद्योग से लाभ प्राप्त करता है।

अविनाश मिश्रा नीति आयोग में सलाहकार (प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन प्रभाग, पर्यटन एवं संस्कृति) हैं। ईमेल: amishra-pc@gov.in
मधुबंती दत्ता नीति आयोग में यंग प्रोफेशनल हैं। ईमेल: dutta.madhubanti@gov.in

Scanned with OKEN Scanner

रोज़गार के अवसरों और बड़े पैमाने पर आमदनी का सृजन करने के सामर्थ्य के कारण पर्यटन को लद्दाख जिले में एक महत्वपूर्ण उद्योग के रूप में व्यापक पहचान प्राप्त है। ज़िले के सामाजिक-आर्थिक क्षेत्र पर पर्यटन क्षेत्र का प्रत्यक्ष प्रभाव है। परिवहन, आवास, खानपान, कुटीर उद्योग आदि जैसे सम्बन्धित उद्योगों में काम करने वाले बहुत से अन्य लोगों को पर्यटन व्यवसाय में काम करने के अवसर मिलते हैं लेकिन, दुर्भाग्यवश, इसकी वजह से इस संवेदनशील पारिस्थितिकीय तंत्र के प्राकृतिक संसाधनों पर बहुत दबाव पड़ता है।

इसे और गति देने के लिए, जलवायु परिवर्तन का अत्यधिक प्रभाव भी यहां लोगों की जान को बहुत बड़े जोखिम में डाल रहा है। पिछले दो दशकों में यहां के ग्लेशियर बहुत तेजी से पिघल रहे हैं तथा हिमपात में यकायक और हैरतंगेज रूप से कमी आई है। वर्षा भी अविश्वसनीय रूप से अनियमित हो गई है। लेह लद्दाख क्षेत्र में बादल फटने के कारण अचानक आने वाली बाढ़ भी लद्दाख के दीर्घकालिक टिकाऊ होने पर संदेह उत्पन्न कर रही है। लद्दाख सरकार ने पर्यावरण की रक्षा, कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने और हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को बरकरार रखने के लक्ष्य के साथ अपशिष्ट प्रबंधन का कार्य आरंभ किया है।

केंद्र सरकार साहसिक, संस्कृति और जिम्मेदार पर्यटन के पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए लद्दाख को पर्यटक स्थल बनाने की दिशा में काम कर रही है। पर्यटन मंत्रालय के अंतर्गत 'स्वदेश दर्शन' और 'प्रसाद' योजनाओं के तहत जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लिए 594 करोड़ रुपये की सात परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।[1] यह कदम लद्दाख को स्थानीय समुदाय के लिए स्थायी और समावेशी विकास को बढ़ावा देने वाला अत्यंत महत्वपूर्ण, पारिस्थितिकीय दृष्टि से सतत पर्यटक स्थल (लो-इम्पैक्ट टूरिज्म) बनाएगा। यह बात ध्यान में रखना होगी कि पर्यटन की प्रकृति टिकाऊ होनी चाहिए तथा व्यवस्थित और नियंत्रित पर्यटन के माध्यम से इसका स्थानीय पारिस्थितिकी और आबादी पर न्यूनतम नकारात्मक प्रभाव होना चाहिए। लद्दाख में पर्यटन को प्रोत्साहन देने का उद्देश्य स्थानीय लोगों के लिए रोज़गार के अवसरों का सृजन करना तथा भारत और शेष विश्व के पर्यटकों के बीच लद्दाख की संस्कृति और उत्पादों को बढ़ावा देना है। विकास के नए अवसरों, कनेक्टिविटी, बुनियादी सुविधाओं तथा टिकाऊ और समुदाय-आधारित विकास पर ध्यान देते हुए लद्दाख के पर्यटन उद्योग को समग्र रूप से विकसित किया जाना बहुत आवश्यक है। यहाँ अवसर और चुनौतियाँ अपार हैं, जो लेह में साहसिक पर्यटन रूप में मौजूद हैं, नई संभावनाओं के द्वार खोलने तथा स्थानीय समुदाय और विशेषकर महिलाओं को सशक्त बनाने आदि का सामर्थ्य होमस्टे पर्यटन में मौजूद हैं।[2]

जम्मू, कश्मीर और लद्दाख तीन अलग-अलग क्षेत्र हैं, जो मिलकर केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख का निर्माण करते हैं। इन तीनों क्षेत्रों में देशी और विदेशी पर्यटकों की बदौलत पर्यटन की अपार

भांड पाथेर कश्मीर की लोककला

संभावनाएं मौजूद हैं। इसका प्रभाव परिवहन, आतिथ्य, बागवानी, हस्तशिल्प और छोटे पैमाने पर विनिर्माण जैसे सेवा क्षेत्र के उद्योगों में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। कश्मीर को अक्सर 'धरती पर स्वर्ग' की उपमा दी जाती है और यह लंबे अर्से से एक प्रमुख पर्यटन स्थल रहा है। प्राकृतिक सौंदर्य की प्रचुरता के कारण इसे 'पूर्व का स्विट्जरलैंड' भी कहा जाता है। इसकी बर्फ से ढकी चोटियां, नदियां और मीठे पानी की झीलें आगंतुकों के लिए हाइकिंग, राफ्टिंग, स्कीइंग और पर्वतारोहण के भरपूर अवसर प्रदान करती हैं।

ऐसे उत्पाद बहुतायत में हैं, जिन्हें जम्मू और कश्मीर राज्य में खरीदा जा सकता है। राज्य के प्रत्येक जिले में आगंतुकों के लिए प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधन, साहसिक पर्यटन (जैसे रिवर राफ्टिंग और पर्वतारोहण), अनेक ट्रेकिंग रूट, तीर्थयात्रा पर्यटन, वन्यजीव पर्यटन, विरासत पर्यटन, जातीय खाद्य उत्सव और सांस्कृतिक कार्यक्रम, हस्तशिल्प आदि सहित बहुत कुछ मौजूद है।

हालांकि, पर्यटन में अभूतपूर्व वृद्धि ने इस स्थान पर 'अति-पर्यटन' (यानी ओवर टूरिज्म) को जन्म दिया है, जिसका प्राकृतिक संसाधनों, सांस्कृतिक विरासत और जीवन की गुणवत्ता पर तत्काल नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस जागरुकता ने दुनिया भर में सतत पर्यटन के बारे में चर्चाओं में वृद्धि की है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कियदि खराब प्रबंधन वाले 'अति-पर्यटन' को संभावित जोखिम के रूप में देखा जा रहा है, तो पर्यटन को बहुधा संचालित करने वाली गतिशील ताकतों का नकारात्मक प्रभाव अपरिहार्य हो जाता है। एक सतत संरचना में, पर्यटन के आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक-सांस्कृतिक परिणामों के बीच संतुलन होना चाहिए।

ऐसे उत्पाद बहुतायत में हैं, जिन्हें जम्मू और कश्मीर राज्य में खरीदा जा सकता है। राज्य के प्रत्येक जिले में आगंतुकों के लिए प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधन, साहसिक पर्यटन (जैसे रिवर रॉफ्टिंग और पर्वतारोहण), अनेक ट्रेकिंग रूट, तीर्थयात्रा पर्यटन, वन्यजीव पर्यटन, विरासत पर्यटन, जातीय खाद्य उत्सव और सांस्कृतिक कार्यक्रम, हस्तशिल्प आदि सहित बहुत कुछ मौजूद है।

यूएनडब्ल्यूटीओ के अनुसार, सतत पर्यटन:

- महत्वपूर्ण पारिस्थितिकीय प्रक्रियाओं को बरकरार रखते हुए तथा प्राकृतिक विरासत और जैव विविधता के संरक्षण में सहायता देते हुए, पर्यटन के विकास के लिए महत्वपूर्ण पर्यावरणीय संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करता है;
- मेजबान समुदायों की सामाजिक-सांस्कृतिक प्रामाणिकता का सम्मान करता है, उनकी निर्मित और सजीव सांस्कृतिक

Scanned with OKEN Scanner

विरासत और पारम्परिक मूल्यों को संरक्षित करता है, और अंतरसांस्कृतिक समझ और सहिष्णुता को बढ़ावा देता है।

- दीर्घकालिक आर्थिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करता है, स्थायी रोज़गार और आय के सृजन के अवसरों सहित सभी हितधारकों को संतुलित तरीके से सामाजिक-आर्थिक लाभ वितरित करता है, मेजबान समुदायों के लिए सामाजिक सेवाओं और गरीबी में कमी लाने में सहायता करता है।

लद्दाख जैसे स्थानों में पर्यटन उद्योग प्राचीन प्राकृतिक स्थान की छवि प्रस्तुत करने पर निर्भर करता है, लेकिन इन क्षेत्रों में आने वाले अधिकांश आगंतुक इसके संवेदनशील पारिस्थितिकीय तंत्र और सांस्कृतिक संवेदनशीलता के प्रति बहुत कम सम्मान दिखाते हैं। हर साल, वे टनों कचरा उत्पन्न करते हैं, पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य को खतरे में डालने के साथ ही साथ ऐसे स्थान की सुंदरता को बर्बाद कर देते हैं। वर्तमान समय में ऐसी रणनीति अपनायी जानी चाहिए जो प्रदूषण के खतरे और पर्यावरणीय क्षरण के जोखिम में पर्याप्त कमी लाए और पर्यटन का विकास वहन करने की क्षमता पर आधारित हो।

उच्च गुणवत्ता सम्पन्न पर्यटन और वन्यजीव संरक्षण की क्षमता का दोहन वैज्ञानिक समझ और कुशल योजना के माध्यम से किया जाना अभी बाकी है। लद्दाख का परिदृश्य मुख्य रूप से चरागाहों/घास के मैदानों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जो पशुपालन उत्पादों पर निर्भर जातीय समुदायों के घर हैं।

उच्च गुणवत्ता सम्पन्न पर्यटन और वन्यजीव संरक्षण की क्षमता का दोहन वैज्ञानिक समझ और कुशल योजना के माध्यम से किया जाना अभी

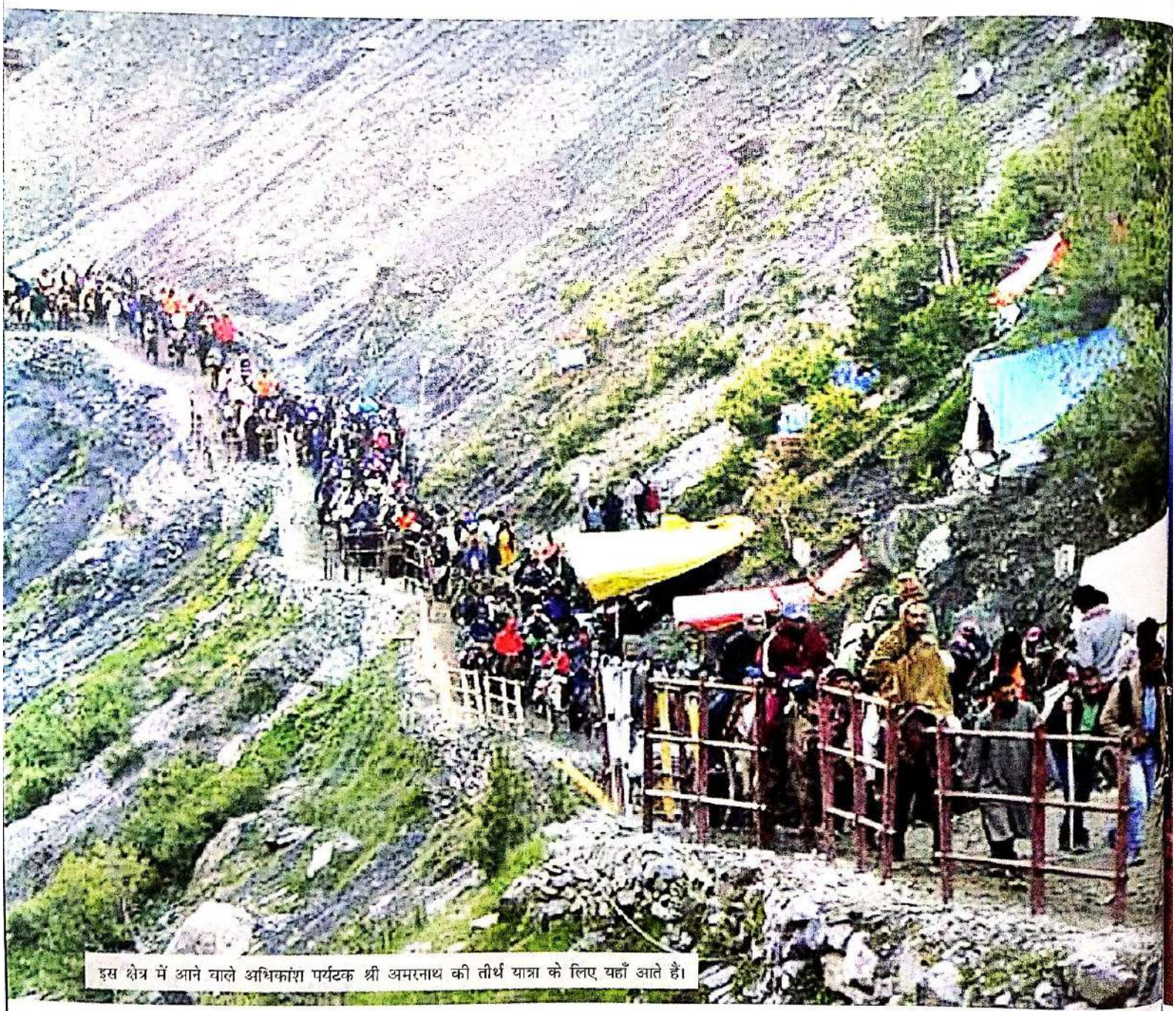

इस क्षेत्र में आने वाले अधिकांश पर्यटक श्री अमरनाथ की तीर्थ यात्रा के लिए यहाँ आते हैं।

Scanned with OKEN Scanner

बाकी है। लद्दाख का परिदृश्य मुख्य रूप से चरागाहों/घास के मैदानों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जो पशुपालन उत्पादों पर निर्भर जातीय समुदायों के घर हैं। इसलिए, ये चरागाह प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्यों के समूह को दर्शाते हैं। हालांकि इन परिदृश्यों के विभिन्न घटकों के नाजुक अंतर्संबंधों को उचित रूप से समझे बिना, पर्यटन का त्वरित विकास लद्दाख के इन विलक्षण घास के मैदानों के पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित कर सकता है।

लद्दाख क्षेत्र की विशिष्टता और संवेदनशीलता की विशेषताओं को देखते हुए पर्यटक विकास का फोकस पर्यटन की गुणवत्ता और स्थानीय समुदायों सहित विभिन्न हितधारकों के बीच पर्यटन से होने वाली आय में समानता पर हो सकता है।

लद्दाख परिदृश्य के इन क्षेत्रों में पर्यटन के विकास के लिए निरंतरता की संभावनाओं पर विचार करना महत्वपूर्ण है। सामाजिक-सांस्कृतिक विरासत के लिए खतरा, सीमित संसाधनों का गहन उपयोग और बाकी स्थानों की ही तरह नकारात्मक बाह्यता के यहां भी कई अन्य हानिकारक प्रभाव हो सकते हैं, जैसे कि पारम्परिक पर्यावरण के अनुकूल और सौंदर्य की दृष्टि से आकर्षक वास्तुकला को अनुचित, संसाधनों के अतिशय इस्तेमाल वाले और खतरनाक निर्माणों, खराब डिजाइन वाली सड़कों और अन्य सम्बन्धित बुनियादी सुविधाओं, अपर्याप्त ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, बढ़े हुए वायु प्रदूषण, जल स्रोतों में गिरावट और जैविक विविधता के नुकसान से बदल देना। इसलिए, केवल ज्यादा से ज्यादा आगंतुकों को आकर्षित करने पर ही ध्यान केंद्रित करना सतत पर्यटन विकास का आधार नहीं हो सकता, खासकर तब, जबकि क्षेत्र की वहन क्षमता सीमित हो। लद्दाख क्षेत्र की

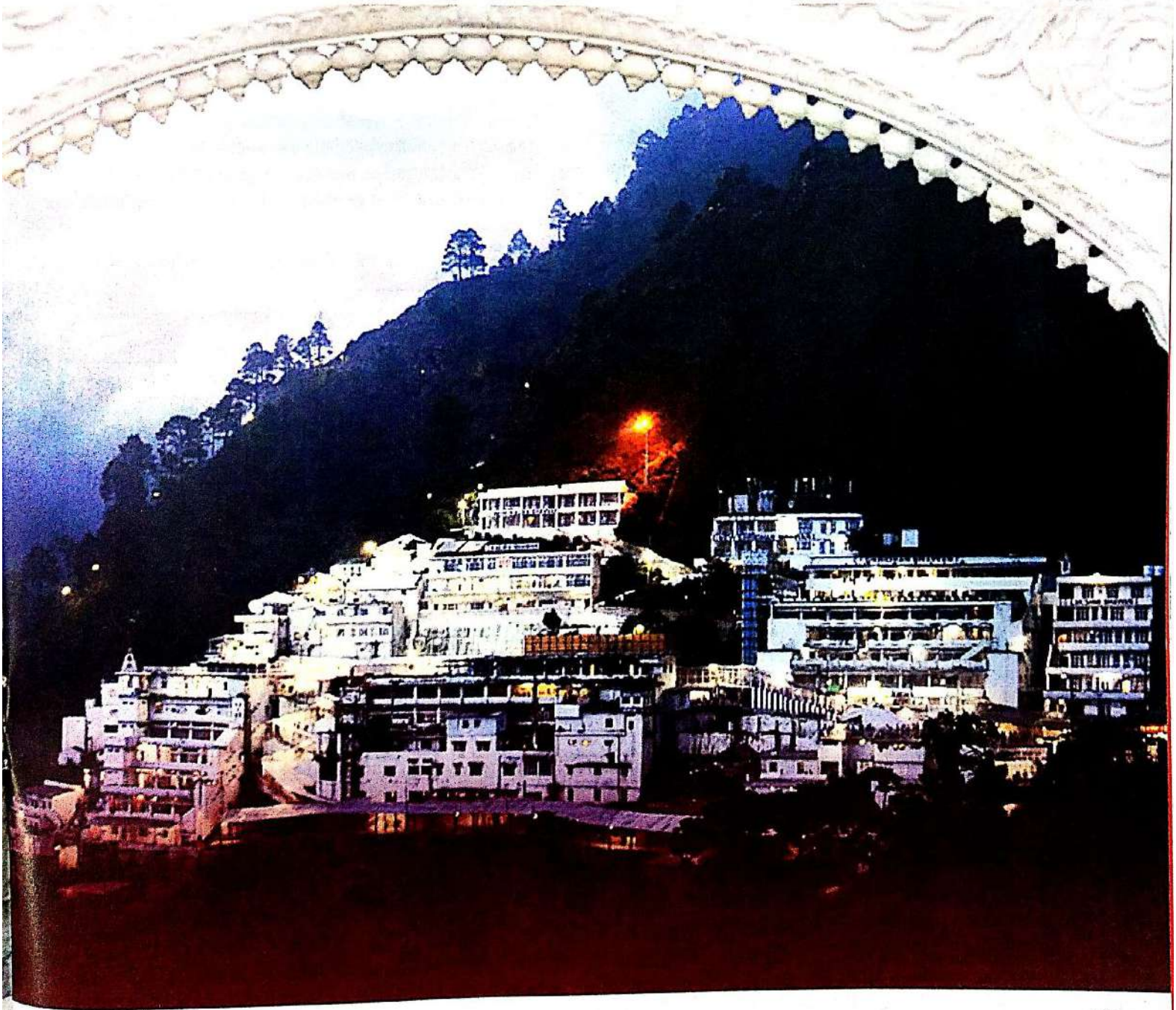

Scanned with OKEN Scanner

लद्दाख का परिदृश्य मुख्य रूप से चरागाहों/घास के मैदानों द्वारा दर्शाया गया है, जो पशुपालन उत्पादों पर निर्भर जातीय समुदायों के घर हैं।

विशिष्टता और संवेदनशीलता की विशेषताओं को देखते हुए पर्यटक विकास का फोकस पर्यटन की गुणवत्ता और स्थानीय समुदायों सहित विभिन्न हितधारकों के बीच पर्यटन से होने वाली आय में समानता पर हो सकता है।[3]

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को 'इको-टूरिज्म हॉटस्पॉट' के रूप में विकसित करने के दिशा में कड़ा परिश्रम करना होगा, क्योंकि अनियंत्रित पर्यटन जलवायु परिवर्तन के कारण उपजे पारिस्थितिकीय असंतुलन में योगदान देता है। पारिस्थितिकीय पर्यटन या इकोटूरिज्म प्राचीन क्षेत्रों की नीतिपरक यात्रा (इथिकल ट्रैवल) है, जो पर्यावरण की रक्षा करती है, सामुदायिक विकास को बढ़ावा देती है तथा स्थानीय लोगों और आगंतुकों दोनों को शिक्षित करती है। यह केंद्र शासित प्रदेश उत्सर्जित किए गए कार्बन से अधिक मात्रा में कार्बन को अवशोषित करने और वैश्विक ग्रीनहाउस गैसों के लिए नेट सिंक होने का संकल्प लेने वाले भूटान[4] के साथ ही साथ अन्य पर्यटक हॉटस्पॉट्स से जानकारी एकत्र कर सकता है। उदाहरण के लिए, आगंतुकों की संख्या सीमित करने, पर्यावरण के अनुकूल उच्च गुणवत्ता वाली इको-लॉज का निर्माण करने और विदेशी वन्यजीवों के अवैध शिकार में कमी लाने, जैसे कदम संभवतः इन क्षेत्रों में विकास और पर्यटन को बढ़ाने की दिशा में बनाए जाने वाले कड़े नियमों और दिशानिर्देशों का हिस्सा हो सकते हैं। निरंतरता की दिशा में इन संतुलित प्रयासों को अपनाकर हम प्राकृतिक पर्यावरण और पारिस्थितिकी की रक्षा करके इन स्थानों की सुंदरता को बरकरार रख सकते हैं। ■

संदर्भ

1. https://pib.gov.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=198957
2. https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1749257
3. सस्टेनेबिलिटी ऑफ़ टूरिज्म इन लद्दाख: एक्शन प्वाइंट्स – रिव्यू, रिकमेंडेशन्स एं एक्शन एजेंडा
4. इमेजिंग इन्क्रेडिबल इंडिया : सेविंग लद्दाख थ्रू सस्टेनेबिलिटी-क्लाइमेट चेंज चैलेंज।

Scanned with OKEN Scanner

आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर सभी देश

स्वतंत्रता दिवस की हार्दि

आने वाले 25 वर्षों का अमृतकाल, हर
मिलकर बनाएं स्वतंत्रता सेनानियों के

"स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कृतज्ञ देशवासी अपने अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हैं। जैसे देश की आज़ादी के मतवाले, स्वतंत्रता के लिए एकजुट हो गए थे, वैसे ही हमें देश के विकास के लिए एकजुट होना है।"

- नरेन्द्र मोदी

#HarGharTiranga

cbc 22201/13/0101/2223

YH-2047/2022

Scanned with OKEN Scanner

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार

आज़ादी का अमृत महोत्सव

शवासियों को
क शुभकामनाएं

र देशवासी का कर्तव्यकाल
क सपनों का भारत

Scanned with OKEN Scanner

शिक्षा और कौशल विकास

पद्मा आंग्मो

लद्दाख अपनी विशिष्ट भौगोलिक स्थिति, स्थलाकृति, संस्कृति, इतिहास और प्राकृतिक विरासत की वजह से एक अनूठा क्षेत्र है। कठिन भूगोल, साल में लगभग चार महीनों तक चलने वाली बर्फानी सर्दी, दूरदराज के गाँव, विस्तृत क्षेत्र में फैली विरल आबादी, अवसंरचनाओं की कमी और योग्य मानव संसाधन की तंगी इस संघ शासित क्षेत्र में विकास की किसी भी पहल के लिये चुनौतियां हैं। लद्दाख के युवाओं को शिक्षा, कौशल विकास, नवोन्मेष और उद्यमिता के जरिये प्रगति में उत्प्रेरक बनाया जाना आवश्यक है।

लद्दाख को 2019 में संघ शासित क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया। इसके बाद से अनूठे प्राकृतिक संसाधनों, बेहतरीन पर्यावरण और मिलनसार आबादी वाले इस क्षेत्र के लिये प्रचुर अवसरों के द्वार खुल गये हैं। केंद्र सरकार से मिल रहे धन तथा केंद्रीय और संघ शासित क्षेत्र स्तरीय नेतृत्व के प्रयासों ने लद्दाख प्रशासन को अवसर दिया है कि वह इस शांत और बेहद खूबसूरत क्षेत्र में विकास का एक विशिष्ट मॉडल तैयार कर लागू करे।

विकास के किसी भी मॉडल के लिये प्रशासन की योजना में युवाओं की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। लिहाजा, लद्दाख के युवाओं को जरूरी कौशलों और क्षमता से लैस करना महत्वपूर्ण है ताकि वे एक अनुकरणीय मॉडल पेश करते हुए क्षेत्र को विकास के पथ पर आगे ले जा सकें। लद्दाख में 2019-20 में 18 से 23 वर्ष तक के युवाओं की आबादी 36588 थी।[1] मौजूदा समय में इनमें से लगभग 3938 युवा महाविद्यालयों, पॉलीटेकनिक कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे हैं। इसके अलावा लद्दाख के लगभग इतने ही युवा इस संघ शासित क्षेत्र के बाहर उच्चतर शिक्षा संस्थानों में अध्ययनरत हैं। देखा गया है कि लद्दाख के बाहर पढ़ने वाले स्थानीय युवा लौट कर सरकारी नौकरियों तथा पर्यटन और इससे सम्बन्धित उद्योगों में लग जाते हैं। लद्दाख में उद्योगों की मौजूदगी बहुत कम है। इसलिये युवाओं की वापसी से इस संघ शासित क्षेत्र के सीमित रोज़गार बाजार पर दबाव बढ़ता है। लेकिन ये शिक्षित युवा अपने साथ अनुभव, विचार और उद्यमिता भी लाते हैं जिससे क्षेत्र को नये अवसरों के इस्तेमाल में मदद मिल सकती है।

लद्दाख प्रशासन ने पिछले ढाई वर्षों में इस जनसांख्यिकीय लाभ का उपयोग करने पर ध्यान केंद्रित किया है। वह युवाओं के क्षमता निर्माण के लिये प्रयासरत है ताकि वे क्षेत्र के संवहनीय विकास में सक्रिय योगदान कर सकें।

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और मददगार अवसंरचना

लद्दाख में गुणवत्तापूर्ण उच्चतर शिक्षा पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। लद्दाख विश्वविद्यालय की स्थापना 2019 में की गयी और इसके अंतर्गत लेह, कारगिल, नुबरा, जंस्कार, खालसी और द्रास के छह महाविद्यालय आते हैं। वर्तमान में इस विश्वविद्यालय में 22 विभाग हैं तथा अपराध विज्ञान, पुलिस प्रशासन और शारीरिक शिक्षा जैसे विशिष्ट विषयों की भी पढ़ाई की जा रही है। लद्दाख विश्वविद्यालय ने छात्र आदान-प्रदान कार्यक्रमों, संकाय विकास, अनुसंधान में सहयोग और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने के लिये अन्य संस्थानों के साथ 16 करार किये हैं। इन संस्थानों में दिल्ली विश्वविद्यालय, डेनिश कंसॉर्टियम फॉर एकैडमिक क्राफ्ट्समैनशिप, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी और राष्ट्रीय अपराध विज्ञान यूनिवर्सिटी शामिल हैं। लद्दाख विश्वविद्यालय के दो परिसरों में नये संकाय और प्रयोगशाला खंडों, खेल अवसंरचना, सभागार तथा कर्मचारी आवासों का निर्माण कर उनका विस्तार किया जा रहा है।

महाविद्यालयों में भी अवसंरचना को मजबूत किया जा रहा है ताकि वे छात्रों की बढ़ती संख्या की जरूरतों को पूरा कर सकें।

लेखिका संघ शासित क्षेत्र लद्दाख में उच्चतर और तकनीकी शिक्षा तथा कौशल विकास की आयुक्त/सचिव हैं। ईमेल: padmaangmo.iis@ladakh.gov.in

Scanned with OKEN Scanner

संकाय विकास और छात्रों के आदान-प्रदान के कार्यक्रमों तथा अतिथि शिक्षकों के जरिये शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार किया जा रहा है। नुबरा और जंस्कार के महाविद्यालयों में दो खंड थे जिनका निर्माण तत्कालीन जम्मू-कश्मीर राज्य के उच्चतर शिक्षा विभाग ने कराया था। सबसे बाद में स्थापित खालसी और द्रास महाविद्यालयों में कोई अवसंरचना नहीं थी। लद्दाख प्रशासन ने इन महाविद्यालयों की अवसंरचनाओं में सुधार का बीड़ा उठाया है। सिर्फ लेह के महाविद्यालय में 24 लड़कियों के लिये एक छात्रावास था। इसलिये सबसे पहले सभी महाविद्यालयों में लड़कों और लड़कियों के लिये छात्रावासों के निर्माण पर ध्यान दिया गया है। भारत सरकार ने नये संघ शासित क्षेत्र लद्दाख के लिये विशेष विकास पैकेज दिया है। इसके तहत 2021-22 में महाविद्यालयों के लिये लगभग 200 करोड़ रुपये की अवसंरचना परियोजनाएं मंजूर की गयी हैं। ये परियोजनाएं छात्रावासों, पुस्तकालयों, बहुउद्देश्यीय कक्षों और खेल के मैदानों के निर्माण से सम्बन्धित हैं और इनमें कार्य शुरू हो चुका है। ये सभी निर्माण लद्दाख के लिये कार्बन निरपेक्ष दृष्टिकोण के अनुरूप ऊर्जा के न्यूनतम इस्तेमाल वाले हैं। इन्हें दिव्यांग छात्रों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है। लद्दाख प्रशासन ने 2022-23 को दिव्यांगजन वर्ष घोषित किया है।

इस संघ शासित क्षेत्र में पिछले दो वर्षों में महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में दाखिलों में ज़बरदस्त वृद्धि हुई है। शासकीय महाविद्यालय कारगिल में छात्रों की संख्या नियंत्रित करने के मकसद से 2022 में इसकी एक शाखा संकू में शुरू की गयी। इस शाखा को शुरू किये जाने का उद्देश्य संकू सब डिवीजन की बढ़ती मांग को पूरा करना था। इस परिसर में पहले वर्ष में 51 छात्रों ने दाखिला लिया। प्रशासन ने इस सबडिवीजन के छात्रों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अब इसमें एक नये कॉलेज की स्थापना का प्रस्ताव किया है।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में 2021 में सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की थी। इस विश्वविद्यालय का निर्माण खालसी में 110 एकड़ भूमि पर किया जा रहा है। यह विश्वविद्यालय लद्दाख के युवाओं को देश के अन्य भागों और विदेश के युवाओं के साथ अध्ययन का अवसर प्रदान करेगा।

छात्रवृत्ति

लद्दाख प्रशासन ने छात्रों में मेधा और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2021 में रेवा योजना शुरू की। लद्दाखी शब्द रेवा का अर्थ उम्मीद होता है। इस योजना के अंतर्गत कक्षा 10 और 12 के मेधावी छात्रों को एक लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जाती है चाहे उनकी पारिवारिक आय कितनी भी हो। छात्र इस धन का इस्तेमाल एनईईटी, जेईई, यूजी सीएलएटी और एनडीए जैसी राष्ट्र स्तरीय परीक्षाओं के लिये कोचिंग में कर सकते हैं। इस साल हर जिले से दसवीं के लगभग 30 और बारहवीं कक्षा के 35 छात्रों को यह छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी।

देखा गया है कि लद्दाख के बाहर पढ़ने वाले स्थानीय युवा लौट कर सरकारी नौकरियों तथा पर्यटन और इससे सम्बन्धित उद्योगों में लग जाते हैं। लद्दाख में उद्योगों की मौजूदगी बहुत कम है। इसलिये युवाओं की वापसी से इस संघ शासित क्षेत्र के सीमित रोज़गार बाजार पर दबाव बढ़ता है। लेकिन ये शिक्षित युवा अपने साथ अनुभव, विचार और उद्यमिता भी लाते हैं जिससे क्षेत्र को नये अवसरों के इस्तेमाल में मदद मिल सकती है।

रेवा योजना के तहत सिविल सेवा, इंजीनियरी सेवा और वन सेवा जैसी परीक्षाओं के प्रारंभिक चरण में उत्तीर्ण छात्रों को भी 1.54 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जाती है। छात्र इस रकम का इस्तेमाल इन प्रतियोगिता परीक्षाओं के मुख्य चरण की कोचिंग के लिये कर सकते हैं। सिविल सेवा परीक्षा 2021 के प्रारंभिक चरण में उत्तीर्ण दो छात्रों को यह छात्रवृत्ति दी गयी है।

लद्दाख के लगभग 9363 छात्रों ने 2021-22 में अल्पसंख्यक और जनजातीय मामले मंत्रालयों की मैट्रिक पश्चात् छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत वजीफा हासिल किया।

Scanned with OKEN Scanner

इसके अलावा इस संघ शासित क्षेत्र के 347 छात्रों को प्रधानमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना के तहत वजीफा दिया गया। यह योजना लद्दाख और जम्मू-कश्मीर के उन छात्रों के लिये हैं जो इन संघ शासित क्षेत्रों के बाहर मान्यता प्राप्त संस्थानों में अध्ययन कर रहे हैं। योजना में शिक्षण शुल्क का भुगतान किये जाने के साथ ही प्रति वर्ष एक लाख रुपये तक के भत्ते का भी प्रावधान है।

इस संघ शासित क्षेत्र में पिछले दो वर्षों में महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में दाखिलों में ज़बरदस्त वृद्धि हुई है। शासकीय महाविद्यालय कारगिल में छात्रों की संख्या नियंत्रित करने के मकसद से 2022 में इसकी एक शाखा संकू में शुरू की गयी। इस शाखा को शुरू किये जाने का उद्देश्य संकू सबडिवीजन की बढ़ती मांग को पूरा करना था। इस परिसर में पहले वर्ष में 51 छात्रों ने दाखिला लिया। प्रशासन ने इस सब डिवीजन के छात्रों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अब इसमें एक नये कॉलेज की स्थापना का प्रस्ताव किया है।

आईआईटी के साथ सहयोग

लद्दाख के छात्रों को पहली दफा देश की प्रमुख शैक्षिक संस्था भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) में इंटर्नशिप और एमटेक करने का मौका मिला है। संघ शासित क्षेत्र लद्दाख के उच्चतर शिक्षा विभाग और आईआईटी समूह के बीच इस बारे में एक समझौता किया गया है।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्थानीय परिवेश को ध्यान में रखते हुए नवोन्मेष और उद्यमिता को बढ़ावा देना तथा रोज़गार के अवसर बढ़ाने के लिये युवाओं का कौशल विकास है। इसके तहत लद्दाख के 30 छात्र दिल्ली, मुंबई और कानपुर आईआईटी में दो महीनों की इंटर्नशिप कर सकते हैं। इसके अलावा इस संघ शासित क्षेत्र के 15 छात्रों को इन संस्थानों में छह महीनों की लंबी इंटर्नशिप का मौका मिलेगा। छात्रों को दो महीनों की इंटर्नशिप के लिये 15000 रुपये दिये जाते हैं। छह महीनों की इंटर्नशिप के लिये यह एकमुश्त रकम 50000 रुपये की होती है। इन छात्रों की संस्थान की फीस और छात्रावास के शुल्क का भुगतान लद्दाख प्रशासन करता है।

प्रायोजित एमटेक कार्यक्रम भी आईआईटी के साथ सहयोग का हिस्सा है। इसके तहत हर साल लद्दाख के 12 इंजीनियरी स्नातक इन तीन आईआईटी में एमटेक की पढ़ाई कर सकते हैं। इन छात्रों को प्रति माह 25000 रुपये का वजीफा दिया जायेगा। उनकी फीस और छात्रावास शुल्कों का भुगतान भी लद्दाख प्रशासन ही करेगा।

आईआईटी के कार्यक्रमों से लद्दाख के छात्रों को महत्वपूर्ण अनुभव प्राप्त होगा। साथ ही उन्हें विभिन्न अवसरों को तलाशने, अपना उद्यमिता कौशल विकसित करने तथा अनुसंधान और विकास के लिये नये रास्ते बनाने में मदद मिलेगी। पांच साल के लिये इन कार्यक्रमों को जून 2022 में शुरू किया गया है।

लद्दाख के छात्रों के लिये तकनीकी शिक्षा के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से कारगिल में एक इंजीनियरी महाविद्यालय खोलने का प्रस्ताव है। इसके पाठ्यक्रम को तैयार करने तथा अवसंरचना, सांगठनिक ढांचे और मानव संसाधन की जरूरतों के बारे में सलाह देने के लिये आईआईटी से संपर्क किया गया है। इसके जरिये यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि प्रस्तावित महाविद्यालय में गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा मिल सके।

लद्दाख में कौशल विकास

कौशल विकास और व्यावसायिक शिक्षा को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का अभिन्न अंग बनाया गया है। लद्दाख में भी कौशल विकास के तंत्र को मजबूत करने और विस्तार देने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं।

लद्दाख के दोनों जिलों में से हरेक में एक-एक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) और पॉलीटेकनिक महाविद्यालय है। आईटीआई में कुशल कामगारों की मौजूदा और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उनमें 12 व्यवसायों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है जिनमें फैशन डिजाइन और प्रौद्योगिकी, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी प्रणाली प्रबंधन, कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग सहायक, बढ़ई, इलेक्ट्रिशियन तथा प्लंबर की ट्रेनिंग शामिल है।

दोनों आईटीआई की अवसंरचना को मजबूत करने के लिये उनमें अत्याधुनिक उपकरणों से लैस नये कार्यशाला भवन बनाये जा रहे हैं। कार्यशालाओं के उन्नयन के लिये उद्योग के साथ तालमेल किया गया है। इस क्षेत्र में सर्दियों में तापमान शून्य डिग्री से भी नीचे चला जाता है। इसे ध्यान में रखते हुए आईटीआई की कक्षाओं और कार्यशालाओं में हीटिंग की व्यवस्था की गयी है। नयी कार्यशालाओं, कक्षाओं, बहुउद्देश्यीय कक्षों, पुस्तकालयों और अन्य सुविधाओं के निर्माण के लिये 15 करोड़ रुपये की अवसंरचना विकास परियोजनाएं शुरू की गयी हैं।

आईटीआई में प्रशिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने के लिये प्रशिक्षकों की योग्यता में सुधार जरूरी है। इस दिशा में भी अनेक कदम उठाये गये हैं। अतिथि शिक्षकों को किये जाने वाले भुगतान में ढाई गुना बढ़ोतरी की गयी है। इसके अलावा संकाय के विकास तथा प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिये कार्यक्रम भी चलाये गये हैं। क्षेत्र की आवश्यकताओं और छात्रों की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए नये अवसरों की तलाश के लिये बागवानी और फूलों की खेती के दो नये कार्यक्रम शुरू किये गये हैं। कुशल कामगारों की आपूर्ति और मांग के बीच तालमेल के लिये उद्योग के साथ सहयोग किया जा रहा है।

लद्दाख कौशल विकास मिशन (एलएसडीएम) का 2021 में गठन किया गया। इसका उद्देश्य प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना

Scanned with OKEN Scanner

और विभिन्न मंत्रालयों के अन्य कौशल विकास कार्यक्रमों के अधीन कार्यक्रम तैयार करना और उन्हें चलाना है। इससे राष्ट्रीय कौशल भारत अभियान के अनुरूप लद्दाख में कौशल विकास तंत्र को मजबूती और विस्तार मिलेगा। इस संघ शासित क्षेत्र में मार्च-अप्रैल 2021 में पहले कौशल मेले का आयोजन किया गया। इसका मकसद लद्दाख के युवाओं को कौशल विकास और रोज़गार के अवसरों को तलाशने के अवसर मुहैया कराना था। मार्च 2022 में इस संघ शासित क्षेत्र के दोनों जिलों में स्वरोज़गार और प्रशिक्षुता मेले आयोजित किये गये।

एलएसडीएम ने लद्दाख के युवाओं को स्वर कलाकार का प्रशिक्षण देने के लिये पुणे के भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान (एफटीआईआई) के साथ एक कार्यक्रम चलाया। इसके तहत लगभग 20 युवाओं को आकाशवाणी के स्टूडियो में स्वर कलाकार का प्रशिक्षण दिया गया। एफटीआईआई ने पटकथा लेखन, अभिनय और स्मार्टफोन फिल्म निर्माण के अल्पकालिक ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाये हैं। लद्दाख के अनुसूचित जनजाति के प्रशिक्षुओं के लिये ये कार्यक्रम निःशुल्क थे।

लद्दाख में टेलीविजन और फिल्म उद्योग का विकास हो रहा है। इसके परिणामस्वरूप सौंदर्य और स्वास्थ्य क्षेत्र में कुशल श्रमशक्ति की मांग बढ़ सकती है। इस संभावना को ध्यान में रखते हुए एलएसडीएम ने सौंदर्य और स्वास्थ्य क्षेत्र कौशल परिषद के सहयोग से सहायक हेयर ड्रेसर और स्टाइलिस्ट का अल्पकालिक प्रशिक्षण संचालित किया।

लद्दाख में कौशल की मांग और उपलब्धता का एक डाटाबेस तैयार किया जा रहा है जिसके जरिये उद्योग, प्रशिक्षण संस्थानों, ट्रेनिंग साझीदारों और युवाओं को एक मंच पर लाया जायेगा।

प्रशिक्षुता

प्रशिक्षुता कानून के तहत 30 या इससे ज्यादा कामगारों वाले सभी संस्थानों के लिये प्रशिक्षुता कार्यक्रम चलाना और प्रशिक्षुओं को रखना अनिवार्य है। लद्दाख में इस कानून का प्रभावी क्रियान्वयन इसी साल जून में एक आदेश जारी किये जाने के साथ ही हुआ है। इसके बारे में स्थानीय उद्योगों तथा महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के युवाओं के बीच जागरूकता फैलाने के लिये अभियान चलाने की योजना बनायी गयी है।

प्रशिक्षुता कानून उन युवाओं को अनुभव प्राप्त करने का अवसर देता है जिन्होंने स्नातक की पढ़ाई हाल में पूरी की है। इस कानून में उद्योग को महाविद्यालयों और आईटीआई से हाल में उत्तीर्ण युवाओं को रोज़गार प्रशिक्षण देने की जिम्मेदारी सौंपी गयी है। छात्र प्रशिक्षुता के जरिये अपनी पसंद का कौशल हासिल करने के साथ ही धनार्जन भी कर सकते हैं। वर्ष 2022-23 में प्रशिक्षुता की शुरुआत होने के कारण लेह और कारगिल के लिये छोटा लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आने वाले वर्षों के लिये लक्ष्य प्रशिक्षुता में प्रगति और क्षेत्र के युवाओं की प्रतिक्रिया के आधार पर तय किये जाएंगे।

उद्यमिता शिक्षा

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा में उद्यमिता शिक्षण को शामिल करने पर जोर दिया गया है। लद्दाख में उच्चतर शिक्षा संस्थानों और आईटीआई में उद्यमिता को क्रेडिट आधारित विषय के रूप में शामिल करने के लिये विस्तृत परियोजना तैयार की जा रही है।

इस संघ शासित प्रदेश के उद्योग विभाग ने कई कदम उठाये हैं। इनमें लद्दाख तैयारी केंद्र की स्थापना, चमड़े के सामान बनाने का प्रशिक्षण तथा फलों, हथकरघा उत्पादों और हस्तशिल्प के लिये निर्यात बाजार की तलाश शामिल है। उसने राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईएफटी) के साथ करार करने के अलावा राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (एनआईडी) के सहयोग से शिल्प दस्तावेजीकरण और ब्रांडिंग गतिविधियां शुरू की हैं। वाणिज्य मंत्रालय के साथ मिल कर खरीददारों और विक्रेताओं की सुविधा के लिये प्रयास किये जा रहे हैं। उद्योग विभाग ने वाणिज्य सप्ताह और उद्यमिता विकास सम्मेलन का आयोजन करने के अलावा पशमीना बुनकरों के क्षमता निर्माण और ब्रांड लद्दाख के सृजन के लिये खादी और ग्रामोद्योग आयोग का सहयोग लिया है।

संघ शासित प्रदेश के उद्योग विभाग ने कई कदम उठाये हैं। इनमें लद्दाख तैयारी केंद्र की स्थापना, चमड़े के सामान बनाने का प्रशिक्षण तथा फलों, हथकरघा उत्पादों और हस्तशिल्प के लिये निर्यात बाजार की तलाश शामिल है। उसने राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईएफटी) के साथ करार करने के अलावा राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (एनआईडी) के सहयोग से शिल्प दस्तावेजीकरण और ब्रांडिंग गतिविधियां शुरू की हैं।

आगे का रास्ता

लद्दाख कार्बन के न्यूनतम उत्सर्जन पर आधारित विकास का अनूठा मॉडल प्रस्तुत कर सकता है। लेकिन इस लक्ष्य को सभी हितधारकों की सक्रिय भागीदारी से ही हासिल किया जा सकता है जिनमें सबसे महत्वपूर्ण आम नागरिक हैं। इसके लिये जरूरी है कि युवाओं को शिक्षा, कौशल विकास, नवोन्मेष और उद्यमिता के माध्यम से प्रगति में उत्प्रेरक बनाया जाये। ■

Scanned with OKEN Scanner

डिजिटलीकरण

इश्फ़ाक़ माजिद
डॉ वाई विजया लक्ष्मी

डिजिटल प्रौद्योगिकियों में निश्चित रूप से शिक्षा का दायरा और उसकी पहुंच बढ़ाने का सामर्थ्य है। कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान विश्वभर में शिक्षा संस्थान अचानक बंद करने पड़े थे, उस संकटकाल में डिजिटल टेक्नोलॉजियां ही विभिन्न प्रौद्योगिकीय उपकरणों के माध्यम से शिक्षा व्यवस्था जारी रखने का साधन बनकर उभरी थीं। जम्मू-कश्मीर में सरकार ने शिक्षा जारी रखने की सुनिश्चित व्यवस्था करने के उद्देश्य से विभिन्न डिजिटल पहलें अपनाईं। इन डिजिटल पहलों से शिक्षा जारी रखने की व्यवस्था शुरू हुई ही, साथ ही पठन-पाठन प्रक्रिया के प्रभावी और कुशल प्रबंधन में भी सहायता मिली।

जम्मू-कश्मीर में स्कूली शिक्षा का विस्तार 200 शिक्षा क्षेत्रों और 200 क्षेत्रीय संसाधन केंद्रों तथा 800 क्लस्टर शिक्षण क्षेत्रों में फैला है। इस केंद्रशासित प्रदेश में 14,171 प्राथमिक स्कूल, 6,665 अपर प्राइमरी स्कूल, 1,194 हाई स्कूल, 597 हायर सेकेंडरी (उच्चतर माध्यमिक) स्कूल, 2 सैनिक स्कूल, 22 ज़िला शिक्षण संस्थान और 2 राज्य शिक्षा संस्थान तथा 97 केजीबीवी हैं।[1] 2020 में महामारी के कारण समूचे विश्व में शिक्षा तंत्र मज़बूरन एकदम अचानक बंद करने पड़े थे। ऐसी स्थिति में जम्मू-कश्मीर में भी स्कूल बंद करने पड़े और आमने-सामने पढ़ने की बजाय बच्चों को ऑनलाइन व्यवस्था के जरिए पढ़ाने का विकल्प अपनाया गया। शिक्षण संस्थान बंद हो जाने पर इन संस्थानों ने राज्य सरकार से शिक्षा व्यवस्था जारी रखने के लिए स्कूली शिक्षा की विभिन्न डिजिटल पहल अपनाने का अनुरोध किया।

जम्मू के स्कूली शिक्षा विभाग के निदेशालय ने वैश्विक महामारी के दौरान भी बच्चों की शिक्षा जारी रखने की सुनिश्चित व्यवस्था करने के उद्देश्य से 'डायरक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू होम क्लासेज़' नाम से नई परियोजना चलाईं। गूगल फॉर्म तैयार करके शिक्षकों को भेजे गए और उन्हें होम क्लासों में योगदान करने के लिए आमंत्रित किया गया। इन डिजिटल पहलों को लागू करने के वास्ते 'गूगलमीट, ज़ूम, फेसबुक, व्हाट्सऐप और टेलीग्राम' जैसी विभिन्न एप्लीकेशंस इस्तेमाल की गईं। पठन-पाठन की इस प्रक्रिया को गति देने के लिए विभाग ने डेडिकेटिड यू-ट्यूब चैलन 'डीएसई जम्मू होम क्लासेज' (https://youtube.com/channel/UCarOjNDaNAdKvGccDHzOXqA) आरंभ कर दिया और विभिन्न व्हाट्सऐप ग्रुपों को इसमें शामिल किया गया। विभाग ने ई-लर्निंग के लिए 25,606 व्हाट्सऐप ग्रुप तैयार किए और 10,270 सरकारी स्कूलों, 4,36,331 विद्यार्थियों और 41,113 शिक्षकों को इस प्रयास में जोड़ा। विभाग ने जुलाई, 2020 तक पहली कक्षा से बारहवीं कक्षा तक की 74.19 लाख ऑनलाइन कक्षाएं आयोजित की थीं जिनके लिए 7000 वीडियो बनाए गए थे। विषय विशेषज्ञ, शिक्षक और विद्यार्थी इन व्हाट्सऐप ग्रुपों में शामिल किए गए थे। वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करके स्थानीय केबल नेटवर्क और रेडियो स्टेशनों के माध्यम से टेलीकास्ट (प्रसारित) किए गए थे। 'डीएसईजे के होम असाइनमेंट (गृहकार्य)' प्रक्रिया से विद्यार्थियों को वैश्विक महामारी के दौरान भी शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं। विद्यार्थियों को साप्ताहिक आधार पर गृह कार्य दिया जाता था और इस व्यवस्था से लगभग 10 लाख बच्चों को इस सुविधा का लाभ पहुंचाया गया।

इनके अलावा सरकार ने जम्मू-कश्मीर में कोविड-19 के दौरान और कई पहलें शुरू कीं। ये पहले हैं:-

सरल, एड्रॉयड ऐप: सरल अर्थात् विद्यार्थी पहुंच संसाधन और शिक्षण एप्लीकेशन (ऐप) जम्मू के स्कूली शिक्षा निदेशालय की आईटी विंग (सूचना टेक्नोलॉजी शाखा) ने 'ऑल-इन-वन' यानी 'एक ही

डॉ वाई विजया लक्ष्मी, सेंटर फॉर स्टडीज एंड रिसर्च इन एजुकेशन, स्कूल ऑफ एजुकेशन, द सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में सहायक प्रोफेसर और इश्फ़ाक़ मजीद रिसर्च स्कॉलर हैं। ईमेल: vijaya.lakshmi@cug.ac.in, panditishfaq786@gmail.com

Scanned with OKEN Scanner

में सब कुछ' की अवधारणा से विकसित की थी। यह ऐप विद्यार्थियों को ई-कंटेंट से जोड़ देता है जो दीक्षा, ई-पाठशाला, स्वयं, ई-विद्यादान और स्वयंप्रभा जैसे विभिन्न शिक्षा पोर्टलों पर उपलब्ध हैं। इससे विद्यार्थियों को स्थानीय तौर पर विकसित ई-कंटेंट, लाइव क्लासेज़, गतिविधियों और ऑनलाइन मूल्यांकन (आकलन) से भी जोड़ दिया जाता है। ई-कंटेंट अनेक सु-प्रशिक्षित विषय विशेषज्ञों ने तैयार किया था। इसके माध्यम से जम्मू-कश्मीर स्कूली शिक्षा बोर्ड (जेकेबीओएसई) द्वारा तैयार कराई पाठ्य पुस्तकें भी विद्यार्थी पढ़ सकते हैं। यह ऐप गूगल प्ले स्टोर पर 'सरल डीएसईजे ऑनलाइन एजुकेशन' नाम से उपलब्ध है। इस ऐप के एक भाग में शिक्षा मंत्रालय की पहलें दी गई हैं, जिनमें भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई सभी पहलों के लिंक दिए गए हैं। यह ऐप आकलन का काम भी बखूबी कर सकता है।

स्कूल ट्रैकिंग और मॉनीटरिंग प्रणाली 'आधारशिला': आधार शिला वेब-आधारित प्रणाली है जिसका डिज़ाइन जम्मू के स्कूली शिक्षा निदेशालय ने विकसित किया है। इसका उद्देश्य जम्मू डिवीज़न के सभी सरकारी स्कूलों में डिजिटल व्यवस्था लागू करना है। इस वेब-आधारित प्रणाली से इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षकों और शिक्षण कार्य में उनकी दक्षता का आकलन करने में मदद मिलती है। इस वेब पोर्टल में सभी सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों के बारे में जानकारी उपलब्ध है। इस जानकारी से 'शिक्षक-विद्यार्थी अनुपात, विद्यार्थियों का श्रेणीवार विवरण, स्कॉलरशिप का विवरण, आधार विवरण के बिना वाले विद्यार्थियों की पूरी जानकारी वगैरह' का पता चल जाता है, जिससे आगे की योजना बनाने और नीतिगत फैसले लेने में सुविधा हो जाती है। इस वेब-आधारित पोर्टल पर राज्य और ज़िला स्तर से मिलने वाली आर्थिक सहायता का स्कूल-वार विवरण भी उपलब्ध रहता है। इस पोर्टल का वेब पता है- www.schedujammu.nic.in/aadharshila.

आधार शिला वेब-आधारित प्रणाली है जिसका डिज़ाइन जम्मू के स्कूली शिक्षा निदेशालय ने विकसित किया है। इसका उद्देश्य जम्मू डिवीज़न के सभी सरकारी स्कूलों में डिजिटल व्यवस्था लागू करना है। इस वेब-आधारित प्रणाली से इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षकों और शिक्षण कार्य में उनकी दक्षता का आकलन करने में मदद मिलती है। इस वेब पोर्टल में सभी सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों के बारे में जानकारी उपलब्ध है। इस जानकारी से 'शिक्षक-विद्यार्थी अनुपात, विद्यार्थियों का श्रेणीवार विवरण, स्कॉलरशिप का विवरण, आधार विवरण के बिना वाले विद्यार्थियों की पूरी जानकारी वगैरह' का पता चल जाता है।

समाधान: समाधान शिकायतों की ऑनलाइन सुनवाई की व्यवस्था है जिसका उद्देश्य डिलीवरी तंत्र, विशेषकर स्कूली शिक्षा के डिलीवरी तंत्र को पारदर्शी बनाना और उसमें सुधार लाना है। इस प्रणाली का डिज़ाइन डीएसई ने तैयार किया जिसे राष्ट्रीय अधिसूचना केंद्र (एनआईसी) ने विकसित किया। अभिभावक, विद्यार्थी और शिक्षक अपनी शिकायतें इस प्रणाली में भेज सकते हैं। इन शिकायतों को सुनवाई और निपटारे के लिए संबद्ध अधिकारियों के पास भेज दिया जाता है। ताज़ा रिकॉर्ड के अनुसार इस पोर्टल पर 1034 शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनमें से 669 का समाधान कर दिया गया और 319 पर सुनवाई चल रही है।

जम्मू-कश्मीर शिक्षा हब: जेएंडके एजुकेशन हब यानी जम्मू-कश्मीर शिक्षा हब सरकारी स्कूलों के शिक्षकों द्वारा विकसित शैक्षिक डिजिटल सामग्री की वेब-आधारित प्रणाली है। इस पर उपलब्ध उत्कृष्ट सामग्री चुनकर दीक्षा जैसे राष्ट्रीय स्तर के पोर्टलों पर भेज दी जाती है। यह पोर्टल ऑनलाइन/दूरस्थ शिक्षा को सुगम और सरल बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। विद्यार्थी और शिक्षक अकेले इसी पोर्टल से सभी डिजिटल संसाधनों तक पहुंच प्राप्त कर सकते हैं। निदेशालय इसी हब के माध्यम से सभी ऑनलाइन वेबिनार, बैठकें और कार्यशालाएं आयोजित करता है। इस पोर्टल में एक विशेष भाग ऐसा है जिसमें शिक्षकों और विद्यार्थियों की उपलब्धियों को दर्शाया जाता है।

जम्मू के स्कूली शिक्षा निदेशालय का ई-ऑफिस

निदेशालय ने कार्यालय के कामकाज को व्यवस्थित और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से ई-ऑफिस खोला था। कार्यालय का कामकाज पेपरलेस यानी पूरी तरह से डिजिटल बनाने के उद्देश्य से एनआईसी ने यह ई-ऑफिस शुरू किया था। फाइलों के डिजिटीकरण को देखते हुए जवाबदेही और कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए यह प्रणाली अपनाई गई थी। फाइलों के आने-जाने की व्यवस्था डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए की जाती है जिससे फाइल की स्थिति पर निगाह रखी जा सकती है। बस एक क्लिक करके ही फाइल की स्थिति सामने आ जाती है। इस पहल का उद्देश्य निदेशालय के कामकाज में पारदर्शिता बनाए रखना और सुचारू ढंग से फाइलों की ताज़ा स्थिति का पता लगाना है। निदेशालय अपने सभी अधीनस्थ कार्यालयों में यही प्रणाली लागू करने की सोच रहा है।

प्राइवेट स्कूलों के प्रबंधन की प्रणाली

प्राइवेट स्कूलों के प्रबंधन में भी वेब-आधारित प्रणाली लागू है। यह सभी प्राइवेट स्कूलों के लिए लागू है चाहे वे जेकेबीओएसई, सीबीएसई या आईसीएसई में से किसी बोर्ड के अंतर्गत चलाए जा रहे हों। इस प्रणाली में प्राइवेट स्कूलों के रजिस्ट्रेशन और अपग्रेडेशन (पंजीकरण और उन्नयन) की अनुमति भी ऑनलाइन देने की व्यवस्था है। यह पहल अभी विकसित की जा रही है और शीघ्र ही इसके पूरा हो जाने की उम्मीद है।[1,2]

डिजिटल पहलों के अंतर्गत डीएसई जम्मू ने 25 से 31 जुलाई, 2022 तक 'डिजिटल जम्मू-कश्मीर सप्ताह' मनाया जिसमें जम्मू-कश्मीर को डिजिटल बनाने में सरकार द्वारा चलाई गई डिजिटल पहलों का उल्लेख करने पर विशेष बल दिया गया था।[3]

जम्मू-कश्मीर सरकार शिक्षा व्यवस्था को तेज़ी से आगे बढ़ाने और इसमें अधिक पारदर्शिता लाने के लिए अनूठी डिजिटल पहले अपना रही है। शिक्षा क्षेत्र में ये क्रांतिकारी पहले सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के सहयोग से चलाई जा रही हैं जिससे विद्यार्थियों का जीवन सरल बनाया जा सके और पठन-पाठन अधिक प्रभावी बन जाए। ■

संदर्भ

1. http://schedujammu.nic.in/aadharshila/pdf/report.pdf
2. https://cict.nic.in/upload/Jan%2031_DIGITAL%20INITATIVES%20SCHOOL%20EDUCATION%20DEPARTMENT%20JKUT%20for%20NCERT.pptx.pdf
3. http://schedujammu.nic.in/orders_circulars/DSEJ-28-07-2022(1).PDF

Scanned with OKEN Scanner

कारीगरों को प्रोत्साहन

समीरा सौरभ

आर्थिक प्रगति तथा समतापूर्ण विकास को बढ़ावा देने में लघु उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में ऐसे उद्योगों का बड़ा हिस्सा है। इन लघु उद्योगों में खाद्य तथा पेय पदार्थों, मशीनों, प्लास्टिक की वस्तुओं, रसायनों, औषधियों, कागज की वस्तुओं, रेशम, ईंटों और टाइलों, सीमेंट और वाहनों के हिस्से-पुर्जों आदि का उत्पादन होता है। यह क्षेत्र उद्यमिता सीखने वाली नर्सरी जैसा है जहां रचनात्मक प्रतिभा से सम्पन्न और नवाचार के इच्छुक उद्यमी हाथ आज़माते हैं। इस क्षेत्र में विकास की बड़ी संभावना है और बड़ी संख्या में रोज़गार भी जुटाता है।

जम्मू और कश्मीर विभिन्न क्षेत्रों का समृद्ध परम्पराओं तथा अनेक आकर्षक कलाओं और शिल्पों वाला क्षेत्र है। विश्व भर में यहाँ के हस्तशिल्प प्रसिद्ध हैं। यहाँ के क़ालीनों, रेशमी परिधानों, शालों, टोकरियों, बर्तनों, तांबे और चाँदी की वस्तुओं, पेपरमैशी और अखरोट की लकड़ी की बेहद मांग रहती है। कुटीर शिल्प उद्योग करीब 3,40,000 कारीगरों को प्रत्यक्ष तथा लाभप्रद रोज़गार उपलब्ध करता है। जर्मनी के सहयोग से वैश्विक सहयोग की एक बड़ी योजना शुरू की गई है। जर्मनी में कश्मीरी हस्तशिल्पों की बहुत मांग है। यूरोप के नया देशों के साथ भी वैश्विक सहयोग की ऐसी ही योजनाएँ चलाने के प्रयास जारी हैं।

जम्मू में बुनाई, कढ़ाई, बुनियादी कटिंग और सिलाई सत्र

लेखिका लघु तथा मध्यम उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार में संयुक्त सचिव हैं। ईमेल: sameera.saurabh@gmail.com

Scanned with OKEN Scanner

कश्मीर के हथकरघे के काम की सदियों से दुनिया भर में प्रसिद्धि है। इस क्षेत्र के खास डिज़ाइनों के साथ-साथ, यहाँ के पशमीना, रेशम और ऊन के रूप में कच्चा माल भी स्थानीय तौर पर उपलब्ध होता है। पारम्परिक हथकरघे का काम बड़ी संख्या में कारीगरों को रोज़गार देता है।

कश्मीर से धारा 370 हटाये जाने के बाद, प्रशासन ने अब तक 23,156 करोड़ रुपये मूल्य के 456 करार किए हैं।

कश्मीर के हथकरघे के काम की सदियों से दुनिया भर में प्रसिद्धि है। इस क्षेत्र के खास डिज़ाइनों के साथ-साथ, यहाँ के पशमीना, रेशम और ऊन के रूप में कच्चा माल भी स्थानीय तौर पर उपलब्ध होता है। पारम्परिक हथकरघे का काम बड़ी संख्या में कारीगरों को रोज़गार देता है।

लघु और मंझोले उद्योगों की वर्तमान स्थिति

जम्मू और कश्मीर में छोटे और मंझोले उद्यमों का दायरा अनेक निर्माण और सेवा गतिविधियों में फैला हुआ है। इस समय 1,26,387 छोटी और मंझोली इकाइयां 'उद्यम' पोर्टल पर पंजीकृत हैं। इनमें से अधिकतर निम्न क्षेत्रों में कार्यरत हैं –

- उत्पादन (मैन्युफैक्चरिंग): खाद्य संसाधन, पानी की पैकेजिंग, कार्डबोर्ड तैयार करना, फर्नीचर-आधारित उद्यम, हस्तशिल्प तथा हथकरघा-आधारित उद्यम. क्रिकेट के बैट बनाना।
- सेवाएं: कोल्ड स्टोरेज, होटल उद्योग, टूर एंड ट्रेवल आधारित उद्योग, पर्यटन से जुड़े उद्यम।

कश्मीर घाटी के प्रमुख व्यापार-क्षेत्रों का विकास लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय की सूक्ष्म एवं लघु उद्योग संकुल विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी) के अंतर्गत किया जा रहा है। परियोजना की अनुमानित लागत 46 करोड़ रुपये है। अब 22 करोड़ रुपये की लागत से दो औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं। ये हैं- ऊधमपुर ज़िला और पुलवामा क्षेत्र, जो जम्मू और कश्मीर का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है।

जम्मू और कश्मीर में 'स्फूर्ति' (पारम्परिक उद्योगों के उत्थान के लिए धन देने की योजना -स्कीम फॉर रिजेनेरेशन ऑफ ट्रेडीशनल इंडस्ट्रीज-एसएफ़यूआरटीआई) संकुल भी चलाए जा रहे हैं। पिछले दिनों जम्मू और कश्मीर के माननीय उप-राज्यपाल ने बड़गाँव और अनंतनाग जिलों में ऐसे दो संकुलों का उद्घाटन किया। लघु तथा मध्यम उद्योग मंत्रालय (भारत सरकार) भी नवाचारों को प्रोत्साहन देता है और मंत्रालय की नवाचार प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत एनआईटी, श्रीनगर में एक व्यापार विकास केंद्र (बिजनेस इंक्युबेशन सेंटर) खोला गया है। इस समय दो नवाचार योजनाओं पर काम चल रहा है और उनके प्रोटोटाइप के निर्माण के लिए 21 लाख रुपये दिए गए हैं।

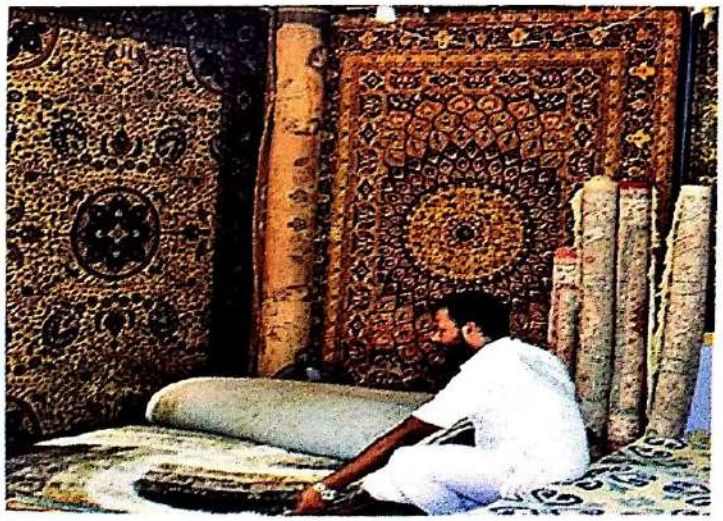

जम्मू और कश्मीर खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड पूरे केंद्र-शासित क्षेत्र में सूक्ष्म तथा ग्रामीण उद्योगों के दायरे में उद्यमिता को स्थापित और प्रोत्साहित कर रहा है। बोर्ड द्वारा सहायता-प्राप्त कारीगर ग्राहकों की पसंद की वस्तुएँ बनाते हैं और पारम्परिक उद्यमों का टिकाऊ तथा गतिशील क्षेत्र विकसित कर ग्रामीण सामुदायिक भावना को सुदृढ़ करते हैं।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग इस केंद्र-शासित क्षेत्र में प्रधान मंत्री रोज़गार गारंटी कार्यक्रम को तेजी से लागू कर रहा है। सरकारी सब्सिडी पूर्व-निर्धारित बैंकों के जरिए सीधे लाभार्थियों/उद्यमियों के बैंक खातों में जमा करा दी जाती है।

लघु और मध्यम उद्यमों से जुड़ी योजनाओं का कार्यान्वयन

मध्यम क्षेत्र संकुल विकास कार्यक्रम (एमएसई क्लस्टर डेवलपमेंट प्रग्राम)

इस योजना का उद्देश्य मध्यम श्रेणी के उद्यमों के संकुलों में मूलभूत सुविधाओं का विस्तार करके टेक्नोलॉजी कौशल, गुणवत्ता तथा बाज़ार तक पहुँच आदि को बढ़ाना है; साथ ही संकुलों को टिकाऊ टेक्नोलॉजी भी सुलभ कराना है।

उद्यमिता कौशल विकास कार्यक्रम (आंत्रप्रेन्योरशिप स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम-ईएसडीपी)

इस कार्यक्रम के अंतर्गत अनुसूचित जातियों/जनजातियों, महिलाओं, दिव्यांगों, भूतपूर्व सैनिकों और गरीबी की रेखा के नीचे जीवन बिता रहे परिवारों आदि के युवाओं को स्व-रोज़गार अथवा अपना उद्यम शुरू करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। (तालिका-1)

तालिका 1

कार्यान्वयन	टिप्पणी
ईएसडीपी कार्यक्रम जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख के सभी जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है।	इस वित्त वर्ष के दौरान दूर-दराज के सीमावर्ती जिलों में कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है।

बीपीएमएस – प्रोक्योरमेंट एंड मार्केटिंग सपोर्ट स्कीम

इस योजना का उद्देश्य वस्तुओं और सेवाओं की बेहतर बिक्री के उपाय करना है। इसके उद्देश्य हैं –

1. बाज़ार में पहुँच बढ़ाने के प्रयासों को बढ़ावा देना तथा लघु और मंझोले उद्यमों के उद्यमियों में जागरुकता बढ़ाना और उन्हें शिक्षित करना।
2. व्यापार मेलों, डिजिटल विज्ञापनों, ई-मार्केटिंग, जीएसटी और जैम पोर्टल के बारे में अधिक जागरूकता फैलाना।

एमएसएमई सस्टेनेबल (ज़ेडईडी) प्रमाणन योजना

इस योजना के अंतर्गत लघु और मध्यम उद्योगों में 'ज़ीरो

Scanned with OKEN Scanner

डिफ़ेक्ट एंड ज़ीरो इफेक्ट' (ज़ेड (ज़ेडईडी) यानि जिनकी गुणवत्ता में कोई कमी न हो और जिनकी निर्माण-प्रक्रिया में पर्यावरण को कोई नुकसान न पहुँचता हो) निर्माण को बढ़ावा देना है। ऐसी वस्तुओं का 'ज़ेड आकलन' करने के बाद प्रमाणित किया जाता है। इस योजना के तहत लघु और मध्यम उद्योगों को आधुनिकतम टेक्नोलॉजी और उपकरणों का इस्तेमाल करते हुए, पर्यावरण को बिना नुकसान पहुँचाए, श्रेष्ठ गुणवत्ता के उत्पाद तैयार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। (तालिका 2)

तालिका 2

कार्यान्वयन	टिप्पणी
संशोधित 'ज़ेड' योजना के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख के लघु और मध्यम उद्योगों को पंजीकृत करना	इस योजना के अंतर्गत 141 इकाइयों को पोर्टल में पंजीकृत किया जा चुका है।

'उद्यम' पंजीकरण

सरकार ने लघु और मध्यम उद्योगों को पंजीकृत करने की प्रणाली बनाई है। पंजीकरण के बाद एक स्थायी पंजीकरण संख्या दी जाती है। (तालिका 3)

तालिका 3

कार्यान्वयन	टिप्पणी
उद्यम पंजीकरण के बारे में जागरुकता पैदा करने के लिए एमएसएमई-डीओ, जम्मू और कश्मीर द्वारा ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया गया।	कुल उद्यम पंजीकरण-126387, इस वित्त वर्ष में उद्यम पंजीकरण के बारे में जागरुकता पैदा करने के लिए 4 कार्यक्रम आयोजित किए गए।

सांबा में टेक्नोलॉजी केंद्र का निर्माण

सांबा (जम्मू और कश्मीर) के औद्योगिक क्षेत्र में टेक्नोलॉजी केंद्र बनाया जा रहा है। मंत्रालय ने जमीन हासिल कर ली है और निर्माण-कार्य चल रहा है।

लेह (लद्दाख) में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति केंद्र (नेशनल एससी-एसटी हब -एनएसएसएच)

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति केंद्र (नेशनल एससी-एसटी हब -एनएसएसएच) योजना केंद्रीय लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय की योजना है जिसका 2016 में प्रधान मंत्री ने शुभारंभ किया। इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उद्यमियों की क्षमता बढ़ाना और इन समुदायों के बीच 'उद्यमिता की संस्कृति' को बढ़ावा देना है। इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के समुदायों की सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया में भागीदारी बढ़ाना है और मंत्रालयों, विभागों और केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा इन समुदायों के उद्यमियों से 4 प्रतिशत खरीद का लक्ष्य पूरा करना है। यह योजना केंद्र सरकार सार्वजनिक उपक्रम- राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के प्रारम्भ से ही, विभिन्न हितधारकों से परामर्श करते हुए, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उद्यमियों की क्षमता बढ़ाने तथा उन्हें बाज़ार में संपर्क प्रदान करने के अनेक प्रयास किए गए हैं और उप-योजनाएँ चलाई गई हैं।

जम्मू और कश्मीर की अपनी विशिष्टताएँ और भौगोलिक स्थिति है, इसलिए यहाँ तीव्र विकास करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना ज़रूरी है। बागवानी, हथकरघा और हस्तशिल्प, बायोटेक्नोलॉजी, पर्यटन और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) यहाँ विकास के संभावित क्षेत्र हैं जिनकी विकास योजनाओं को घनिष्टता से आपस में तथा अन्य क्षेत्रों के साथ जोड़ा जाना आवश्यक है। ■

मरीन आर्कियोलॉजी इन इंडिया

भाषा : अंग्रेजी, मूल्य : 600 रुपये

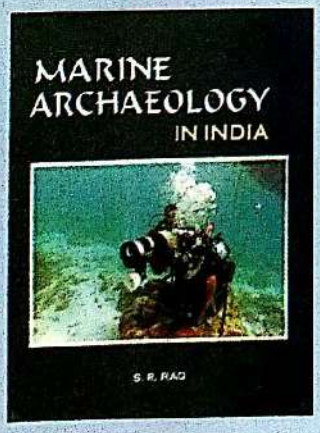

भारतीय उपमहाद्वीप ने अपनी 6500 किलोमीटर लंबी तटरेखा, 200 बंदरगाहों और प्रमुख नदियों से जुड़े समृद्ध आंतरिक इलाक़ों के साथ अपने 5000 साल के नौवहन और समुद्री व्यापार के इतिहास में पूर्व और पश्चिम को जोड़ते हुए हिंद महासागर के व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह सिंधु घाटी (हड़प्पा) की सभ्यता के दौर में भी जहाज और पोतगाह (डॉकयार्ड) के निर्माण में अग्रणी था। यह बात 2300 ईसा पूर्व में खंभात की खाड़ी में लोथल के हड़प्पा बंदरगाह पर एक गोदाम के साथ ईंटों से निर्मित एक विशाल ज्वारीय गोदी (टाइडल डॉक) की खोज से प्रमाणित हो चुकी है। 1600 ईसा पूर्व तक, यह बड़े जहाजों के लंगर डालने के लिए बंदरगाह में उपयुक्त रूप से एक रिज में बदलाव लाकर द्वारका के बंदरगाह में लंगर डालने की सुविधाएं प्रदान कर सकता था। समुद्री इंजीनियरिंग में हासिल की गई इस प्रगति के साथ ही साथ, द्वारका के नाविक पहले वाले पत्थर के लंगरों में सुधार कर सकते थे। नौवहन के लंबे इतिहास के दौरान, दुनिया के विभिन्न देशों ने अपने हजारों जहाजों को खो दिया है और चक्रवाती तूफानों, तटीय क्षरण और समुद्र के जलस्तर में वृद्धि के परिणामस्वरूप अनेकों बंदरगाहों को समुद्र निगल चुका है। खो चुका प्रत्येक जहाज और डूब चुका प्रत्येक बंदरगाह, उसका निर्माण करने वाले समाज का प्रतीक तथा ज्ञान का खजाना है। इसलिए व्यवस्थित उत्खनन के माध्यम से इनकी खोज की जानी चाहिए और मानव की इस विरासत को सहेजा जाना चाहिए। भारत ने क्षतिग्रस्त जहाजों तथा द्वारका, पुम्पुहार और सोमनाथ जैसे जलमग्न बंदरगाहों की खोज के लिए 1981 में समुद्री पुरातत्व केंद्र की स्थापना की। यह पुस्तक 'मरीन आर्कियोलॉजी इन इंडिया' पिछले डेढ़ दशक के दौरान भारत द्वारा की गई इस जलमग्न सांस्कृतिक विरासत की खोज का विस्तृत विवरण देती है। इसमें क्षेत्र के अग्रदूतों के समक्ष आयी समस्याओं और उत्खनन के लिए अपनायी गई तकनीकों और प्राप्त हुए परिणामों पर प्रकाश डाला गया है। ■

स्वच्छ सागर - सुरक्षित सागर
Clean Coast - Safe Sea

Scanned with OKEN Scanner

लैवेंडर का फलता-फूलता कारोबार

डॉ सुमीत गैरोला

जम्मू स्थिति वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद सीएसआईआर के भारतीय समेकित औषधि संस्थान (आईआईआईएम) ने कई दशक के वैज्ञानिक प्रयोगों के बाद इसकी अत्यंत दुर्लभ किस्म आरआरएल-12 और एग्रोटेक्नोलॉजी (कृषि प्रौद्योगिकी) विकसित की है। लैवेंडर की इस किस्म की खेती वर्षा पर आधारित क्षेत्रों और सम-मौसम वाले इलाकों में बहुत उपयुक्त रहती है जिनमें कश्मीर घाटी और जम्मू डिवीज़न के समशीतोष्ण मौसम वाले क्षेत्र विशेष हैं। सीएसआईआर-अरोमा मिशन के अंतर्गत जम्मू के सीएसआईआर-आईआईआईएम ने जम्मू डिवीजन के डोडा, रामबन, किश्तवाड़, कठुआ, उधमपुर, रजौरी, पुलवामा, अनंतनाग, कुपवाड़ा और बांदीपुरा जिलों के किसानों को लैवेंडर की खेती के बारे में जानकारी दी। सीएसआईआर-आईआईआईएम, जम्मू ने सीएसआईआर-अरोमा मिशन के तहत किसानों को लैवेंडर की खेती, प्रसंस्करण, मूल्यवर्द्धन और विपणन के लिए मुफ्त में क्वालिटी प्लांटिंग मैटिरियल यानी बढ़िया किस्म की पौधरोपण सामग्री तथा एंड-टु-एंड (शुरू से आखिर तक) टेक्नोलॉजी पैकेज उपलब्ध कराए हैं। सीएसआईआर-आईआईआईएम ने जम्मू-कश्मीर के विभिन्न क्षेत्रों में 50 डिस्टिलेशन यूनिट लगाई हैं जिनमें से 45 यूनिटें फिक्स्ड यानी अचल हैं और पांच यूनिटें चलती-फिरती यानी मोबाइल हैं। यह व्यवस्था किसानों को उनके उत्पादों के प्रसंस्करण में मदद देने के उद्देश्य से सीएसआईआर-अरोमा मिशन के अंतर्गत की गई हैं।

भौगोलिक दृष्टि से जम्मू-कश्मीर के दूरदराज के क्षेत्रों में किसान और युवा उद्यमी बड़ी संख्या में लैवेंडर की खेती को व्यवसाय के रूप में अपना रहे हैं। इस क्षेत्र में लैवेंडर की खेती पर आधारित नए उद्योग विकसित हो गए हैं। इस समय जम्मू-कश्मीर में 1000 से ज्यादा खेतिहर परिवार इस क्षेत्र के विभिन्न भागों में 300 एकड़ से ज्यादा जमीन पर लैवेंडर उगा रहे हैं। लैवेंडर उगाने वाला हर किसान खेती में सहयोग के लिए 5 और लोगों को काम पर रखता है। इस प्रकार इस क्षेत्र के 5000 से ज्यादा कृषक परिवारों को रोज़गार मिला हुआ है। खेतों में लैवेंडर की कटाई और फूलों की प्रोसेसिंग का काम मुख्य रूप से महिलाओं से कराया जाता है जिससे इस क्षेत्र की महिलाओं की आय बढ़ी है। जम्मू-कश्मीर के डोडा ज़िले के विभिन्न गाँवों की महिलाओं ने वर्ष 2022 के दौरान अब तक एक करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के 20 लाख से ज्यादा लैवेंडर पौधों की नर्सरी विकसित की है। कई युवा उद्यमियों ने लैवेंडर तेल, हाइड्रोसोल और फूलों के मूल्यवर्द्धन से जुड़े छोटे पैमाने के व्यवसाय शुरू

लेखक सीएसआईआर अरोमा मिशन (सीएसआईआर-आईआईआईएम), जम्मू-कश्मीर में नोडल वैज्ञानिक हैं। ईमेल: sumeetgairola@iiim.res.in

Scanned with OKEN Scanner

जम्मू-कश्मीर के दूर-दराज वाले इलाकों में बड़ी संख्या में किसान और युवा उद्यमी लैवेंडर की खेती अपना रहे हैं। कई युवा उद्यमियों ने तो लैवेंडर का तेल, हाइड्रोसोल और सूखे फूलों का व्यवसाय लघु उद्योग के रूप में शुरू कर दिया है- 'लैवेंड्युला एंगस्तिफोलिया मिल' या 'असल लैवेंडर' का पौधा छोटा और नरम होता है जो सदाबहार रहता है और दुनिया के अनेक भागों में इसकी वाणिज्यिक खेती की जाती है तथा इसकी आकर्षक नुकीली पत्तियों का हाइड्रो-डिस्टिलेशन यानी आवसन करके अर्क़ तैयार किया जाता है। व्यावसायिक दृष्टि से लैवेंडर इत्र या खुशबूदार तेल बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले सबसे लोकप्रिय पौधों में से है जिसे अर्क़ तैयार करने और सूखे फूल बनाने के उद्देश्य से उगाया जाता है।

Scanned with OKEN Scanner

तलिका-1 : जम्मू क्षेत्र में पर्पल क्रांति से उद्यमिता विकास

उद्यमियों की किस्में	संख्या
लैवेंडर की पौधरोपण सामग्री तैयार करना	35
उत्पाद विकास/मूल्यवर्द्धन	5
तेल अर्क़ का डिस्टिलेशन/डिस्टिलेशन यूनिट संचालन	10
कुल	**50**

कर लिए हैं। सीएसआईआर-आईआईआईएम ने सीएसआईआर-अरोमा मिशन के तहत कौशल विकास के कई कार्यक्रम शुरू किए हैं और जम्मू-कश्मीर के 2,500 से ज्यादा किसानों और युवा उद्यमियों को लैवेंडर की खेती, मूल्य संवर्द्धन और विपणन का प्रशिक्षण उपलब्ध कराया है (तालिका-1)।

जम्मू-कश्मीर में उत्पादित लैवेंडर तेल का मूल्य भारतीय बाज़ारों में लगभग 10,000 रुपये प्रति किलोग्राम है। लैवेंडर के फूलों की कीमत भी 1,000 रुपये से 1,500 रुपये प्रति किलोग्राम के बीच है। जम्मू डिवीज़न के कई समशीतोष्ण क्षेत्रों में मोटे अनाज की खेती करने वाले छोटे और सीमांत किसानों ने भी लैवेंडर की खेती करनी शुरू कर दी है क्योंकि इन्हें मोटे अनाज की खेती से 2,500 रुपये प्रति कनाल (1 हेक्टेयर/ 20 कनाल) की आमदनी ही होती थी। इस क्षेत्र में लैवेंडर तेल का वार्षिक उत्पादन क़रीब 40 से 60 लीटर प्रति हैक्टेयर है जिससे औसत उत्पादन क़रीब 50 लीटर प्रति हैक्टेयर प्रति वर्ष होता है। इस प्रकार लैवेंडर किसानों की शुद्ध वार्षिक आय कई गुणा बढ़कर 40,000 रुपये से 60,000 रुपये प्रति हैक्टेयर से लेकर 3,50,000 रुपये से 6,00,000 लाख रुपये प्रति हैक्टेयर तक पहुंच गई है। डोडा जिले के किसानों ने 2019 में 300 लीटर, 2020 में 500 लीटर, 2021 में 800 लीटर और 2022 में 1200 लीटर लैवेंडर तेल का उत्पादन किया (चित्र 2)। इससे इन किसानों को 2018 से 2022 के बीच सूखे फूलों, लैवेंडर की क्वालिटी पौधरोपण सामग्री और लैवेंडर तेल की बिक्री से 5 करोड़ रुपये से अधिक की आय हुई। इस क्षेत्र में लैवेंडर तेल का मौजूदा उत्पादन अभी शुरूआती चरण में है। आने वाले वर्षों में लैवेंडर तेल का उत्पादन कई गुणा हो जाने की उम्मीद है। ऐसा हो जाने पर आयात कम करके विदेशी मुद्रा की बचत की जा सकेगी। साथ ही, लैवेंडर तेल के निर्यात की

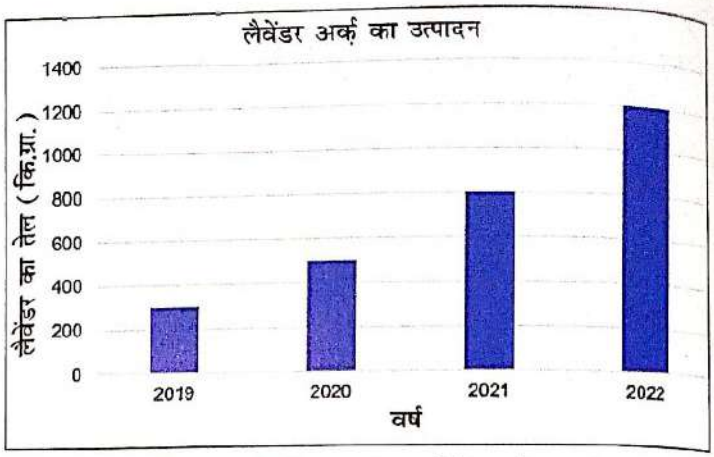

चित्र 1 : डोडा ज़िले में उत्पादित लैवेंडर तेल की मात्राएं

काफी संभावनाएं बन जाएंगी क्योंकि विदेशों में इसकी बहुत मांग है।

अरोमा मिशन के अंतर्गत सीएसआईआर-आईआईआईएम द्वारा जम्मू-कश्मीर के किसानों को लैवेंडर की खेती से जुड़ी टेक्नोलॉजी की समूची जानकारी हस्तांतरित करने की सफलता को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रिंट मीडिया (समाचार पत्रों) और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया (रेडियो-टेलीविज़न) में व्यापक कवरेज दिया गया है। सीएसआईआर-भारतीय समेकित औषधि संस्थान, जम्मू को जम्मू-कश्मीर में लैवेंडर की खेती से पर्पल (बैंजनी) क्रांति के जरिये ग्रामीण विकास नवाचार (सीएआईआरडी-2020) लाने के लिए एसएंडटी नवाचार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

सीएसआईआर-आईआईआईएम ने सीएसआईआर-अरोमा मिशन के तहत कौशल विकास के कई कार्यक्रम शुरू किए हैं और जम्मू-कश्मीर के 2,500 से ज्यादा किसानों और युवा उद्यमियों को लैवेंडर की खेती, मूल्य संवर्द्धन और विपणन का प्रशिक्षण उपलब्ध कराया है।

जम्मू-कश्मीर में डोडा जिले के भद्रवाह में पहली बार मई, 2022 में लैवेंडर समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें उद्योगों, शिक्षा संस्थानों और किसानों के 250 से ज़्यादा प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। 25 प्रगतिशील लैवेंडर किसानों और स्टार्टअप्स को सम्मानित भी किया गया। सीएसआईआर-अरोमा मिशन का उद्देश्य भारत को अरोमा (औषधीय पौधों) के उत्पादन का प्रमुख केंद्र बनाना है और इस प्रयास के तहत किसानों, उद्योगों और समाज के असल उपयोगकर्ताओं और ग्राहकों तक विकसित अरोमा उत्पाद वितरित करके व्यापार के अवसर जुटाने, ग्रामीण विकास और जीवन स्तर सुधारने तथा अधिकांश औषधीय/सुगंध वाले तेलों के घरेलू उद्योगों में इस्तेमाल को बढ़ावा देकर आयात पर खर्च होने वाली विदेशी मुद्रा की बचत की जा सकेगी। साथ ही भारत की छवि भी कच्चे माल उत्पादक की जगह उत्तम किस्म के विकसित (तैयार) और मूल्यवर्द्धित उत्पाद उपलब्ध कराने वाले देश की हो जाएगी।

अरोमा मिशन देशभर के स्टार्टअप्स और किसानों को आकर्षित कर रहा है। इसके पहले चरण में सीएसआईआर ने देश में 6000 हैक्टेयर में लैवेंडर की खेती करने में मदद दी जिसके तहत 46 ज़िले कवर किए गए। 44,000 से ज़्यादा लोगों को प्रशिक्षित किया जा चुका है और किसानों ने करोड़ों रुपये की आय अर्जित की है। दूसरे चरण में अरोमा मिशन के तहत 45,000 से अधिक कुशल लोग इसकी खेती से जुड़ जाएंगे, जिससे देशभर के 75,000 से ज़्यादा कृषि परिवार लाभान्वित होंगे। ■

Scanned with OKEN Scanner

जम्मू-कश्मीर में सबके लिये स्वास्थ्य

यासीन एम चौधरी

सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान-नेशनल हेल्थ मिशन (एनएचएम) के तहत आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र-हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर (एबी-एचडब्ल्यूसी) कार्यक्रम चलाया है। इस कार्यक्रम में एचडब्ल्यूसी की स्थापना शामिल है। यह प्राथमिक स्तर की स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने का हाल के वर्षों में सबसे बड़ा प्रयास है। इसमें सबके लिये स्वास्थ्य सुविधा हासिल करने के मकसद से चयन आधारित के बजाय व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा-कंप्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर (सीपीएचसी) का दृष्टिकोण अपनाया गया है। जम्मू-कश्मीर सभी उप स्वास्थ्य केंद्रों-सब हेल्थ सेंटर (एसएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों-प्राइमरी हेल्थ सेंटर (पीएचसी) को एचडब्ल्यूसी में बदलने का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में अग्रणी राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों में से एक है। यह कदम क्षेत्र में सामुदायिक भागीदारी और स्वास्थ्य सेवाओं की मांग में सुधार के लिये महत्वपूर्ण है।

एक बहुत पुरानी कहावत है - 'दवा से परहेज भला'। कोविड 19 की वैश्विक महामारी के बाद के मौजूदा समय में यह कहावत पहले से भी ज्यादा प्रासंगिक हो गयी है। संवहनीय विकास लक्ष्य-सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल (एसडीजी.3) में स्वास्थ्य संवर्द्धन और रोगों की रोकथाम के महत्व को रेखांकित किया गया है। इसमें व्यक्तियों के लिये 'अच्छी सेहत और कल्याण' के सिद्धांत को सामुदायिक स्वास्थ्य प्रक्रियाओं के महत्वपूर्ण पहलू के रूप में शामिल किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन-वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन (डब्ल्यूएचओ) ने सबके लिये स्वास्थ्य कवरेज-यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज (यूएचसी) के एसडीजी 3.8 को प्राथमिकता दी है। वह इस सिद्धांत पर चलते हुए जरूरी स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच के जरिये सभी क्षेत्रों, उम्र समूहों तथा सामाजिक और आय वर्गों के व्यक्तियों को सेहत संवर्द्धन, रोगों की रोकथाम और उपचार, पुनर्वास तथा उपशामक सेवा समेत संपूर्ण आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं का आश्वासन प्रदान करता है।[1] हमें गौर करना चाहिये कि इस रणनीति में 'पहुंच' पर खास तौर से जोर दिया गया है।

स्वास्थ्य को संविधान की सातवीं अनुसूची में राज्यों के विषय के तौर पर शामिल किया गया है। फिर भी केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय इस क्षेत्र में राज्यों में बड़े पैमाने पर संसाधनों का निवेश करता है। वह एक मजबूत और समुदाय आधारित स्वास्थ्य प्रणाली की स्थापना के लिये प्रयासरत है। इस दिशा में 1997 में प्रजनन और बाल स्वास्थ्य-रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ (आरसीएच) 1 और बाद में व्यापक दायरे वाले एनएचएम की शुरुआत की गयी। एनएचएम के तहत निचले स्तर पर मान्यताप्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं-एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट (आशा) समेत स्वास्थ्यकर्मियों का एक मजबूत कैडर तैयार किया गया है। डब्ल्यूएचओ ने स्वास्थ्य संरक्षण और संवर्द्धन में आशा के विशिष्ट योगदान की हाल ही में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सराहना की है। देश के अन्य राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों की तरह ही जम्मू-कश्मीर

लेखक भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, संघ शासित क्षेत्र जम्मू-कश्मीर के मिशन निदेशक हैं। ईमेल: mdnhmjk@gmail.com

Scanned with OKEN Scanner

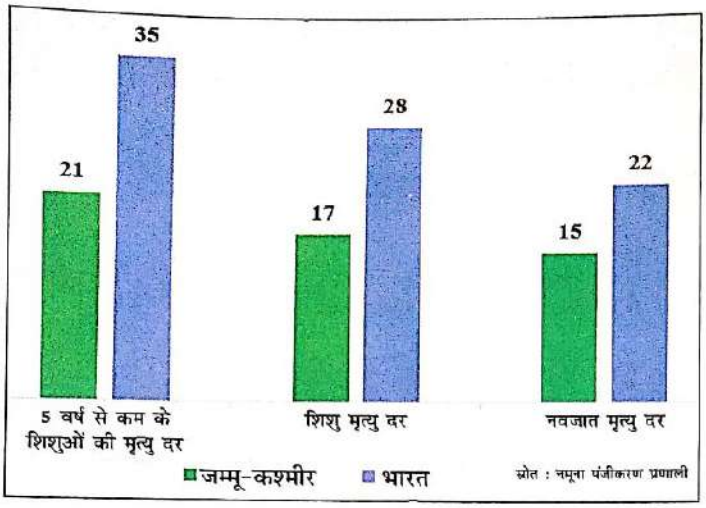

में भी एनएचएम की मदद से लगभग 13500 आशा कार्यकर्ताओं का नेटवर्क तैयार किया गया है। वे प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिये समुदाय को स्वास्थ्य प्रणाली से जोड़ने में महत्वपूर्ण योगदान करती हैं। उनका उद्देश्य हर व्यक्ति को उसके घर तक सेवाओं की निर्बाध डिलीवरी प्रदान कर स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच में अंतर को खत्म करना है। आशा कार्यकर्ताओं और उनकी मदद करने वाली सहायक उपचारिकाओं-ऑक्जिलियरी नर्स मिडवाइफ (एएनएम) और अन्य क्षेत्रीय स्वास्थ्यकर्मियों का विस्तृत नेटवर्क एक ऐसी कवरेज प्रणाली तैयार करता है जिसमें सभी नागरिक शामिल हों। संघ शासित क्षेत्र जम्मू-कश्मीर में समुदाय आधारित हस्तक्षेपों पर अवाम की प्रतिक्रिया कुल मिला कर सकारात्मक रही है। स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली-हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम (एचएमआईएस) और आरसीएच पोर्टलों पर मौजूद आंकड़ों का विशाल संग्रह इसका सबूत है। इन पोर्टलों से क्षेत्रीय कार्यों की लगातार निगरानी और मूल्यांकन सुनिश्चित हुआ है। ये बताते हैं कि सबके लिये स्वास्थ्य की दिशा में अब तक कितनी सेवाएं प्रदान की जा चुकी हैं और कितना काम जारी है। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप जम्मू-कश्मीर में स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार आया है। इस संघ शासित क्षेत्र में शिशु मृत्यु दर घट कर 17 और नवजात मृत्यु दर 15 हो गयी जो राष्ट्रीय औसत से काफी नीचे है।[2]

संकेतक (राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5)	जम्मू-कश्मीर (%)	भारत (%)
प्रसव पूर्व देखरेख के लिये कम-से-कम चार बार आने वाली माताएं	80.9	58.1
किसी स्वास्थ्य संस्थान में जन्म	92.4	88.6
कुशल स्वास्थ्य कर्मियों की देखरेख में जन्म	95.1	89.4
सभी टीके ले चुके 12 से 23 माह के बच्चे	86.2	76.4

स्रोत: स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय

विभिन्न देशों में इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि सकारात्मक स्वास्थ्य परिणाम हासिल करने और उन्हें बरकरार रखने के लिये समुदाय और स्वास्थ्य सेवा के बीच भागीदारी की जरूरत होती है। जम्मू-कश्मीर में आरसीएच में हुई जबरदस्त प्रगति से भी यह जाहिर है।[3]

स्वास्थ्य सुविधाएं	भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानकों के अनुसार आवश्यकता	ग्रामीण स्वास्थ्य आंकड़ों (2020) के अनुसार स्थिति
ज़िला अस्पताल		21
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र	83	77
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ग्रामीण	333	923
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शहरी	80	49
उपस्वास्थ्य केंद्र	2042	2470
मेडिकल कॉलेज और अस्पताल		9

स्रोत: स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय

आधुनिक भारतीय स्वास्थ्य सेवा नीति में आम तौर पर सेवाओं तक पहुंच को आपूर्ति पक्ष के सरोकार और खास तौर से अवसंरचनात्मक मुद्दे के रूप में लिया गया है। लिहाजा, जम्मू-कश्मीर समेत देश के कुछ हिस्सों में सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना की पहुंच भारतीय जन स्वास्थ्य मानकों-इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड (आईपीएचएस) से भी अधिक हो गयी है।[4]

सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान-नेशनल हेल्थ मिशन (एनएचएम) के तहत आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र-हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर (एबी-एचडब्ल्यूसी) कार्यक्रम चलाया है। इस कार्यक्रम में एचडब्ल्यूसी की स्थापना शामिल है। यह भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है। यह प्राथमिक स्तर की स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने का हाल के वर्षों में सबसे बड़ा प्रयास है। इसमें सबके लिये स्वास्थ्य सुविधा हासिल करने के मकसद से चयन आधारित करने के बजाय विस्तृत प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा-कंप्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर (सीपीएचसी) का दृष्टिकोण अपनाया गया है।[4] जम्मू-कश्मीर सभी उपस्वास्थ्य केंद्रों-सब हेल्थ सेंटर (एससी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों-प्राइमरी हेल्थ सेंटर (पीएचसी) को एचडब्ल्यूसी में बदलने का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में अग्रणी राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों में से एक है।[5]

स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र	लक्ष्य दिसंबर 2022	मौजूदा स्थिति (एचडब्ल्यूसी पोर्टल)
स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र-उपस्वास्थ्य केंद्र	1770	1415
स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र - प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र	923	543
स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र - शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र	49	44
कुल	2742	2002

स्रोत: स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय

Scanned with OKEN Scanner

एचडब्ल्यूसी-एसएचसी स्तर पर स्वास्थ्यकर्मियों का एक नया कैडर तैनात किया जा रहा है। इन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी-कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर (सीएचओ) या मध्य स्तरीय स्वास्थ्य प्रदाता-मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर (एमएलएचपी) के नाम से जाना जाता है। इनका स्थान चिकित्सा सहायकों और पूर्णकालिक चिकित्सा अधिकारियों के बीच है। ये सीमित रोगों के लिये आबादी आधारित मार्गनिर्देशात्मक स्क्रीनिंग करने में सक्षम होंगे जिससे सामुदायिक पहुंच, क्लिनिकल प्रबंधन और सेवा की निर्बाधता में सुधार आयेगा। एबी-एचडब्ल्यूसी ने आबादी नामांकन और समुदाय आधारित आकलन चेकलिस्ट-पॉपुलेशन एनरॉलमेंट एंड कम्युनिटी बेस्ड एसेसमेंट (सीबीएसी) फॉर्म का प्रावधान किया है। यह संभवतः सबसे आरंभिक मगर अब तक का सर्वाधिक ठोस व्यक्ति आधारित स्वास्थ्य रिकॉर्ड है। जम्मू-कश्मीर इससे भी आगे जाकर देखभाल के विभिन्न स्तरों पर आबादी नामांकन, सीबीएसी फॉर्म, जांच, निदान और उपचार के आंकड़ों के डिजिटलीकरण पर काम कर रहा है। इस तरह असंचारी रोग-नॉन कम्युनिकेबल डिज़ीज़ (एनसीडी) ऐप पर आंकड़ों का अंबार तैयार हो रहा है।

सबके लिये स्वास्थ्य सुविधा हासिल करने के मकसद से चयन आधारित के बजाय विस्तृत प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा-कंप्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर (सीपीएचसी) का दृष्टिकोण अपनाया गया है। जम्मू-कश्मीर सभी उपस्वास्थ्य केंद्रों-सब हेल्थ सेंटर (एससी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों-प्राइमरी हेल्थ सेंटर (पीएचसी) को एचडब्ल्यूसी में बदलने का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में अग्रणी राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों में से एक है।

लेकिन समाज पर आपूर्ति पक्ष के अत्यधिक संसाधन लादने से पहले मांग के पहलू का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है। समाजवैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार व्यक्तियों और समुदायों की आकांक्षाओं का स्तर सामाजिक विकास की गति के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। एक शिक्षित और जानकार समाज अपनी जरूरतों के प्रति ज्यादा जागरूक होता है। इसलिये स्वास्थ्य के बेहतर स्तर को लेकर उसकी आकांक्षा भी बड़ी होगी। लिहाजा, वह आपूर्ति पक्ष के संसाधनों से खुद को अधिक सफलतापूर्वक जोड़ सकता है। दूसरी ओर, एक कम जागरूक समाज की आकांक्षाओं का स्तर भी नीचे होगा। इसलिये वह अपने घर तक पहुंचाये जाने पर भी स्वास्थ्य सेवा संसाधनों को हासिल करने या उनका फायदा उठाने में सक्षम नहीं होगा। संसाधनों, योजनाओं और सुविधाओं का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिये समुदायों में उनकी मांग का होना महत्वपूर्ण है। जन स्वास्थ्य सहयोग (जेएसएस), गनयारी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ के रूप में भारत में समुदाय आधारित प्राथमिक सेवा हस्तक्षेपों की मिसाल हमारे सामने है। जेएसएस दिखाता है कि यह मांग आम तौर पर समुदाय में साक्षरता और जागरूकता के स्तर से निर्धारित होती है। मसलन, अगर कोई समुदाय किन्हीं कारणों से टीकाकरण के खिलाफ है तो उस क्षेत्र में टीकों का प्रचुर भंडार और टीका लगाने वाले कर्मियों की बड़ी संख्या भी इस काम में सफलता नहीं दिला सकती। संघ शासित क्षेत्र जम्मू-कश्मीर में एचडब्ल्यूसी की स्थापना की दिशा में समुदाय की भागीदारी और स्वास्थ्य सेवाओं की मांग में सुधार के लिये यह महत्वपूर्ण कदम है। आशा कर्मी, ग्राम स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता समिति, ग्रामीण स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण दिवस, सहायक समूह और हाल में स्थापित जन आरोग्य समिति (जेएएस) इसमें मददगार हैं।

द्वितीय और तृतीय स्तर की स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं में भीड़भाड़ काफी बढ़ गयी है। इन तक पहुंचने वाले रोगियों की बाढ़ में लगभग 40 प्रतिशत मरीज ऐसे हैं जिनका उपचार प्राथमिक स्तर पर आसानी से किया जा सकता है। कई क्षेत्रों में इस विसंगति का कारण खराब परामर्श व्यवस्था और सरकारी प्राथमिक सेवा सुविधाओं की बदहाली है। कई दफा रोगी निचले स्तर की सेवा को नजरंदाज कर बेहतर इलाज की उम्मीद में बड़े शहरी अस्पतालों में पहुंच जाते हैं भले ही उन्हें क्यों न ओपीडी के काउंटर के सामने घंटों खड़ा रहना पड़े।[6] इसका एक आर्थिक परिणाम भी है। कल्पना करें कि एक गरीब ग्रामीण मजदूर शहर के बड़े अस्पताल में इलाज कराने के चक्कर में अपनी दिहाड़ी गंवा देता है हालांकि उसके मामूली रोग का उपचार घर के नजदीक ही संभव था। इस तरह का मरीज अक्सर अनुवर्ती इलाज के लिये बार-बार शहर के अस्पताल में नहीं जा पाता। वह काफी समय बाद तृतीय स्तर के सरकारी अस्पताल में अनुवर्ती उपचार के लिये पहुंच भी जाये तो उसे वही डॉक्टर नहीं मिलता जिसने पहले उसका इलाज किया था। अगर वह डॉक्टर मिल भी गया तो उसे मरीज का साल भर से अधिक

Scanned with OKEN Scanner

समय पुराना पिछला स्वास्थ्य रिकॉर्ड याद नहीं होगा। इसलिये रोगी को हर बार अपना इलाज नये सिरे से कराना पड़ जाता है। डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड के अभाव में ज्यादातर मरीज बेतरतीब कागजों का भारी पुलिंदा लेकर घूमते नजर आते हैं। इन कागजों में ऐसी पुरानी पर्चियां और जांच रिपोर्टें भी होती हैं जिनका इस्तेमाल कई दफा मुश्किल है। मरीजों की संख्या ज्यादा होने की वजह से डॉक्टर उन्हें समय कम दे पाते हैं। इसलिये मरीज को गुणवत्तापूर्ण सेवा के बजाय सिर्फ लक्षण पर आधारित उपचार ही मिल पाता है। दूसरी ओर, परामर्श के अभाव में पुराने और गंभीर रोगों के मरीजों को द्वितीय या तृतीय स्तर के उन अस्पतालों का पता ही नहीं चल पाता जहां उन्हें जाना चाहिये। परामर्श और व्यक्तिगत निर्देश तंत्र के अभाव में अनपढ़ ग्रामीण रोगी शहर के भीड़भाड़ वाले बड़े अस्पताल में खो जाता और खुद को अवांछित महसूस करता है। ऑस्कर लुइस के 'निर्धनता चक्र' के सिद्धांत के अनुसार गरीब और हाशिये के लोग आम तौर पर संस्थानों को शक की निगाह से देखते हैं। इस वजह से भी निर्धन ग्रामीण सार्वजनिक संस्थाओं की सेवाओं का लाभ नहीं उठा पाते हैं।

नतीजतन अनेक रोगियों का उपचार नहीं हो पाता या फिर अनुवर्ती प्रक्रिया छूट जाने के कारण उनका इलाज अधूरा रह जाता है। इसके परिणामस्वरूप उन्हें अपने रोग के साथ ही जीना पड़ता है। उपचार अधूरा छूट जाने पर गुर्दे के रोगों, कीमोथेरेपी की आवश्यकता वाले कैंसर, प्रतिरक्षा संबंधी बीमारियों और रक्त विकारों जैसी तकलीफों की पहचान नहीं होने से रोगियों के लिये स्थिति गंभीर हो जाती है।

द्वितीय और तृतीय चरण के उपचार संस्थानों में भीड़भाड़ घटाना तथा समुदाय के नजदीक ही मजबूत परामर्श और अनुवर्ती व्यवस्था वाली प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करना महत्वपूर्ण है। घर के नजदीक इलाज की व्यवस्था से रोगों का निदान और उपचार तेजी से किया जा सकता है। इससे बीमारी गंभीर रूप धारण नहीं करेगी। इसलिये रोगी को तीसरे चरण की देखभाल के लिये घबराहट में भागने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। कल्पना करें कि किसी समुदाय में मधुमेह के जोखिम वाले सभी रोगियों की पहचान जल्दी कर एक मजबूत प्राथमिक देखभाल प्रणाली के जरिये उन्हें तंदुरुस्ती की राह पर लाया जाता है। ऐसे में तृतीय चरण की देखभाल के लिये भीड़ में शामिल होने वाले मधुमेह संबंधी जटिलता से ग्रस्त रोगियों की संख्या काफी घट जायेगी।

संघ शासित क्षेत्र जम्मू-कश्मीर में घर के नजदीक ही जल्दी निदान को संभव बनाया जा रहा है। इसके लिये सुनिश्चित किया गया है कि मधुमेह और सामान्य कैंसर जैसे असंचारी रोगों की एचडब्लयूसी में आबादी आधारित जांच हो। इस जांच का आंख, कान, नाक और गले के रोगों तथा बुजुर्ग और उपशामक देखरेख तक विस्तार किया जा रहा है।

सोचने की बात यह भी है कि प्राथमिक स्तरीय अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण के बावजूद कमी कहां रह गयी है। हम आबादी की जांच के बाद क्या कर रहे हैं। सतत देखभाल-कॉन्टिनम ऑफ केयर (सीओसी) के मॉडल में दो चीजों की कल्पना की गयी है। पहली, अगले स्तर की सेवाओं तक पहुंच गाँव में ही प्रदान करना और दूसरी, देखभाल के समय में उसके घर या समुदाय से संपर्क। इस मॉडल में गहन देखभाल, मुफ्त निदान और औषधि तक पहुंच सुनिश्चित करना शामिल है। यह देखभाल की गुणवत्ता में सुधार के लिये सततता सुनिश्चित करता है।[7] संघ शासित क्षेत्र जम्मू-कश्मीर में घर के नजदीक ही जल्दी निदान को संभव बनाया जा रहा है। इसके लिये सुनिश्चित किया गया है कि मधुमेह और सामान्य कैंसर जैसे असंचारी रोगों की एचडब्लयूसी में आबादी आधारित जांच हो। इस जांच का आंख, कान, नाक और गले के रोगों तथा बुजुर्ग और उपशामक देखरेख तक विस्तार किया जा रहा है। कल्पना करें कि कोई गरीब वृद्ध व्यक्ति अज्ञानतावश मांसपेशियों और हड्डियों की परेशानी के लिये शहर के बड़े अस्पताल तक जाता है। इस परेशानी का उसके गाँव के एचडब्ल्यूसी में पहले ही आसानी से पता लगाया जा सकता है। सीएचओ या एमएलएचपी इसका आसानी से इलाज कर इसे गंभीर रूप अख्तियार करने से रोक सकते हैं। लेकिन हमारी राज्य स्तरीय स्वास्थ्य प्रणाली आबादी आधारित जांच में रोगग्रस्त पाये गये नागरिकों को भर्ती होकर इलाज के लिये प्रेरित करती है। इसका कारण देखभाल के स्तरों के बीच तालमेल का अभाव है। एबी-एचडब्ल्यूसी प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को मजबूत कर रहे हैं। इससे सततता आधारित इष्टतमता मानदंडों-कॉन्टिनम बेस्ड ऑप्टिमलिटी क्राइटेरिया (सीओसी) के दृष्टिकोण को सुनिश्चित करने के लिये एक मजबूत परामर्श और अनुवर्ती सेवा प्रणाली का उदय हो रहा है।

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) निस्संदेह स्वास्थ्य क्षेत्र की दशक की सबसे महत्वपूर्ण पहल है। किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत स्वास्थ्य रिकॉर्ड से ज्यादा मूल्यवान या विशिष्ट कोई अन्य डाटा नहीं हो सकता। एबीडीएम के परिष्कृत सेवा विन्यास का लक्ष्य ओपीडी, आईपीडी और प्रयोगशाला जांच नतीजों समेत हर स्वास्थ्य परामर्श को दर्ज करना है। इस रिकॉर्ड को मान्यताप्राप्त संस्थाओं के बीच व्यवहार के रूप में दर्ज किया जाता है। इन संस्थाओं में आभा पहचानधारी रोगी तथा स्वास्थ्य सेवा पंजीयन वाले अस्पताल में स्वास्थ्य सेवा प्रोफेशनल के रूप में पंजीकृत चिकित्सक शामिल हैं। इस तरह तैयार व्यक्तिगत इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड (ईएमआर) मरीज को रोगी स्वास्थ्य दस्तावेज-पेशेंट हेल्थ रिकॉर्ड (पीएचआर) ऐप के जरिये मिल सकता है। पीएचआर एक आधार

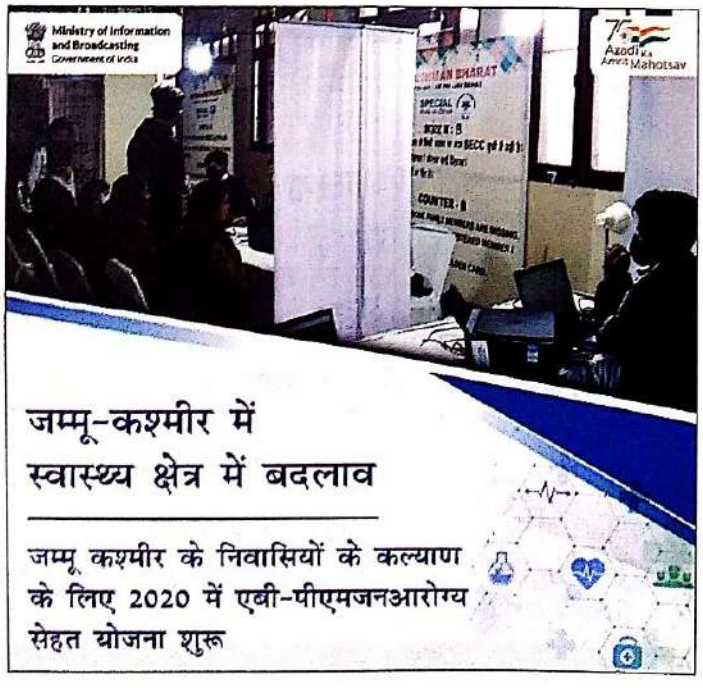

Scanned with OKEN Scanner

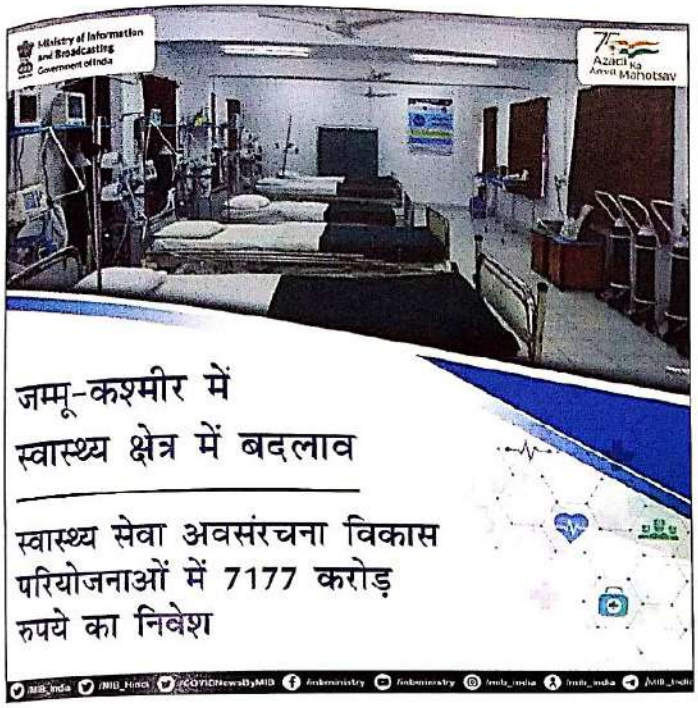

समर्थित और मरीज की सहमति पर आधारित प्रणाली है। मरीज की सहमति के बिना उसके मेडिकल रिकॉर्ड को किसी को भी सौंपा नहीं जा सकता। एबीडीएम के तहत जम्मू-कश्मीर ने यह सुनिश्चित करने का कठिन बीड़ा उठाया है कि एसएचसी/पीएचसी/सीएचसी/डीएच में प्रवेश करने के साथ ही किसी व्यक्ति का रिकॉर्ड डिजिटल स्वरूप में आभा पहचान और पीएचआर से जुड़ जाये। सूचना प्रबंधन प्रणाली में पहचान, निदान, जांच, उपचार और औषधि आपूर्ति को शामिल किया जाता है। जम्मू-कश्मीर प्रशासन विभिन्न मंचों पर डाटा के महत्व को ध्यान में रखते हुए प्रणालियों को आपस में जोड़ने पर भी लगातार काम कर रहा है ताकि ये देखभाल के हर स्तर पर उपलब्ध रहें।

स्वास्थ्य संबंधी दस्तावेजों का भारी पुलिंदा उठाये इधर-उधर भटक रहे रोगी की ओर एक बार फिर लौटते हैं। एबीडीएम डिजिलॉकर आधारित ईएमआर उसकी परेशानी को दूर करने की कोशिश है। लेकिन समाज में डिजिटल विभाजन बहुत गहरा है। ऐसी स्थिति में यह देखने की बात है कि क्या एक अनपढ़ मजदूर डिजिटल रिकॉर्ड को समझने और उसका उपयोग करने में सक्षम होगा। अस्पताल में भर्ती होकर इलाज के भारी खर्च का सवाल भी बड़ा है। हाल के वर्षों में हमारा देश इस चुनौती से निपटने में काफी हद तक कामयाब रहा है। आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबीपीएमजय) इस दिशा में एक युगांतरकारी कदम है। इसके तहत देश भर में गरीबी रेखा से नीचे के मरीज अस्पताल में भर्ती होकर पांच लाख रुपये तक का इलाज मुफ्त करा सकते हैं। जम्मू-कश्मीर का प्रयास है कि इस संघ शासित क्षेत्र की समूची आबादी को आर्थिक परेशानी के बिना स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें। वह भारत के उन कुछेक राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में शामिल है जिनमें एबी-पीएमजय में समूची आबादी को शामिल किया गया है। जम्मू-कश्मीर की एबी-पीएमजय सेहत (सोशल एंडेवर फॉर हेल्थ एंड टेलीमेडिसिन) योजना में इस संघ शासित क्षेत्र की समूची आबादी शामिल है।

संघ शासित क्षेत्र जम्मू-कश्मीर में एबी-एचडब्ल्यूसी, एबी-पीएमजय और एबीडीएम से प्राथमिक, द्वितीय और तीसरे चरण की स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच की स्थिति आर्थिक और डिजिटल तौर पर तेजी से बदल रही है। हमारी स्वास्थ्य प्रणाली का जोर प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा को मजबूत कर बड़े अस्पतालों के ऊपर सामान्य ओपीडी के बोझ को घटाने पर होना चाहिये। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि जरूरतमंद नागरिकों को अस्पताल में भर्ती होकर मुफ्त इलाज कराने की सुविधा मिल सके। भारत संवर्द्धित और आधुनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के युग में प्रवेश कर रहा है। ऐसे में चुनौतियों का सामने आना अनिवार्य है। यह काम बहुत कठिन लग सकता है मगर कतारों को छोटा कर हम इसकी शुरुआत कर सकते हैं। ■

संदर्भ

1. विश्व स्वास्थ्य संगठन। 2020। मॉनिटरिंग प्रोग्रेस ऑन यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एंड द हेल्थ रिलेटेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन द डब्ल्यूएचओ साउथ-ईस्ट एशिया रीजन: 2020 अपडेट, इंडिया।
2. महापंजीयक कार्यालय, नयी दिल्ली। एसआरएस बुलेटिन 2022, महापंजीयक कार्यालय, नयी दिल्ली। नमूना पंजीकरण प्रणाली 2019।
3. अंतरराष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान (आईआईपीएस) और आईसीएफ। 2021। राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस-5), भारत, 2020-21 : राजस्थान। मुंबई : आईआईपीएस।
4. राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र। 2018। आयुष्मान भारत कंप्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर थ्रू हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स ऑपरेशनल गाइडलाइंस।
5. एबी-एचडब्ल्यूसी पोर्टल। https://ab-hwc.nhp.gov.in/
6. श्रीवास्तव एस, करण एके, भान एन, मुखोपाध्याय आई और विश्व स्वास्थ्य संगठन। 2022। इंडिया : हेल्थ सिस्टम रिव्यू। हेल्थ सिस्टम्स इन ट्रांजिशन, 11 (1)।
7. राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र। 2018। आयुष्मान भारत कंप्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर थ्रू हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स ऑपरेशनल गाइडलाइंस।

Scanned with OKEN Scanner

आकाश से परे

डॉ विनय कुमार

पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल या उससे परे प्रवेश करने वाले अंतरिक्ष यान से किए गए अनुसंधान के रूप में परिभाषित अंतरिक्ष विज्ञान में मौसम विज्ञान, भूविज्ञान, चंद्र, सौर, ग्रह विज्ञान, खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी सहित अनेक क्षेत्र शामिल हैं। उन्नत अनुसंधान के जरिये जम्मू-कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र ने अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अपार संभावना दर्शायी है।

अंतरिक्ष विज्ञान और उसके अनुप्रयोगों को समझने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने देश के विभिन्न भागों में कई संस्थान स्थापित किए हैं। उनमें जम्मू और कश्मीर शामिल है जहां इसरो और जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय (सीयूजे) के सहयोग से एक उन्नत अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष विज्ञान केंद्र (एसडीसीएसएस) जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है।

सीयूजे में एसडीसीएसएस की स्थापना इसके उत्तर भारत में प्रमुख केंद्र होने के नाते जम्मू-कश्मीर के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह केंद्र इस क्षेत्र के लिए अंतरिक्ष अनुप्रयोगों की क्षमता का दोहन करने में मदद करेगा और युवाओं को अंतरिक्ष विज्ञान के साथ-साथ राष्ट्र के विकास में योगदान करने का अवसर प्रदान करेगा। अंतरिक्ष अनुप्रयोगों का दायरा जम्मू-कश्मीर और बृहत्तर हिमालयी क्षेत्र के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक है क्योंकि इसकी अर्थव्यवस्था और निवास स्थल वनस्पति आच्छादन, वन क्षेत्र, हिम, भूस्खलन, हिमस्खलन, भूजल, मेघावरण, वायुमंडलीय परिस्थितियों आदि से प्रभावित हैं और इन पर सुदूर संवेदन (रिमोट सेंसिंग) के जरिए अंतरिक्ष से आसानी से नजर रखी जा सकती है। इस केंद्र में स्थित रिमोट सेंसिंग और जीआईएस प्रयोगशालाएं वायु प्रदूषकों और कणाकार पदार्थों की स्थिति और पूर्वानुमान का मूल्यांकन करने में सहायक हैं। साथ ही वे तापमान उत्क्रमण और वायुमंडलीय स्थिरता के साथ उनके परस्पर सम्बन्ध का पता लगाती हैं और मेसोस्केल वायुमंडलीय मॉडल और 3डी-वीएआर डाटा एसिमिलेशन तकनीक का उपयोग करके जम्मू-कश्मीर के मौसम की घटनाओं की मेसोस्केल मॉडलिंग करती हैं। क्षेत्र में बारम्बार आने वाली प्राकृतिक आपदाओं को ध्यान में रखते हुए मौसम और वायुमंडलीय अनुसंधान के लिए इस क्षेत्र की भू-आधारित पर्यवेक्षण क्षमताओं को मजबूत करने की आवश्यकता का भी अत्यन्त महत्व है। इस केंद्र की स्थापना जम्मू-कश्मीर क्षेत्र के विकास के लिए उभरती भू-स्थानिक और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी आवश्यकताओं को भी पूरी करेगी।

सीयूजे के सतीश धवन अंतरिक्ष विज्ञान केंद्र में भू-स्थानिक डाटा विश्लेषण की सुविधाएं होंगी जो प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग और भूमि-उपयोग पैटर्न की योजना बनाने में मदद करेंगी। इसमें वायुमंडलीय अध्ययन के लिए भू-आधारित पर्यवेक्षण सुविधाएँ होंगी। यहाँ खगोल भौतिकी और वायुमंडलीय संवेदन के लिए एक शोध प्रयोगशाला के अलावा उत्तर भारत की नदियों में मौसमी हिम, बर्फ और हिमनदों के रूप में संग्रहित बड़ी मात्रा में जल के बेहतर उपयोग के लिए ग्लेशियर अध्ययन प्रयोगशाला होगी। इसके अलावा यहां आपदा प्रबन्धन केंद्र भी स्थापित किया जाएगा जो जम्मू-कश्मीर क्षेत्र में बाढ़, भूस्खलन, जंगल में लगने वाली आग, सूखा और जलवायु परिवर्तन जैसी विभिन्न आपदाओं पर अनुसंधान करेगा। यह केंद्र जम्मू और कश्मीर के आस-पास के क्षेत्र में जलवायु और पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना पर बायोएरोसोल के विविध प्रभावों का पता लगाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

एसडीसीएसएस जम्मू और कश्मीर में स्थापित अपनी तरह का पहला संस्थान है। यह केंद्र अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में शिक्षा के लिए नए तरीकों की एक विशाल शृंखला प्रदान करता है। सहायक प्रौद्योगिकी से लाभान्वित विशेष आवश्यकताओं वाले जम्मू-कश्मीर के शिक्षित लोगों के लिए रोज़गार के अधिक अवसर प्राप्त होंगे। ■

अंतरिक्ष अनुप्रयोगों का दायरा जम्मू-कश्मीर और बृहत्तर हिमालयी क्षेत्र के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक है क्योंकि इसकी अर्थव्यवस्था और निवास स्थल वनस्पति आच्छादन, वन क्षेत्र, हिम, भूस्खलन, हिमस्खलन, भूजल, मेघावरण, वायुमंडलीय परिस्थितियों आदि से प्रभावित हैं और इन पर सुदूर संवेदन (रिमोट सेंसिंग) के जरिए अंतरिक्ष से आसानी से नजर रखी जा सकती है।

लेखक जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। ईमेल: vinay.phy@cujammu.ac.in

Scanned with OKEN Scanner

हनले अंतरिक्ष वेधशाला

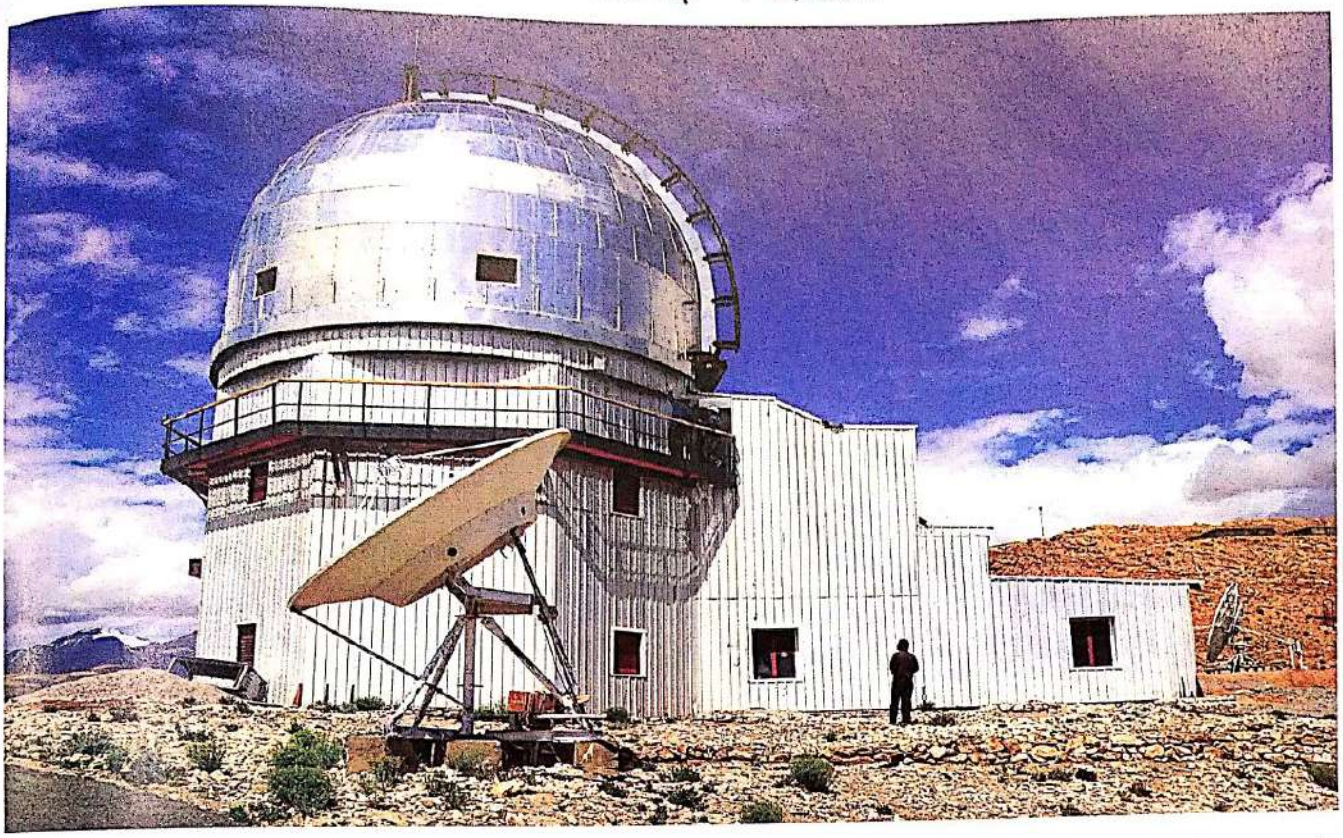

एक हालिया अध्ययन में कहा गया है कि लद्दाख में लेह के पास हनले में स्थित भारतीय खगोलीय वेधशाला (आईएओ) विश्व स्तर पर सबसे उदीयमान वेधशाला स्थलों में से एक बन रहा है। यह इसके लाभों जैसे अधिक साफ़ रातें, न्यूनतम प्रकाश प्रदूषण, हवा में तरल बूंदें यानी एरोसोल की सघनता, अत्यंत शुष्क वायुमंडलीय स्थिति और वर्षा से अबाधित होने के कारण है।

खगोलविद् कई वर्षों के दौरान एकत्रित स्थानीय मौसम संबंधी आंकड़ों के आधार पर अपने आगामी बड़े टेलिस्कोप बनाने के लिए दुनिया भर में उपयुक्त स्थानों की लगातार खोज कर रहे हैं। इस तरह के अध्ययन भावी वेधशालाओं की योजना बनाने और यह पूर्वानुमान लगाने में महत्वपूर्ण हैं कि वे समय के साथ कैसे बदलेंगे।

भारत के शोधकर्ताओं और उनके सहयोगियों ने 8 ऊँचाई वाले वेधशालाओं में रात्रिकाल के बादलों के जमघट के अंश का विस्तृत अध्ययन किया जिसमें भारत में तीन यानी हनले और मरक (लद्दाख) और देवस्थल (नैनीताल) में स्थित भारतीय खगोलीय वेधशाला (आईएओ) शामिल हैं।

दिग्पा-रत्सा री, हनले का राष्ट्रीय वेधशाला के लिए संभावित स्थल के रूप में चयन भारतीय उपमहाद्वीप पर मौसम संबंधी स्थितियों के अध्ययन, हिमालय और ट्रांस-हिमालयी क्षेत्रों में उच्च ऊँचाई वाले इलाकों के स्थलाकृतिक मानचित्रों के अध्ययन और साथ-साथ सितंबर 1993 में छह सम्भावित स्थलों के टोही सर्वेक्षण के बाद किया गया था। इसके अतिरिक्त जनवरी और जून 1994 में संस्थान के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने इस स्थल के दौरे किये। स्थायी स्थल सर्वेक्षण शिविर दिसंबर 1994 में दिग्पा-रत्सा री के उत्तर में नीलमखुल मैदानी क्षेत्र के सिरे पर स्थापित किया गया था। स्थल का विस्तृत निरूपण जनवरी 1995 में शुरू हुआ और आज तक जारी है।

दिग्पा-रत्सा री की सबसे ऊँची चोटी 4517 मीटर की ऊँचाई पर है और इसका नाम सरस्वती पर्वत रखा गया है। आसपास का नीलमखुल मैदानी क्षेत्र समुद्र तल से 4240 मीटर की ऊँचाई पर है। यह शृंखला 2 कि.मी. पूर्व-पश्चिम और 1 कि.मी. उत्तर-दक्षिण में फैली है जिसका शीर्ष लगभग आधा वर्ग कि.मी. समतल क्षेत्र है। चोटी में कुछ चट्टानी टीले हैं जिन्हें कुछ मीटर तक समतल किया गया है। दो मीटर चौड़ाई वाला हिमालयी चंद्र टेलीस्कोप (एचसीटी) का स्थान शिखर के पूर्व में एमएसएल से 4500 मीटर की ऊँचाई पर है।

विभिन्न खगोल-जलवायु मापदंडों के कई वर्षों के आंकड़ों की जांच करने के बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स (आईआईए) ने 2000 में भारतीय खगोलीय वेधशाला (आईएओ), हनले में 2-मीटर एपर्चर वाला हिमालयी चंद्र टेलीस्कोप (एचसीटी) स्थापित किया। इसके बाद इस स्थल की विशिष्टता के कारण देश के अनेक संस्थानों द्वारा हनले में ऑप्टिकल और इन्फ्रारेड वेवबैंड पर संचालित कई खगोलीय टेलीस्कोपों को स्थापित किया गया है। ■

स्रोत: पीआईबी और न्यूज़ऑनएयर

Scanned with OKEN Scanner

कश्मीर: कविता और रहस्यवाद

डॉ नम्रता चतुर्वेदी

बौद्ध और शैव मतों से सूफी रिवायत तक – कश्मीर के साहित्यिक-सांस्कृतिक परिदृश्य ने भारत में रहस्यवाद तथा साहित्य की परम्परा को समृद्ध किया है।

संस्कृत साहित्यिक समालोचना, अध्यात्म और काव्य-शास्त्र के उद्भव और विकास में कश्मीर का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। कश्मीर अनेक श्रेष्ठ साहित्यिक समालोचकों, सिद्धांतकारों, दार्शनिकों और टीकाकारों की जन्म-स्थली और कर्म-स्थली रहा है। पाणिनि, चंद्राचार्य, भरत, क्षेमेन्द्र, अभिनवगुप्त, वसुगुप्त, सोमानंद, सोमदेव, बिल्हण, कल्हण, पतंजलि, आनंदवर्धन जैसे अनेक मनीषी हुए हैं जिन्होंने भारत में भाषा, साहित्य, इतिहास और दर्शन के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जहां पाणिनि की अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण का आधार है, वहीं भारत का नाट्यशास्त्र नाटक-विधा के सिद्धांतों का मूलभूत ग्रंथ है। औचित्य, गुण, रीति और ध्वनि के सिद्धान्तकाव्य-शास्त्र में कश्मीर के ही योगदान हैं। ये सिद्धान्त साहित्य तथा सौंदर्य-शास्त्र की सभी विचारधाराओं में सन्निहित हैं। कश्मीर में ही ऐतिहासिक चतुर्थ बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी जिसमें अश्वघोष जैसे अनेक उत्कृष्ट बौद्ध विद्वान शामिल हुए थे। बौद्ध और शैव मतों से सूफी रिवायत तक – कश्मीर के साहित्यिक-सांस्कृतिक परिदृश्य ने भारत में रहस्यवाद तथा साहित्य की परम्परा को समृद्ध किया है।

11वीं शताब्दी के महान दार्शनिक अभिनवगुप्त का नाम कश्मीर के शैव दर्शन के साथ अभिन्न रूप से जुड़ा है। इस दर्शन में आभास-वाद (अंतर्दृष्टि) तथा प्रत्यभिज्ञा (स्मृति-जन्य ज्ञान) की धारणाओं की व्याख्या की गई है। अभिनवगुप्त ने न केवल इन धारणाओं को सैद्धान्तिक रूप दिया, बल्कि इन्हें सौन्दर्य-शास्त्र से भी जोड़ते हुए, भरत के नाट्य-शास्त्र में वर्णित आठ रसों में नवां –शांत रस भी जोड़ा। तंत्रालोक, अभिनवभारती और गीतार्थ संग्रह (भगवद्गीता पर भाष्य) उनके प्रमुख ग्रंथ हैं। उनकी रचना परमार्थसार में कश्मीर के शैव दर्शन की व्याख्या करने वाले 105 छंद हैं। बीसवीं शताब्दी में स्वामी लक्ष्मण जू ने अपने विभिन्न ग्रन्थों – जैसे शिव सूक्त, विज्ञान भैरव, द लाइट ऑफ तंत्रा इन कश्मीर शैविज़्म आदि के जरिए इन्हें संरक्षित और व्याख्यायित किया। उन्होंने इस विषय पर अनेक व्याख्यान भी दिए जिनके वीडियो उनके शिष्यों ने बनाए और प्रचारित किए हैं। उनके निधन के बाद, उनकी शिष्य प्रभा देवी कश्मीर के शैव दर्शन के ज्ञान तथा लेखन का प्रचार-प्रसार कर रही हैं। योगिनी शारिका देवी स्वामी लक्ष्मण जू की घनिष्ठ शिष्या थीं। नीरजामट्टू द्वारा संपादित पुस्तक शारिकादेवी: ए योगिनी ऑफ कश्मीर में शारिका देवी के जीवन और प्रज्ञा से सम्बन्धित लेख तथा संस्मरण संग्रहीत है।

आध्यात्मिक दीक्षा तथा अभिव्यक्ति की परम्परा में हम देखते हैं कि ज्ञानी जनों को उनके शिष्यों द्वारा प्रायः गुरु, संत अथवा स्वामी जैसे शब्दों से संबोधित करते हैं, चाहे वे पुरुष हों या स्त्री। कश्मीर में रहस्यवाद के इतिहास में हमें एक प्रख्यात पुरुष शिष्य को उनकी गुरु-माता द्वारा दीक्षित किए जाने की वाचिक परम्परा और आख्यान मिलते हैं। वह शिष्य हैं नुंद ऋषि, और उनकी मातृ-तुल्य गुरु लालदेद हैं जिन्हें कश्मीर में ऋषि (वतरेशी ओर रुशि) परम्परा

लेखिका ज़ाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज (दिल्ली विश्वविद्यालय) के अंग्रेजी विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। उन्होंने भारतीय रहस्यवाद तथा काव्य से सम्बन्धित विषयों पर अनेक पुस्तकें लिखी और संपादित की हैं। ईमेल: namrata.chaturvedi@gmail.com

Scanned with OKEN Scanner

की जननी माना जाता है। चौदहवीं शताब्दी में कश्मीर में आध्यात्मिक वातावरण उत्कर्ष पर था। उसी काल में लाल देद जैसी संत-कवियत्री ने अपने प्रसिद्ध वख (चार पंक्तियों की छंद रचनाएँ) रचे। वाचिक गाथाओं में कहा गया है कि उन्होंने एक बालक को गोद लिया, उसे स्तन-पान कराया और अपना शिष्य तथा उत्तराधिकारी बनाया। उस बालक का जन्म से नाम शेख नूरुद्दीन था और वह कश्मीर की ऋषि अथवा रेहसुत परम्परा के प्रमुख संत बने। उनके रहस्यवादी विचारों में कश्मीर के शैव मत और सूफी परम्परा के जीवन-मूल्य सन्निहित हैं। उन्होंने कश्मीरी भाषा में श्रुख कहे जाने वाले चार से छह पंक्तियों वाले छंद रचे। उन्होंने कुरान शरीफ का कश्मीरी भाषा में अनुवाद भी किया। उन्होंने कश्मीर में रहस्यवाद की ऋषि परम्परा को जनप्रिय बनाया। इस परम्परा की एक प्रमुख विशेषता बड़ी संख्या में महिला शिष्यों की उपस्थिति है जो अपने विचारों में अत्यंत स्पष्ट और मुखर हैं। उनकी माता – सौर मौज, जो जल्दी ही विधवा हो गई थीं, उनकी प्रारम्भिक शिष्यों में एक थीं। इससे हमें प्रथम बौद्ध भिक्षुणी गौतमी का प्रसंग याद आ जाता है जो भगवान तथागत बुद्ध की मौसी थीं और तथागत के जन्म के तुरंत बाद उनकी माता–महामाया की मृत्यु हो जाने के बाद उन्होंने ही तथागत को पाला-पोसा था। सौर मौज के आध्यत्मिक जीवन के बारे में अधिक विवरण उपलब्ध नहीं है। नुंद ऋषि ने अपनी पत्नी ज़ाईदेद को भी दीक्षित किया था। उनकी प्रथम प्रख्यात शिष्या शाम बीबी थी। कहते हैं कि उनकी आध्यात्मिक चेतना इतनी प्रबल थी कि वह अपनी बारात के बीच में ही निकल आई थीं और नुंद ऋषि के चरणों में गिरकर अपनी शिष्या बना लेने का अनुरोध किया था। रहस्यवादी परम्परा में बहत बाई और दहत बाई का भी उल्लेख है जो संभवतः सगी बहनें या गुरु बहनें थीं। वाचिक गाथाओं में उल्लेख है कि अपने गुरु से चर्चा और संवाद के जरिए उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। दोनों ही संवाद और चर्चा के जरिए दीक्षित किए जाने की पक्षधर थीं जिससे इस तथ्य का पता चलता है कि स्त्रियों की आध्यात्मिक चेतना का विकास स्वतः हो जाना जरूरी नहीं था बल्कि निरंतर विवेकपूर्ण संवाद से भी ज्ञान-प्राप्ति हो सकती थी। ऐसी मान्यता है कि दहत बाई ने हज़रत मीर मुहम्मद हमादानी और नुंद ऋषि के बीच शास्त्रार्थ में भाग लिया था जिसमें उन्होंने नुंद ऋषि की ओर से बढ़-चढ़ कर चर्चा की थी। स्त्री योगिनी होने की अपनी स्थिति और क्षमता के पक्ष में उन्होंने कहा था कि ईश्वर पुरुष और महिला साधकों के बीच भेद नहीं करता। एक अन्य प्रख्यात शिष्या शांग बाई थीं जो नाच-गाने और रास-रंग का जीवन छोड़ कर आत्म-ज्ञान की राह पर चली थीं। चरारे-शरीफ में अपने गुरु के मकबरे के पास ही उनकी भी कब्र है। एक अन्य शांग बाई भी थीं जिनके बारे में किंवदंती है कि बीमार और विकलांग होने के बावजूद वह तेंदुए की सवारी करती थीं और जंगलों में योगिनी का जीवन जीती थीं।

समकालीन कश्मीरी कविता में, बिमलारैना ने लालदेद के वखगायन की परम्परा को संरक्षित किया है। चन्द्र दस्सी भी वखों की रचना करते हैं जिनका गायन-प्रदर्शन किया जाता रहा है। मोहिनी कौल 'मोहना' विवाह गीतों और रहस्यवादी कविताओं की रचना कर संस्कृति के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

कश्मीर के भक्ति-गीतों और दरगाहों में महान महिला संतों और गुरुओं की परम्परा संरक्षित है। श्रीनगर के पास क्रालपुरा में बीबीबारिया की दरगाह है। वह कश्मीर में सूफी परम्परा के जनक माने जाने वाले मीर सैयद अली हमादानी की पुत्रवधू थीं। इस दरगाह में केवल स्त्रियाँ ही जा सकती हैं। श्रीनगर से 20 किलोमीटर दूर हरिपुराहरवान गाँव में मुस्तैद रहती थीं। स्थानीय वाचिक परम्परा के अनुसार, उनका कम उम्र में विवाह हो गया था और जल्दी ही उनके पति और दो भाई-बहनों की मृत्यु के दुःख ने उन्हें ईश्वरीय प्रेम और इबादत की राह पर मोड़ दिया। वह संतों की समाधियों में जाने लगीं और अपने आप को पूरी तरह ईश्वर के ध्यान और अर्चना में डुबो दिया। स्थानीय लोग उनका बहुत सम्मान करते थे और अपने रोग-तापों के निवारण और सही राह दिखाने के लिए उनकी प्रार्थना करते थे। उनकी सैयद मिराक शाह काशनी और पीर यासीन साहब जैसे सूफी संतों से आध्यात्मिक चर्चा होती रहती थी। ये संत बीबीबारिया की आध्यात्मिक पवित्रता और श्रेष्ठता के कायल थे और अक्सर उनके सान्निध्य में रहते थे। यहाँ कुछ ही महिला संतों के प्रसंग दिए गए हैं। ऐसे अनेक संतों-सूफियों के योगदान पर अभी गहन शोध होना आवश्यक है।

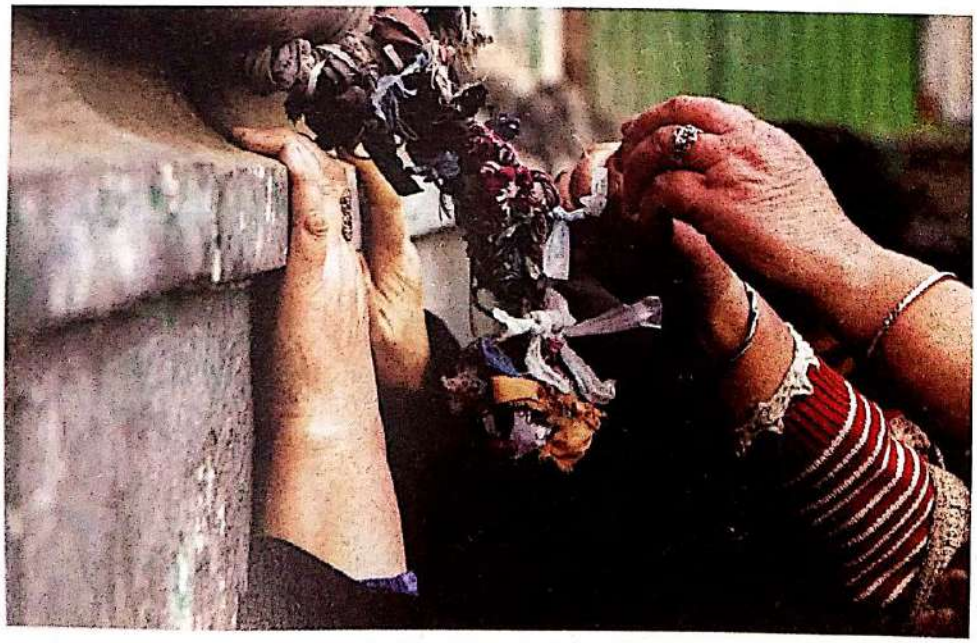

महान महिला संतों और गुरुओं की परम्परा कश्मीरी में छन्दों और दरगाहों में संरक्षित है।

समकालीन कश्मीरी कविता में, बिमलारैना ने लालदेद के वखगायन की

Scanned with OKEN Scanner

परम्परा को संरक्षित किया है। चन्द्र दस्सी भी वखों की रचना करते हैं जिनका गायन-प्रदर्शन किया जाता रहा है। मोहिनी कौल 'मोहना' विवाह गीतों और रहस्यवादी कविताओं की रचना कर संस्कृति के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। संतोष नादान के भजन और रहस्यवादी कविताएं कश्मीर में अत्यंत लोकप्रिय हैं। सुनीता रैना पंडित ने कृष्ण भगवान के भजन की रचना से कविताओं के लेखन की शुरूआत की और अब वह कश्मीरी में गजल लिखने वाली प्रमुख महिला रचनाकार हैं। इस क्षेत्र में केवल महिलाओं वाला पहला बैंड- येमबरज़ल 2015 में बना जो सूफियाना मौसिकी (संगीत) और कश्मीरी शास्त्रीय संगीत की परम्परा को आगे बढ़ा रहा है। यह बैंड लाल-देद, हब्बा खातून, गुलाम हसन ग़मगीन और शेख-उल-आलम जैसे रहस्यवादियों की कविताओं की प्रस्तुति करता है।

कश्मीर की संत कवियित्रियों के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए नीरजामट्टू ने अपनी पुस्तक द मिस्टिक एंड द लिरिक: फॉर तुमेन पोइट्स फ्रॉम कश्मीर में लालदेद, हब्बा खातून, रूपा भवानी और अर्णिमाल की कविताओं की व्याख्या की है। इस पुस्तक के बारे में एक चर्चा में प्रोफेसर शफी शौक ने इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाया कि ये चार कवियित्रियां कश्मीर में रहस्यवाद के चार कालों का प्रतिनिधित्व करती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कश्मीर की सूफी परम्परा की ऐतिहासिकता तथा महिलाओं की भूमिका पर केंद्रित शोध की बड़ी आवश्यकता है। नीरजामट्टू ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि जहां तक शब्दावली और भाषा की सरलता का प्रश्न है, लाल देद और रूपा भवानी की कविताओं में महत्वपूर्ण अंतर है। लाल देदगहनतम अपने अनुभूत सत्यों को आध्यात्मिक सत्यों को रोज़मर्रा की काव्य शैली में व्यक्त करती हैं, जबकि रूपा भवानी प्रेरणा तो लाल देद से लेती हैं लेकिन वह फारसी और संस्कृत की गूढ़ शब्दावली का प्रयोग करती हैं जिसे रहस्यवाद की धारणाओं से सुपरिचित ही समझ सकते हैं। यह महिलाओं के आध्यात्मिक लेखन को एक नया आयाम देता है और हमें महिलाओं की आध्यात्मिक चेतना के अनुभवों, अभिव्यक्तियों और प्रस्तुतियों की गहनता और विभिन्न परतों से परिचित कराता है जिसको प्राय: स्वत: स्फूर्त और बिना किसी विश्लेषण के सरल-सपाट मान लिया जाता है। अर्णिमाल और हब्बा खातून के काव्य में दु:ख का प्राधान्य है और विरह तथा उदासी एक तरह से इस भौतिक संसार के निरर्थक होने का रूपक बन जाते हैं।

हब्बा खातून के रोशे की ये पंक्तियाँ देखिए जो आज भी लोकप्रिय संस्कृति का हिस्सा बनी हुई हैं –

रोशेमदनोचोलहोमा...

वलय वासिएगसवाईह्यी-यै,
यूस मारी सुकत्युयीयाई
प्रारानतहेंजाईजूयी-है
वाले म्यानीपूसयमदनो...

वलवेसगसवाई अबस दुनिया नींदरीतेखाबस
कुसवेनीदेदी ताई बाबस
वालोम्यानीरोशेमदनो
मुझसे रूठकर, मेरा प्रिय चला गया...

आओ सखियो, हम चमेली के फूल चुनें।
मृत्यु हो जाने पर तो कोई जीवन का सुख नहीं भोग सकता।
मैं चाहती हूं, तू खूब फले-फूले।
आओ मेरे पुष्पमय कामदेव, आओ...
चलो मित्र, पानी भरने चलें।
पूरी दुनिया गहरी नींद में सोई है;
मैं तुम्हारी बाट जोह रही हूं।
ओ मेरे रूठे प्रिय, अब तो आ जाओ।
ओ मेरे रूठे प्रिय, अब तो आ जाओ।

इन सुंदर पंक्तियों में एक बहू अपनी सास की भावनाओं की गुप्त लेखिका बन गई है। वख के प्रारूप में ये पंक्तियाँ अपने गहन भावों के कारण अमर हो गई है। रिचेदेद की निम्न पंक्तियों सहित उनके साहित्य को उनकी बहू दानावती ने संरक्षित किया। ये वख भी आत्म-चिंतन की गहन अनुभूतियों और मानवीय स्थितियों के वर्णनों से सम्पन्न हैं। इन्हें बहू की मृत्यु के बाद उनके पुत्र ने प्रकाशित किया। इस लेख के अंत में, उनका एक वख प्रस्तुत कर रही हूँ जो कश्मीर के रहस्यवादी काव्य की समृद्धि और गहनता को व्यक्त करता है –

आत्म अनुभव छु दीवान दिव ज्ञान

अवय आत्म ज्ञानिक छी सारी अनुग्रगी
आत्म ज्ञान छु मुक्ति हुंद निशान
सुआस्तन योगी, भोगी, रागी या त्यागी।
आत्म-अनुभूति से ईश्वर का ज्ञान होता है।

इसीलिए बुद्धिमान जन स्वयं को
जानने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं।
आत्म-ज्ञान सभी के लिए मुक्ति का प्रतीक है –
चाहे कोई योगी हो, भोगी हो, रागी हो या त्यागी हो। ■

संदर्भ:

1. चतुर्वेदी, नमृता, लाल देद: सेंट पोइटेस, त्रिवेणी, अक्तूबर-दिसंबर, 2006, https://www.wisdomlib.org/history/compilation/triveni-journal/d/doc73548.html 5 अगस्त 2022 को लिया गया।
2. कौल, टी.एन., http://www.ikashmir.net/saints/richeded.html 8 अगस्त 2022 को लिया गया।
3. खान, नाइला अली, द पार्चमेंट ऑफ कश्मीरएहिस्ट्री, पॉलिटी, सोसाइटी, न्यूयॉर्क, पालग्रेव, 2012
4. सईद, नफीसा, 'कश्मीरी वुमेनफाइंड ए स्प्रिचुअलस्पेस ऑफ देअरऑन, 'द गार्जियन, सितंबर 2011 https://www.theguardian.com/commentisfree/belief/2011/sep/06/kashmir-srinagar-shrine 5 अगस्त 2022 को लिया गया।
5. सियारोटा, मिशेल, 'येमबर्ज़ल: दिऑलवुमेन सूफी ग्रुप इन कश्मीर', थिएटर, आर्ट, लाइफ, 3 नवंबर 2021 https://www.theatreartlife.com/music-sound/yemberzal-the-all-women-sufi-music-group-in-kashmir/ 4 अगस्त 2022 को लिया गया।
6. https://www.youtube.com/watch?v=-fm_6CEanG4 से 4 अगस्त 2022 को लिया गया।
7. https://kashmirsufis.wordpress.com/tag/female-saints-of-kashmir/ से 4 अगस्त 2022 को लिया गया।
8. https://sufinama.org/articles/women-in-rishi-movement-of-kashmir-rashid-nazki-sufinama-archive-articles से 5 अगस्त 2022 को लिया गया।

Scanned with OKEN Scanner